दृष्टिकोण

गोपाल जालान

विशाल प्रकाशन
राजगढ़, गुवाहाटी-3

DRISHTIKON

A colletion of various articless written in Hindi by
Gopal Jalan and Published by Brajendra Nath Deka
of behalf of Bishal Prakasha, Rajgarh, Guwahati-3.

First Edition : June, 2017 **Price : Rs. 170/-**

ISNB No. : 978-93-82587-507

प्रकाशक : ब्रजेंद्र नाथ डेका
विशाल प्रकाशन, राजगढ़, गुवाहाटी-3
फोन : 98640-38814
लेखक द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित
प्रथम प्रकाश : जून 2017
मूल्य : 170/- रुपए
मुख्य पृष्ठ : मृदुल नाथ
डी.टी.पी. : केदार नाथ दास
मुद्रण :
शराईघाट फोटो टाइप
बामुनीमैदाम, गुवाहाटी-21

सादर-समर्पित

पुज्यनीय पिताश्री स्वर्गीय वासुदेव जालान
और माताश्री स्वर्गीय पुष्पा देवी जालान की
पवित्र स्मृति में समर्पित।

- गोपाल जालान

लेखक के दो शब्द

किसी विद्वान ने कहा है दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपका दृष्टिकोण वस्तु को वैसा बना देता है। इंसान के जीवन में घटित एक छोटी-सी घटना जीवन प्रवाह को बदलने की ताकत रखती है। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो विपरीत बातें अथवा घटनाएं भी आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। असम-पूर्वोत्तर सहित देश-विदेश की उल्लेखनीय घटनाओं को समझने-परखने के बाद उनको लेकर मेरा जो दृष्टिकोण सामने आया, उसे इस संकलन में शामिल लेखों के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की एक विनम्र कोशिश की है। वैसे तो सारी घटनाएं लोगों को याद नहीं रहतीं, मगर कुछ घटनाएं उनके मन पर गहरा असर करती हैं। कभी-कभी तो वर्षों पुरानी घटनाएं लोगों के दिलो-दिमाग से निकलती ही नहीं हैं। अपने लेखों के माध्यम से वैसी घटनाओं पर नजर डालते वक्त मेरे मन में मेरे निजी नहीं, बल्कि पाठकों के भाव थे। लेख रचना के दौरान मैंने उस दृष्टिकोण को पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है, जिसे पढ़ उन्हें वह अपना दृष्टिकोण लगे। लेखक जब तक पाठकों के साथ बंधता नहीं है, तब तक वह न तो अपने पाठकों के दिल के अंदर झांक सकता है और न ही उनकी अनुभूति को महसूस ही कर

सकता है। लेखक में यदि संवेदनाएं हैं तो चढ़ती धूप में पत्थर तोड़ती महिला भी सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविता की नायिका बन सकती है। मैंने लेखों के माध्यम पाठक-हृदय पर जमीं वैसी ही संवेदनाओं को कुरेदने की कोशिश की है। मेरी कोशिश कितनी सफल-असफल रही, यह निर्णय आप पाठकों को करना है।

इस संग्रह में शामिल किए गए मेरे सारे लेख हिंदी दैनिक 'दैनिक पूर्वोदय' के अलावा राज्य के अन्य असमिया दैनिकों में प्रकाशित हो चुके हैं। दैनिक पूर्वोदय के प्रबंधन एवं संपादकीय विभाग के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे लेख को अखबार के नियमित स्तंभ में प्रकाशित किए गए। मैं उन सभी पाठकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे लेख पढ़ने के बाद मुझे फोन कर मेरा हौसला बढ़ाया और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। मैं विशाल प्रकाशन के प्रमुख ब्रजेंद्र नाथ डेका के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे लेख-संग्रह को पुस्तक के आकार में प्रकाशित किया।

- गोपाल जालान

भूमिका

किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका में नियमित स्तंभ लिखना आसान नहीं होता है। मैं अपने अखबार के लिए नियमित स्तंभ लिखता हूं, इसलिए इस बात को महसूस करता हूं। स्तंभ काफी पहले लिखा नहीं जा सकता। स्तंभ लिखने के लिए एक मानसिक स्थिति का होना जरूरी है। लेकिन व्यवसाय करते हुए स्तंभ लिखना तो और भी मुश्किल काम है। श्री गोपाल जालान कुछ विरले लोगों में शामिल हैं, जो दैनिक पूर्वोदय के लिए पिछले कई वर्षों से स्तंभ लिख रहे हैं, बिना किसी नागा के। मेरे संपादक बनने के बाद से मुझे स्मरण नहीं है कि उनका स्तंभ निश्चित दिन में प्रकाशित नहीं हुआ हो। वे असमिया मारवाड़ी संतान हैं, इसलिए असम की माटी के प्रति उनकी निष्ठा उनकी जीवन शैली और लेखन में दिखती है। शुद्ध हिंदी बोलने में भले ही उन्हें असुविधा होती है, लेकिन शुद्ध असमिया बोलने और लिखने में कभी असुविधा नहीं होती। वे असमिया साहित्य और कला जगत से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। भ्राम्यमान नाटक के प्रति उनका लगाव पाठशाला (असम का एक कस्बा) में पैदा होने की वजह से भी है, क्योंकि पाठशाला असम के भ्राम्यमान थिएटर का मक्का माना जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित ज्यादातर लेख दैनिक पूर्वोदय में छपने वाले उनके स्तंभ से लिए गए हैं। सामयिक घटना-परिघटना पर उनकी त्वरित टिप्पणी उल्लेनीय है। जब भी समाज में कुछ घटित होता, उनकी त्वरित टिप्पणी आ जाती है। इससे साफ है कि वे अपने आस-पास के माहौल के बारे में न केवल सजग हैं, बल्कि स्थितियों की अच्छी समझ है, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि को जाने कोई भी लेखक टिप्पणी नहीं कर सकता है। इस पुस्तक में शामिल लेखों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि श्री गोपाल जालान का नजरिया समग्र है, विस्तार लिए हुआ है। वे एक तरफ स्थानीय समाज में जारी वाद-विवादों पर कलम चलाते हैं तो देश और दुनिया के अन्य हिस्से में जो कुछ हो रहा है, उसे भी अपने तरीके से रेखांकित करते हैं। इसलिए उनके लेखों में असम के साथ पूरी दुनिया के घटनाक्रमों पर टिप्पणी दिखती है।

लेकिन तमाम लेखों पर उनकी सांस्कृतिक समझ और पकड़ का प्रभाव दिखता है, क्योंकि उनकी जड़ें असमिया संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए राजनीतिक आयोजनों में असमिया गामोछा का महत्व दिखता है तो माजुली में कैबिनेट की बैठक का दूरगामी संकेत भी। पहली बार असमिया धर्म-संस्कृति के केंद्र रहे माजुली में किसी सरकार की कैबिनेट का बैठक होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। संकेत साफ है कि सर्वानंद सरकार के कार्यकाल में असमिया संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रयास हो रहा है। इन तत्वों को बिना सांस्कृतिक सोच के रेखांकित करना संभव नहीं है।

यह पुस्तक कई मायने में पठनीय है। इसकी भाषा काफी सरल है। हर कोई उसे समझ सकता है। इस पुस्तक के लिए मैं श्री गोपाल जालान को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी समसामयिक टिप्पणी जारी रहेगी।

- रविशंकर रवि

संपादक, दैनिक पूर्वोदय

सूची पत्र

1. बेटियों की उपेक्षा क्यों 13
2. गुरु-शिष्य के रिश्तों में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन ?..... 15
3. स्वाधीनता संग्राम और वंदेमातरम् 17
4. शंकाओं में घिरी भारत-पाकिस्तान वार्ता 19
5. हर राज्य का दौरा करे पीएम 21
6. आतंकवाद पर भारत से वार्ता क्यों नहीं चाहता पाक 23
7. स्वास्थ समाज गठन की जिम्मेदारी सभी की है 25
8. मानवता को सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता 27
9. कौन समझेगा मूर्तिकारों की व्यथा 30
10. पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी है, मगर भक्ति ? 32
11. कौन लेगा अनाथ बच्चों की सुध 34
12. रूपकुंवर के सपने और हम 36
13. पत्र मित्र, एसएमएस और फेसबुक 38
14. प्रकाशोत्सव की परंपरा पर चीन का हमला 40
15. अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद 42
16. फैंसी बाजार-न्यू मार्केट के अग्निकांड का सबक 44
17. अलग से मारवाड़ी साहित्य सभा की जरूरत क्या है 46
18. भारत-नेपाल दोस्ती पर चीन की नजर 48
19. प्रदूषण के चलते रहने लायक नहीं रह गए बड़े शहर 51
20. वनभोज पर जाने वाले साफ-सफाई का भी रखें ध्यान 53
21. कितना सही है कानून को अपने हाथ में लेना 55

22. फ्रांसिसी कलाकार ने किया 'पारिजात हरण' का मंचन 58
23. पठानकोट पर हमला और भारत-पाक वार्ता 61
24. श्रीमंत शंकरदेव का योगदान अविस्मरणीय 63
25. लोक विश्वास-परंपराओं के बीच में बोहाग बिहू 65
26. वेलेंटाइन डे के नाम पर अपसंस्कृति को बढ़ावा देना कितना सही .. 67
27. कम सिहरनकारी नहीं है हमारे सैनिकों की वीरता की दास्तां 69
28. मगर दिल हार गए पाक-बांग्लादेशी खिलाड़ी 71
29. एकता में पिरोती है असम साहित्य सभा 73
30. विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों ? 75
31. होली का मतलब ही है रंगों का उत्सव, लेकिन... 77
32. गुजर गई होली, अब सफाई की बारी 79
33. मतदान करें, यह आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है 81
34. प्रतिभा विकास में कितने रीयल है रियलिटी शो 83
35. ब्रिटेन के शाही दंपति का काजीरंगा भ्रमण 85
36. रंगाली बिहू, प्रकृति का तांडव और बिहू मंच 87
37. डायन के नाम पर हत्याओं का सिलसिला कब तक 89
38. लोकतंत्र का प्रहरी होता है विपक्ष 92
39. जागरूकता से ही बंद होगा ड्रग्स का अवैध धंधा 94
40. ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देना होगा नई सरकार को 96
41. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए सरकार 99
42. मैट्रिक के नतीजे और कालेजों में दाखिले की समस्या 102
43. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में असम का गामोछा 104
44. वनांचलवासियों की मदद से रोकी जा सकती है गैंडों की हत्या .. 106
45. लोकप्रियता का असर : अंबुवासी मेले में उमड़ी भारी भीड़ 108
46. भारत के एनएसजी में शामिल होने पर चीन को आपत्ति क्यों ? 110

47. केवल जरूरतमंदों को ही जारी किए जाएं राशनकार्ड 113
48. एम्स की स्थापना को लेकर हंगामा क्यों ? 116
49. तुर्की का तख्तापलट और पाक के नापाक इरादे 118
50. कश्मीर की आजादी पर जनमत, पाक का ख्याली पुलाव 120
51. भारत को सबसे बड़ा खतरा किससे, चीन या पाकिस्तान से 122
52. निरीह लोगों की खून से होली खेलकर फायदा किसको 125
53. भारत को चाहिए पाक अधिकृत कश्मीर 127
54. बच्ची के अपहरणकांड से निकले सबक 129
55. बलूचिस्तान के समर्थन में भारत, पाक में हलचल 131
56. माजुली में कैबिनेट की बैठक, जनता की उम्मीदें 133
57. पाक में हुक्मरानों का नहीं आतंकियों का शासन 135
58. खिलौने के नाम पर बच्चों को हथियार ही क्यों ? 137
59. चीन क्यों चाहता है भारत-पाक के बीच लड़ाई हो 139
60. आतंवाद के खिलाफ भारत-रूस हुए लामबंद 141
61. असम की धरोहर है सुधाकंठ 143
62. रंगीन रोशनियों के बीच मिट्टी के दिए की तलाश 145
63. गुजर गया पूजा-पर्व का मौसम, अब साफ-सफाई की बारी 147
64. परिवर्तन की लहर : मोदी से ट्रम्प तक 149
65. नोटबंदी : जनता से संसद तक खलबली 151
66. भगवान भरोसे है वन्य-जंतुओं की सुरक्षा 153
67. कैशलेस चुनाव से भी लगेगी काला धन पर लगाम 155
68. कब तक चलेगा पाकिस्तान का झूठ 157
69. राजमार्ग के किनारे शराब बिक्री पर रोक 159
70. पुराने को अलविदा कह, नए साल का करें स्वागत 161
71. पाक में नोटबंदी, पांच हजार के नोट पर पाबंदी 163

72. संकल्प लें, देश-विदेश तक पहुंचें असमिया परंपरागत पकवान... 165
73. अच्छे पड़ोसी चाहता है भारत 167
74. बिहार की तर्ज में असम में भी हो शराबबंदी 169
75. भ्राम्यमान थिएटर के अद्वितीय व्यक्तित्व थे रतन लहकर..... 172
76. सांस्कृतिक आदान-प्रदान से बढ़ता है भाईचारा..... 174
77. दिपोरबिल के संरक्षण के लिए सरकार उठाए कदम 176
78. अब सुरंग के रास्ते आतंकवादी भेजना चाहता है पाकिस्तान 178
79. नमामी ब्रह्मपुत्र उत्सव, एक अर्थपूर्ण प्रयास..... 180
80. नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव, एक संभावना 182
81. लोक विश्वास-परंपराओं के बीच में बोहाग बिहू..... 184
82. उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के मायने 186
83. विद्यार्थियों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन 189
84. समन्वय की प्रतीक है बटद्रवा-बरपेटा की होली 191

बेटियों की उपेक्षा क्यों

कई दिन पहले कामरूप जिले के छयगांव की एक हृदय विदारक घटना अखबारों की सुर्खियां बनी थी। एक गरीब परिवार के तीन बच्चे अपनी मां कल्पना दास के शव को दो बांस के सहारे लटकाकर उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। उस अभागिन की अंतिम यात्रा में चौथे व्यक्ति के रूप में छयगांव के माकेली में रहने वाला उसका पति बाबुल दास भी अपने बच्चों के साथ था। आज के इस दौर में एक महिला के शव को पशुओं की तरह दो बांस के सहारे बांधकर ले जाना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। लंबी बीमारी के बाद कल्पना का निधन हो गया था। इस घटना ने एक बार फिर हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

लगता है कि भोग-विलास में डूबे समाज में अब दयालु लोगों की संख्या नहीं के बराबर रह गई है। समाज में भले ही बेहतर कपड़े पहनने वालों और कीमती गाड़ियों में घूमने वालों की संख्या में इजाफा हुआ हो, मगर संकट की घड़ी में किसी गरीब की मदद करने वाले लोगों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। कल्पना के निधन के बाद भी समाज का ऐसा ही पत्थर दिल चरित्र उभरकर सामने आया। मां की मौत के बाद उसके बच्चों ने अपने पड़ोसियों के घर-घर जाकर अपनी मां के निधन का दुखद समाचार दिया था, मगर एक भी पड़ोसी उनकी मदद अथवा कल्पना के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकलकर नहीं आया। कल्पना के दस वर्षीय बेटे हृदय ने यह भी कहा कि उसका घर मालिक तक अपने घर से निकलकर बाहर नहीं आया। मृतक परिवार के चारों सदस्य शव का अंतिम संस्कार करने में मदद करने

के लिए लोगों केसामने गिड़गिड़ाते रहे, मगर एक भी बंदा मदद के लिए आगे नहीं आया। कहते हैं कोई किसी से कितना भी नाराज क्यों न रहे, मौत के बाद सारे गिले-शिकवों को भुला दिया जाता है। मौत एक अंतिम सत्य है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए कोई चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, उसकी मौत हो जाने पर सारी दुश्मनी उसके साथ खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक गरीब परिवार की महिला के अंतिम संस्कार के लिए एक भी व्यक्ति का आगे नहीं आना समाज की निष्ठुरता और गिरते सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है।

कैसा करुण दृष्य था, पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, मां के शव से लिपटकर बच्चे रो रहे थे और बाबुल दास केसामने सिवाय इस करुण मंजर को देखते रहने केअन्य कोई चारा नहीं था। यह मंजर इस बात की गवाही देता है कि आज के दौर में मानवता जैसा शब्द महत्वहीन हो गया है। इस यांत्रिक दुनिया में किसी के पास भी दूसरे के लिए घड़ी भर तक का वक्त नहीं रह गया है। हम भले कितना ही चीखे-चिल्लाएं कि हम सभ्यता के ऊंच शिखर तक पहुंच गए हैं, मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि हम मानवता के सबसे निचले पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं। यह घटना इस बात को भी स्थापित करती है कि अच्छे कपड़े पहनने, महल-मकानों में रहने और कीमती गाड़ियों में घूमने से ही कोई सही मायने में इंसान नहीं हो जाता। आधुनिक समाज में लगभग हर कोई पढ़ा-लिखा है, धनवान लोगों की भी कमी नहीं है हमारे समाज में, मगर पवित्र हृदय वाले लोगों से हमारा समाज खाली होता जा रहा है। दूसरे के गम में गमजदा होने का किसी के पास भी वक्त नहीं है। कवि चंद्र कुमार अग्रवाला ने अपनी एक कविता में लिखा था 'दूसरों केलिए रोना जानने से रोने में भी सुख है।' इस पंक्ति के मर्म को समझने वाले लोग भी समाज में नहीं के बराबर रह गए हैं। प्रतियोगिता के इस दौर में 'मानवता' एक बेमतलब का शब्द भर बनकर रह गया है। चारों ओर सिर्फ पैसे जुटाने-जमाने की रेलम-पेलम लगी हुई है, ऐसे में किसे फुर्सत है मानवता के बारे में सोचने की, किसे समय है किसी के अंतिम संस्कार के लिए बढ़कर आगे आने की। 1

गुरु-शिष्य के रिश्तों में गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन

गुरु-शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र कहलाता है। हमारे देश में प्राचीन काल में गुरुकुल आश्रम व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के तहत गुरु-शिष्य के संबंधों को भगवान से भी ऊंचा माना गया है। आप सभी को वह दोहा तो याद ही होगा 'गुरु गोविन्द दोउ खड़े, काकेलागूं पायं। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दियो दिखाय।' वैसे भी स्कूल अथवा गुरुकुल को बच्चे का दूसरा घर कहा जाता है। घर में माता-पिता भले ही प्यार-दुलार के साथ अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, मगर उम्र होने पर हर एक बच्चे को स्कूल जाना ही पड़ता है। स्कूल में बच्चे की सारी जिम्मेदारी शिक्षक पर ही होती है। शिक्षक बच्चे को जो शिक्षा देते हैं, बच्चा वही ग्रहण करता है। कहा जाए तो जिंदगी की शुरुआत ही स्कूल से होती है। विद्यालय के माध्यम से ही एक बच्चा बाहरी दुनिया को जानता-समझता है। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी का पहला सबक पढ़ाने वाले शिक्षक ही होते हैं। एक शिक्षक द्वारा लाड़-प्यार से पढ़ाई-सिखाई गई बातें बात में जाकर ऐसी अनमोल संपदा बन जाती हैं, जिसके दम पर एक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग तय करता है।

आज के दौर में यह सवाल उठने लगता है कि क्या गुरु-शिष्य अथवा शिक्षक-विद्यार्थी केबीच के संबंध पहले की तरह पवित्र रह गए हैं। आज के दौर में अधिकांश विद्यार्थियों को अपने शिक्षक के प्रति सम्मान अथवा श्रद्धा का भाव देखने को नहीं मिलता। आज का विद्यार्थी अपने शिक्षक के सामने अच्छा-बुरा कोई भी काम करने में संकोच महसूस नहीं करता। शिक्षकों को प्रणाम अथवा नमस्ते कहने की परंपरा तो रही ही नहीं। पहले के जमाने में शिक्षक को देखने पर विद्यार्थी प्रणाम-नमस्ते ही नहीं करते थे, बल्कि उनके बैठने केलिए अपनी सीट तक छोड़ देते थे। बैठे रहने पर शिक्षक को देखते ही खड़े होकर उनका

सम्मान करते थे। साइकिल चलाते वक्त सामने शिक्षक को आते देख अपनी साइकिल की सीट से नीचे उतरना तो मुझे कल की-सी बात लगती है। आज स्थिति बिल्कुल उलट नजर आती है, सामने शिक्षक को आते देख विद्यार्थियों के चेहरे पर 'कौन शिक्षक-किसका शिक्षक' जैसे भाव तैरते नजर आते हैं। सड़क के किनारे सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते विद्यार्थियों की टोलियों को देख शिक्षक को या तो सर झुकाकर वहां से निकलना पड़ता है अथवा रास्ता तक बदलना पड़ता है। बहुत से शिक्षकों को तो अपने विद्यार्थियों के सामने से गुजरने में ही शर्म महसूस होती है। मैं नहीं कहता हमारे समाज के सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं, जिनमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान-आदर की भावना है, मगर इससे हम गुरु-शिष्य के रिश्ते में आ रहे बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुरु-शिष्यों के रिश्तों में आई इस खटास के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी तह में जाना ही होगा।

गुरु-शिष्य के रिश्तों में आई गिरावट को आजकल अखबारों में छपी खबरों से ही जाना-समझा जा सकता है। गुरु-शिष्यों केगिरते संबंधों को लेकर अखबारों में जिस तरह की खबरें छपती हैं, उनका जिक्र तक करने में मुझे शर्म आती है। गुरु-शिष्य के संबंधों में अब पहले जैसी पवित्रता नहीं रह गई है। गुरु-शिष्य के संबंधों में आई गिरावट के लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं। इसका जवाब तभी सामने आ सकता है, जब हम स्वयं से यह सवाल करें। यदि हम कहें आधुनिकता की वजह से इन रिश्तों में गिरावट आई है तो हमें उन बिंदुओं को तो तलाशना ही होगा, जो इसकी मुख्य वजह हो सकती हैं। यदि कोई कहे जेनरेशन गैप की वजह से गुरु-शिष्य केरिश्तों में गिरावट आ रही है तो यह जिम्मेदारी बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों के सर जाती है। अब पहले जैसी शिक्षा नहीं रह गई है, पहले कठोर अनुशासन के बीच शिक्षादान हुआ करता था। पढ़ाई न करने पर स्कूलों में विद्यार्थियों की पिटाई अथवा उससे भी कड़ी सजा आम बात थी। मगर अब ऐसा नहीं है, विद्यार्थी को चपत तक लगाने का शिक्षक को हक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है, कब सुधरेगें गुरु-शिष्य केरिश्ते। ।

स्वाधीनता संग्राम और वंदेमातरम्

भारतीय स्वाधीनता संग्राम को लेकर चर्चाओं का अंत नहीं है, जितनी भी की जाए कम है। मातृभूमि को सफेद चमड़ी वाले गोरों के शासन से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चला था, उसका हर क्षण स्मरणीय था। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हर बात, हर एक घटना बाद में सुनहरे इतिहास में बदल गई। स्वाधीनता संग्राम के इस सुनहरे इतिहास के पन्नों में तीन गीतों का राष्ट्रीय गौरव भी दर्ज है। 15 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को पूरे देश भर में 'जन-मन-गण अधिनायक' गीत भले ही गाया-बजाया जाता हो, मगर स्वाधीनता संग्राम के समय सबसे अधिक गाया-सुना जाने वाला गीत 'वंदेमातरम्' ही था। यह भी कहा जा सकता है 'वंदेमातरम्' स्वाधीनता संग्राम का मूलमंत्र था।

हम यदि इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानियों का विश्लेषण करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देवी दुर्गा का वंदना गीत होने के बावजूद 'वंदेमातरम्' स्वाधीनता संग्राम का ऊर्जा-गीत था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत और बांग्ला भाषा में इस गीत की रचना की थी। बंकिम बाबू द्वारा रचित यह गीत बाद में न सिर्फ देश भर में, बल्कि विदेशों में भी खासा चर्चित रहा। बंकिम बाबू ने विद्रोह की पृष्ठभूमि में 'आनंदमठ' नामक एक उपन्यास लिखा था।

'वंदेमातरम्' को यदि उक्त उपन्यास का अंश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धूर्त अंग्रेजों ने बहुत बार ऐसे गीतों के खिलाफ कुप्रचार चलाने के साथ ही दमनमूलक कार्रवाई करने की धौंस दी थी, मगर बाद में देश के बच्चे-बच्चे को अंग्रेजों की यह कुटिलता समझ में आ गई थी। अंग्रेजों ने तो 'गॉड सेव क्वीन' की सोच को भी भारत के राष्ट्रीय संगीत के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर भारतीयों ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि यह गीत भारतीय संस्कृति के विपरीत था। अंग्रेजों की ऐसी सोच किसी भारतीय को प्रभावित न कर सके, संभवत: इसी बात को ध्यान में रखते हुए बंकिम बाबू ने 'वंदेमातरम्' गीत की रचना की थी। बंकिम चट्टोपाध्याय ने चाहे जो कुछ भी सोचकर यह गीत लिखा होगा, मगर बाद में यह गीत देश के हर एक नागरिक के दिल-दिमाग और जुबान पर चढ़ गया था। इस गीत को प्रतिबंधित करने में ब्रिटिश शासन ने जितनी जोर आजमाइश की, यह गीत लोगों की जुबान पर उतना ही चढ़ता-निखरता गया। गीत की लोकप्रियता का आलम यह था कि फांसी के फंदे पर लटकने से पहले तक स्वाधीनता संग्राम के वीर सिपाही 'वंदेमातरम्' को भावविभोर होकर गाया करते थे। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक पत्रिका प्रकाशित की थी, जिसका नाम भी उन्होंने 'वंदेमातरम्' ही रखा था। 1896 के दिसंबर में कोलकाता के विडन स्क्वायर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में कवि गुरु रबींद्र नाथ ने यह गीत गाया था। इसके पांच साल बाद कोलकाता में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य एक अधिवेशन में दक्षिणाचरण सेन ने भी यही गीत गाया था। बाद में भारतीय संविधान हस्ताक्षर के लिए 26 जनवरी, 1950 को आयोजित अधिवेशन में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 'वंदेमातरम्' के महत्व को विस्तार से रेखांकित करते हुए कहा था कि 'जन-गण-मन' को भारत के राष्ट्रगान की संज्ञा दिए जाने के बावजूद 'वंदेमातरम्' को राष्ट्रीय संगीत का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी। आज भी बंकिम बाबू का यह गीत हर एक भारतीय के दिल के साथ धड़कता है। 14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को आयोजित भारतीय गण परिषद का अधिवेशन भी 'वंदेमातरम्' के साथ शुरू हुआ था। [1]

शंकाओं में घिरी भारत-पाकिस्तान वार्ता

भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर होने वाली वार्ता हमेशा ही शंकाओं में घिरी रहती है। 1947 में देश विभाजन के समय दोनों राष्ट्रों की जनता में सफेद चमड़ी वाले अंग्रेज घृणा के जो बीज बो गए थे, उसकी फसल आज भी लहरा रही है। मौखिक रूप से भले ही दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार होने का दावा करें, मगर हकीकत में स्थिति इससे बिल्कुल उलट दिखती है। भारत पर पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष हमले इस बात के प्रमाण हैं। भारत पाकिस्तान के उग्रवादी कार्यकलापों की जितना विरोध करता है, पाकिस्तान अपनी ओर से उग्रवादी, हत्या-हिंसात्मक गतिविधियों को उतनी ही तेज कर देता है। हाल ही में पंजाब और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर की गई उग्रवादी वारदातों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान कभी भी सौहार्द्रपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के लिए इच्छुक नहीं रहा है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में विगत 5 अगस्त को हुए उग्रवादी हमले के प्रमुख कट्टर आतंकवादी मोहम्मद नावेद की गिरफ्तारी के बाद से ही ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच के संबंध

और अधिक खराब होने जा रहे हैं। विभिन्न लोगों की मदद से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों में 45 दिनों तक छिपे रहने वाले पाकिस्तानी उग्रवादी गुट के सदस्य नावेद को भले ही मोहम्मद याकूब नामक व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक बताता हो, मगर इस्लामाबाद इस बात से इनकार करता है। पाकिस्तान सरकार द्वारा नावेद को उसके देश का नागरिक नहीं मानना स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को उग्रवाद का केंद्र के रूप में चिन्हित किए जाने के बावजूद पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता आया है। विश्व वासियों की आंखों में धूल झोंक कर विश्व भर में आतंक का पर्याय बने ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान ने ही अपने यहां शरण दे रखी थी। अमरीकी सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार गिराने वाली घटना ने पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने बेनकाब कर दिया था। इसके बाद भी पाकिस्तान के चेहरे पर शर्म की एक लकीर तक नजर नहीं आती।

मुंबई के हमले में शामिल कसाब को भी इस्लामाबाद ने पहले पहल पाकिस्तानी नागरिक मानने से इनकार किया था, मगर बाद में कसाब की नागरिकता से जुड़ी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत में हुई हर आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों के पाकिस्तानी नागरिक होने की बात से इनकार कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। सिर्फ यही नहीं, कारगिल की लड़ाई के समय भी पाकिस्तान ने पहले भारत पर हमला करने की बात से इनकार किया था। इसके अलावा कारगिल की लड़ाई में कई आतंकवादी संगठनों के भी पाकिस्तानी सेना की मदद करने की बात भी समाचार पत्रों में आई थी। अंतत: कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी को करारी हार मिली। पाकिस्तान ने आज तक भारत के साथ जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, सभी में पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा ही भारत से अपनी पराजय का बदला चुकाने की नापाक कोशिशों में रहता है। पाकिस्तान भारत से बदला लेने की आग में जल रहा है और इसीलिए भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान परोक्ष रूप से आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करता रहा है। 1

हर राज्य का दौरा करे पीएम

नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको लेकर देश के सभी नागरिकों ने राष्ट्र की बेहतरी के सपने देखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी को यह विश्वास था कि श्री मोदी की जो नीतियां हैं, उससे देश का भविष्य सुरक्षित है। विश्व के ताकतवर देशों की कतार में भारत को ला खड़ा करने के लिए जो करना है, प्रधानमंत्री वह सारे कदम उठाएंगे। देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। प्रधानमंत्री स्वयं यह बात कह चुके हैं कि 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'। मगर मोदी के देश की बागडोर संभाले एक साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी यह सारी बातें धरातल पर नजर नहीं आतीं।

प्रधानमंत्री ने हर एक राज्य के समान विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, फिर भी देश के विभिन्न राज्यों के निवासियों के दिल से शंकाएं दूर नहीं हुई हैं। हर एक राज्य में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ों को इतनी गहराई में जमा रखा है कि लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि भ्रष्टाचार को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार की बीमारी से ईमानदार, गरीब सभी त्रस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए जाने की बात कहते आए हैं, मगर अभी तक इस पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हो पाया है। सभी मामलों में देश को संभाल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री यदि एक-एक राज्य में सिर्फ दो घंटे के लिए ही हो, महीने में एक बार जाकर वहां के काम-काज की जानकारी लें और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनें तो भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है। प्रधानमंत्री की इस तरह की सक्रियता से भ्रष्ट नेता-अधिकारी, व्यापारी-ठेकेदार तथा ऐसे अन्य सभी

भ्रष्टाचार में लिप्त होने से घबड़ाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया इस तरह का कदम देश के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस प्रकार के कठोर कदम उठाने ही होंगे। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों, मंत्री से लेकर संतरी तक को भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा।

यह बात सर्व मान्य है कि जो व्यक्ति स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो, वहीं दूसरे व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहने की नसीहत दे सकता है। यह अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर अभी तक भ्रष्टाचार का एक छींटा भी नहीं लग पाया है। प्रधानमंत्री जिस विकास मॉडल की बात कहते हैं, उस पर चलकर यदि सभी राज्यों का विकास हो, तभी जाकर पूरे देश का विकास होगा और भारत को एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में विश्व वासियों के सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा। श्री मोदी यदि हर महीने, किसी एक राज्य के दौरे का कार्यक्रम बनाते हैं तो उनके इस कार्यक्रम से हर एक राज्य थोड़ा ही सही प्रगति कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वे सभी से अपनापन हासिल कर लेते हैं। गुजरात जैसे राज्य के सफल मुख्यमंत्री कहलाने के बाद प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले वे देश के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देशवासियों के दिलों में उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा, विश्वास, प्रेम-स्नेह की भावना है, श्री मोदी उसे बनाए रखने के लिए कम कोशिशें नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो श्री मोदी को संकट में डालने के मौके की तलाश में लगे हैं। ऐसे लोगों की सूची में सिर्फ शीर्ष अधिकारी ही नहीं, कई राज्यों की सरकारें भी शामिल हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे हर एक राज्य के विकास, समस्या व जरूरतों का स्वयं आकलन करें और इसके लिए महीने में किसी एक राज्य का दो घंटे का संक्षिप्त दौरा भी करना पड़े तो उन्हें इस पर गंभीरता से विचार तो करना ही चाहिए। मात्र 2 घंटे के लिए किसी एक राज्य के दौरे से प्रधानमंत्री देश के विकास की गति को और अधिक तेज कर सकते हैं। मेरा तो कम-से-कम ऐसा ही सोचना है। ।

आतंकवाद पर भारत से वार्ता क्यों नहीं चाहता पाक

जब भी भारत के साथ पाकिस्तानी सरकार किसी एक मसले पर वार्ता करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पाकिस्तानी सेना इस प्रक्रिया में रोड़े अटकाने लगती है। पाकिस्तानी सेना की इस बदनीयती पर अब किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रह गया है। हाल ही में दिल्ली में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की वार्ता को पाकिस्तान द्वारा रद्द कर दिए जाने की घटना ने एक बार फिर पाक के नापाक इरादों को बेपर्दा कर दिया है। मालूम हो कि विगत 23 और 24 अगस्त को दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत होनी थी, मगर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अहमद द्वारा खेले गए दांव-पेच के खेल में यह वार्ता भी सियासत की भेंट चढ़ गई। दोनों देशों के बीच होने वाली उक्त बैठक से पूर्व पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ वार्ता करने के निर्णय ने पाक की दोहरी नीति का खुलासा कर दिया। अजीज के भारत भ्रमण के दौरान कश्मीर के अलगाववादी नेता अलिशा गिलानी, मीरवाईज उमर फारुख, नजीम खान और यासीन मल्लिक सहित हुर्रियत नेतृत्व के साथ बैठक करने का न्योता दिए जाने के बाद भारत को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। भारत के पाकिस्तान को यह संदेश

दिए जाने के बाद कि वह पाक के उक्त कदम का कतई समर्थन नहीं करता, इस वार्ता को रद्द कर दिया गया। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा आमंत्रण भेजे जाने के बाद ही दरअसल इस वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 'हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान को भारत की सहमति की जरूरत नहीं है। हुर्रियत के साथ पाकिस्तान की बातचीत सदैव जारी रहेगी। पाकिस्तान भारत के कहे पर चलने वाला नहीं है। भारत-पाकिस्तान के बीच शर्तों पर आधारित कूटनीति स्तर की बातचीत नहीं हो सकती।'

पाकिस्तान यह भी आरोप लगाता रहा है कि भारत हमेशा बातचीत से पीछे हट जाता है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अजीज यदि अलगाववादी नेताओं से बातचीत करते हैं तो भारत किसी भी कीमत पर यह शर्त मानने को तैयार नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि रूस के उफा में भारत-पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के दमन के लिए जिस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसी के आधार पर दोनों देशों के बीच बातचीत संभव है। पाकिस्तान हमेशा से ही जब भी आतंकवाद दमन के प्रसंग को लेकर बातचीत का माहौल बनता है, आतंकवादी अथवा अलगाववादी संगठनों की मदद से ऐसी वार्ताओं को नाकाम करता आया है। उल्लेखनीय है कि 2014 के अगस्त में भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त के कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बैठक में आमंत्रित किए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान से वार्ता में बैठने पर इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की दोहरी नीति और हठधर्मिता के कारण एक साल में दो-दो बैठकें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गईं।

पाकिस्तान किसी भी तरह कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालकर पाकिस्तान को आज तक कोई मनचाहा नतीजा हासिल नहीं हुआ। लड़ाई करके भी वह भारत से नहीं जीत सकता। लिहाजा पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादियों को भेजकर भारत को अस्थिर करना चाहता है। 1

स्वास्थ समाज गठन की जिम्मेदारी सभी की है

मानव जीवन का हर एक पहलू समाज व्यवस्था पर ही टिका है। समाज के साथ मानव का जुड़ाव बहुत गहरा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बिना समाज के जिंदा नहीं रह सकता। इतिहास के पन्नों को यदि पलटकर देखा जाए तो पहले मनुष्य समाज बनाकर निवास नहीं किया करता था, इसीलिए उसका जीवन अनुशासित भी नहीं था। अग्नि के इस्तेमाल के ज्ञान ने मनुष्य को नई गति प्रदान की। क्रमश: विकास के साथ-साथ मनुष्य की बुद्धि का भी विकास हुआ और इस बात की जरूरत भी महसूस की गई कि समाज का गठन कर सहवास किया जाना चाहिए। यह सही है कि आज हम जिस उन्नत समाज में रह रहे हैं, अतीत में वैसे एक समाज अथवा समाज व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी मनुष्य के मन में जब से समाज की अवधारणा बनी, तब से ही सभी में परस्पर के प्रति जिम्मेदारी की भावना का भी संचार हुआ। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मनुष्य और अधिक जागरूक रहने लगा। समाज के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी अथवा कर्तव्य है, इसका ज्ञान होने के कारण ही हम आज इस समाज में निवास कर पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति ही समाज का अंग है। समाज के अन्य दस लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, बाकी सभी लोगों के लिए उसका अनुकरण करना अनिवार्य है। फिर भी हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, जो अपने कदम विपरीत दिशा में बढ़ाने का भी हौसला रखते हैं।

एक स्वस्थ्य और मजबूत समाज के गठन होने के मूल में उन लोगों का दृष्टिकोण छिपा होता है, जो लोग उस समाज में निवास करते हैं। यह सही है कि हर एक व्यक्ति की अलग-अलग सोच, नजरिया होता है, मगर सामूहिक

हितों को देखते हुए कभी-कभी अपने नजरिए को बदलना अथवा छोड़ना पड़ता है। यह बात एक हद तक समाज की परिस्थिति और माहौल पर भी निर्भर करती है। कुछ लोग दिन-रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि समाज बदलाव की आंधी की चपेट में आने से बचते हुए अपने मानवीय मूल्यबोध पर टिका रहे। इसकी कोशिश होती है समाज को मजबूती से थामकर रखते हुए सभी को एक शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना। समाज के सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है तो यही लोग उसके समाधान के लिए आगे आते हैं और इस प्रयास में रहते हैं कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को बनाए रखते हुए कैसे समाज को आगे ले जाया जाए। यह भी सच है कि सामाजिक कार्य करने के दौरान कुछ लोगों में मतभेद-मनमुटाव भी होता है, वैसे में दोनों ही पक्ष उस विवाद को ताक पर रख आपसी संबंधों के बीच आई दरार को पाटने की कोशिश करते हैं। जब भी यह दरार कम होती है, तभी समाज में शांति स्थापित होती है और इसके उलट जब दरारें बढ़ती हैं तो समाज में अशांति भी फैलती है।

वैसे यह बात भी सही है कि किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई वजह होती है। बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। हमें उन कारणों का विश्लेषण करना चाहिए, जिस वजह से समाज में अप्रिय घटनाएं होती हैं। वैसी घटनाओं पर यदि प्रारंभ में ही रोक नहीं लगाई गई तो खतरे की घंटी का बजना तय है। आमतौर पर हम सभी पहले पहल कुछ मामलों को गंभीरता से नहीं लेते। यही बात बाद में तिल का ताड़ बन जाती है। यदि कौरवों ने पांडवों से सुई की नोंक बराबर भूमि न देने की बात नहीं कही होती तो कुरूक्षेत्र की लड़ाई में इतने वीर योद्धाओं की मौत नहीं हुई होती। अंग्रेजों ने पहले ही यदि भारतीयों को स्वाधीनता दे दी होती तो हजारों भारतीय लोगों के नाम शहीदों की सूची में दर्ज नहीं हुए होते। इसी तरह हमारे समाज को भविष्य में भी स्वस्थ्य रखना है तो हमें आगे जाकर पैदा होने वाली समस्याओं के कारणों का अभी से विश्लेषण करना होगा। एक स्वस्थ समाज के गठन की जिम्मेदारी हम सभी की है और यह जिम्मेदारी हम सभी को मिलकर उठानी होगी। 1

मानवता को सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता

एक बार फिर घुसपैठ और शरणार्थी समस्या चर्चाओं में है। वैसे भी ऐसी समस्याएं बहुत पहले से ही पैदा होती रही हैं। मगर हाल ही में सीरिया से विश्व के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ करने वाले शरणार्थियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी देश अपनी सीमाओं पर चाहे कितनी भी कंटीली तार की बाड़ लगा ले, अपनी सीमाओं को कितना भी बंद कर ले, जब मानवीयता का सवाल उठ खड़ा होता है तब कंटीलें तार की बाड़ अथवा सीमा-सुरक्षा के अन्य सारे सवाल गौण हो जाते हैं। गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया से हजारों नागरिकों ने अब यूरोप के विभिन्न देशों से उन्हें शरण दिए जाने की अपील की है। इन शरणार्थियों की स्थिति कितनी भयावह है, आईलन कुर्डी नामक एक तीन साल के बच्चे की मौत ने सभी के सामने उजागर कर दिया है। सीरिया छोड़ अपने परिवार सहित सागर के रास्ते ग्रीक द्वीपपूंज के कोसा जाते वक्त बोट के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इस तीन साल के बच्चे की समुद्र में डूब जाने से मौत हो गई थी। वह मंजर तो सबसे दर्दनाक था, जब समुद्र की लहरों ने तीन साल के आईलन के शव को किनारे पर ला पटका था। इस दर्दनाक तस्वीर को पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। गृह युद्ध की आग में जल रहे सीरिया के नागरिकों ने अपनी जान बचाने के लिए हाल ही में विभिन्न देशों से उन्हें शरण दिए जाने के लिए आवेदन किया। सिर्फ जर्मनी में ही 95 हजार से अधिक शरणार्थियों ने शरण मांगते हुए आवेदन पत्र दिए हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सूडान, फ्रांस, इटली आदि देशों में भी शरणार्थियों ने शरण मांगते हुए आवेदन किया है।

इन दिनों कट्टरवादी संगठन पूरे विश्व के लिए ही एक चुनौती बने हुए हैं। इराक, सीरिया, नैरोबी, यमन, लेबनान आदि देशों में कट्टरवादियों का तांडव

चरम सीमा पर है। इन देशों के नागरिकों को अपना हर पल आतंक के साए तले गुजराना पड़ रहा है। इनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान सबसे अधिक जरूरी हो गया है। इनका भविष्य अंधकारमय है और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में वे अपने बच्चों का भरण-पोषण किस तरह करें, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरा है। इसीलिए अपनी जान को दांव पर लगाकर जिंदगी बचाने केलिए हजारों शरणार्थी विभिन्न देशों की सीमाओं पर इस इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें उक्त देश में किसी भी तरह से शरण मिल जाए। इतने दिन इन शरणार्थियों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करने वाले ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सूडान, फ्रांस, इटली आदि देश भी अब अपने रुख में नरमी दिखाने को मजबूर हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, नैरोबी आदि देशों में शरणार्थी घुस चुके हैं। जर्मनी के वियेना, म्यूनिख आदि शहरों में तो शरणार्थियों को शरण भी दी जा चुकी है। ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों में हजारों शरणार्थियों को शरण दी गई है। एक तीन साल के शरणार्थी बच्चे की समुद्र में डूब कर मौत हो जाने की घटना ने एक बार फिर विश्व वासियों को शरणार्थी के मुद्दे पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया।

एक देश से दूसरे देश में विभिन्न कारणों से घुसपैठ होती है। विशेषकर गृह युद्ध, युद्ध, खाद्य संकट, बेरोजगारी और निवास की कमी केअलावा जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में घुसपैठ होना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हाल केदिनों में जो घुसपैठ हो रही है, उसकी वजह कट्टरवाद और आतंकवाद है। कट्टरवादी संगठन यदि किसी धर्म विशेष के नाम पर आतंक फैलाते हैं तो इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर पूरे विश्व को डराकर रखना चाहते हैं। यह लोग हत्या, बलात्कार, फांसी आदि के माध्यम से लोगों को आतंकित किए रखते हैं और जबरन धर्मांतरण करने से भी बाज नहीं आते। मौका मिलते ही यह लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हमला करते हैं और इनके दिल में मानवता नाम की कोई चीज नहीं होती। यह लोग सिर्फ लोगों में अपना आतंक फैलाकर अपने प्रभाव का विस्तार करना ही जानते हैं।

इतने दिन यूरोपियन देशों में ईसाई और मुसलमानों में विभिन्न कारणों से विरोध चलता आ रहा था। दोनों ही धर्म के लोग जब दुनिया में अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, वैसे में ईसाई देशों में शरण लेने वालों में अधिकांश मुसलमान ही हैं। इससे यह बात भी साबित होता है कि मानवता को हमेशा ही धर्म से ऊंचा स्थान दिया जाता है। मानवता को सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। संकट की घड़ी में जैसे सभी कोई एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं, वैसे ही आतंकवाद-कट्टरवाद का भी हम सभी को एकजुट होकर ही मुकाबला करना होगा। l

कौन समझेगा मूर्तिकारों की व्यथा

शारदीय उत्सव के आगमन के साथ-साथ मूर्तिकार भी व्यस्त हो उठते हैं। दिन-रात प्रतिमा-निर्माण में लगे इन मूर्तिकारों को अन्य किसी बात का ख्याल भी नहीं रहता, क्योंकि इन्हीं मूर्तिकारों के स्पर्श से यदि प्रतिमाएं जीवंत न लगें तो उत्सव भी अधूरा-सा लगता है। कला के ये जादूगर कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास कर एक मिट्‌टी के टुकड़े में प्राण फूंकने जैसा काम करते हैं। देवी-देवता भी इनके हाथों का स्पर्श पाकर जीवंत हो उठते हैं। एक टुकड़ा मिट्‌टी में प्राण डालना कितना कठित और साधना का काम है, यह बात सिवाय एक मूर्तिकार के दूसरा कोई नहीं समझ सकता। एक कलाकार का मन ही कलाकार की सत्ता को समझ सकता है। साधना, एकाग्रता और जीवन का सभी कुछ देवी-देवताओं के चरणों में अर्पित कर शिल्प कला में लगे मूर्तिकार कभी भी आत्मप्रचार के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। वे सृजन तथा शिल्प कला में ही जिंदा रहना चाहते हैं। मूर्तिकारों को प्रचार से अधिक सृष्टि का आधार खोजने में आनंद की अनुभूति होती है। मूर्तिकार इसी दायरे में ही कैद होकर रह गए हैं। प्रचार से कोसों दूर इन मूर्तिकारों के बारे में कौन कितना-कैसा सोचता है, इस बारे में विचार तक करने का वक्त नहीं होता इन मूर्तिकारों के पास। सृजन कला में व्यस्त मूर्तिकार जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बाद भी 'कुछ

नहीं मिलने' पर अफसोस नहीं करते। समाज में अपना अमूल्य योगदान देने के बाद भी ये मूर्तिकार समाज से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। ऐसे कलाकारों के लिए हिसाब-किताब रखना-करना एक मूल्यहीन विषय है। और तो और, अपने बच्चों को अच्छा नहीं खिला-पहना पाने अथवा बेहतर शिक्षा न दिला पाना भी इन कलाकारों के दिलों में अशांति के समुद्र को जागृत नहीं कर पाते। भगवान इनको जिस तरह से रखते हैं, ये कलाकार उसी तरह से जिंदा रहने में खुश रहते हैं। हकीकत में यदि देखा जाए तो इन कलाकारों का जीवन करुणा से भरा होता है। कदम-कदम पर संकट की पदचाप सुनने के बाद भी ये कलाकार उन पदचापों को अनसुना कर आगे निकल जाते हैं। गंभीर बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद इनको किसी के सामने हाथ फैलाना गंवारा नहीं है। स्वाभाविक जीवन-यात्रा के दौरान इन मूर्तिकारों को जिन संकट-कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं से उनकी सृजन कला परवान चढ़ती है। कला का जन्म होता है।

इन कलाकारों को आमतौर पर कुछ कारीगर कहना पसंद करते हैं। वैसे भी कारीगर खराब शब्द नहीं है। मगर इस शब्द से एक तरह की संकीर्णता का बोध होता है। दुर्गा पूजा के समय ये कलाकार जिस प्रकार की मुंह बोलती मूर्तियों का निर्माण करते हैं, वह सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर उभरता है। इसके बाद भी मूर्तिकार को कोई विशेष सम्मान अथवा पुरस्कार नहीं दिया जाता। उन्हें प्रतिमा के निर्माण के एवज में उनके परिश्रम के अनुसार ही पारिश्रमिक दिया जाता है। दो-चार कलाकारों को छोड़ अन्य कलाकारों को तो नाम मात्र ही पारिश्रमिक दिया जाता है। अपनी सृष्टि के सामने फटे-गंदे कपड़े पहनकर खड़े एक मूर्तिकार की ओर कोई भी नहीं देखता। वह एक उपेक्षित वस्तु की तरह पूजा-पंडाल के एक कोने में खड़ा-पड़ा रहता है। उस कलाकार के दिल की व्यथा को समझने का किसी के पास भी वक्त नहीं होता और मूर्तिकार भी कभी नहीं सोचता कि उसकेबारे में सोचने का अथवा उसकी बातें सुनने का किसी के पास वक्त भी होगा। ऐसे में यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि कौन समझेगा इन मूर्तिकारों की व्यथा। l

पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी है मगर भक्ति ?

पिछले कई सालों से दुर्गा पूजा आयोजन की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पहले हरिशोभा अथवा सार्वजिनक स्थान, क्लबों में ही दुर्गा पूजा हुआ करती थी, मगर अब तो एपार्टमेंटों में भी पूजा पंडाल बनने-सजने लगे हैं। सिर्फ पूजा पंडालों की ही संख्या बढ़ी हो ऐसी बात नहीं है। सजावट आदि में भी सैकड़ों गुणा वृद्धि हुई है। दुर्गा पूजा के दौरान चारों ओर आलोक सज्जा का नजारा देखते ही बनता है। नगर-शहर की बात छोड़ ही दें तो अब तो गांवों की पूजा भी आम नहीं रही। गांव-शहर के पूजा पंडालों में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया है। अनादि काल से ही दुर्गा पूजा होती आई है। दुर्गा पूजा को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। सुरथ राजा द्वारा शुरू की गई वासंती पूजा बाद में रावण वध के लिए शरत ऋतु में आयोजन किए जाने का भी रामायण सहित अन्य कई ग्रंथों में जिक्र मिलता है। भगवान श्रीराम द्वारा रावण वध के लिए अकाल बोधन का आयोजन करने के बाद ही प्रभु भक्तों ने शरत में ही दुर्गा पूजा करना शुरू कर दिया। देश केविभिन्न हिस्सों में आज भी परंपरागत ढंग से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। हालांकि दक्षिण भारत के अलावा मुबंई, दिल्ली आदि स्थानों पर दशहरे को ही लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। आसुरी शक्तियों

का विनाश कर समाज-देश में शांति स्थापित करने के लिए ही दशहरे का आयोजन किया जाता है। दशहरे पर जितनी भीड़ उमड़ती है, असम आदि राज्यों में चार दिवसीय शारदीय उत्सव के दौरान उतनी भीड़ नहीं उमड़ती। विशाल आकार की रावण की मूर्ति बनाकर दशहरे के दिन उसका दाह करने के आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। दशहरे के दिन असम के विभिन्न स्थानों पर नदी, तालाब, बिल, झरने आदि में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं।

पूजा के कई दिन पहले से ही पंडाल आदि बनाने-सजाने का काम शुरू हो जाता है। आजकल कौन कितना बड़ा और सुंदर पंडाल बना सकता है, कौन-सी पूजा समिति दुर्गा पूजा के नाम पर कितने लाख रुपए खर्च करती है, इसी को लेकर एक तरह की अघोषित प्रतियोगिता देखने को मिलती है। ऐसी प्रतियोगिताओं से फिजूलखर्ची का मार्ग तो प्रशस्त हुआ, मगर भक्तों की संख्या में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। पूजा पंडालों में सजावट देखने के लिए जाने वाले अधिकतर श्रद्धालुओं को प्रतिमा-प्रणाम करने और निर्माली तक लेने का ख्याल नहीं रहता। मानो वे लोग दुर्गा दर्शन नहीं, सजावट देखने को ही आए हों। बच्चों के साथ पूजा देखने के लिए जाने वाले माता-पिता स्वयं तो प्रणाम करते हैं, मगर पंडाल के पास खड़े अपने बच्चों को इसका अनुकरण करने को नहीं कहते। और तो और, वे दूसरों के सामने यह बात गर्व के साथ कहते भी हैं कि हमारे बच्चे प्रणाम करने और माथे पर तिलक लगवाने में आना कानी करते हैं। ऐसी मानसिकता धर्म और समाज दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। आज के दिन दुर्गा पूजा के आयोजन में सिर्फ आडंबर के ही दर्शन होते हैं, मगर ऐसे आडंबर से किसी पूजा के मानदंड को तय नहीं किया जा सकता। पुरातन परंपराओं को बनाए रख पूजा के आयोजन में जो मादकता है, वह अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। परंपरा का हमेशा ही सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि परंपरागत नीति-नियमों का अनुपालन करते हुए जो धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, वहां दिखावा, सजावट भले ही न हो भक्तों की भीड़ जरूर दिखाई देती है। l

कौन लेगा अनाथ बच्चों की सुध

हर एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना चाहता है। बच्चे जिस तरह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहते हैं, वैसे ही माता-पिता भी अपने बच्चों, भाई-बहनों के साथ संयुक्त परिवार की तरह रहना चाहते हैं। मगर ऐसी दुनिया से दूर रहने वाले अनाथ बच्चों के मन में क्या इस प्रकार का सुख-आनंद उठाने का ख्याल नहीं आता होगा। वह लोग भी माता-पिता से मिलने वाले स्नेह-प्यार को हासिल करना चाहते हैं, मगर ऐसा उनके नसीब में नहीं है। इसीलिए तो कोई भी पर्व-त्योहार आता है तो ऐसे अनाथ बच्चे मन ही मन रोते-बिलखते रहते हैं। ये बच्चे समाज के हर मामले में, हर क्षेत्र में वंचित हैं, उपेक्षित हैं। इन अनाथ बच्चों को पता ही नहीं होता कि माता-पिता का प्यार और परिवार का अपनापन क्या होता है। मगर इन अनाथ बच्चों के सीने में भी आम लोगों की तरह एक दिल धड़कता है। किसी से यदि थोड़ा भी प्यार-ममता मिल जाए, थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिल जाए तो इन बच्चों को जिंदा रहने का ही नहीं, जिंदगी की जंग में और एक कदम आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।

दुर्गोत्सव जैसा कोई ही पर्व-त्योहार आता है तो हम सभी उसके उल्लास में मदमस्त हो जाते हैं। अपने बच्चों को लेकर खरीददारी का दौर शुरू हो जाता है। पूजा-बिहू के मौकों पर बच्चों के लिए नए कपड़े, खिलौने, बैलून और न जाने क्या-क्या खरीदने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। बाजारों में खरीददारी के लिए मानो जनसमुद्र उमड़ पड़ता है, कौन क्या खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है। यह जानने की किसी को भी सुध नहीं रहती, इस व्यस्तता में काश! हम अनाथालय के बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया के अनाथ बच्चों के बारे में भी सोच पाते। इन अनाथ बच्चों का भी तो पूजा-बिहू के मौके पर नए कपड़े पहनने का मन होता ही होगा। इनको भी तो इंतजार रहता होगा कि पूजा के मौके पर कोई उनको भी बैलून दे, खिलौनों के लिए पूछे और अपने साथ पूजा दिखाने ले जाए। मगर इस व्यस्त जिंदगी में शायद ही कोई व्यक्ति

होगा, जिसे इन अनाथ बच्चों की खुशियों की सुध हो। सभी अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर ही व्यस्त हैं। किसी ने कहा है, 'आपकी खुशियां, त्योहार तब तक अधूरे हैं, जब तक आपका पड़ोसी दुखी और भूखा है'। यह बात इन अनाथ बच्चों के मामले में भी सटीक बैठती है। अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है और अनाथ बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना हमारा सामाजिक कर्तव्य है।

राज्य के विभिन्न इलाकों में तांडव मचाकर बाढ़ को विदा हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए। बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेघर होकर आज भी बांध के ऊपर और तंबुओं के नीचे अपनी रातें गुजराने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर दुर्गोत्सव के नाम पर लाखों-करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। महानगर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में पूजा-पंडाल बनाने-सजाने की अघोषित प्रतियोगिता चल रही है। एक-एक पूजा समितियों का पूजा बजट 4 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। इन पूजा समितियों में सजावट, दिखावे की आपसी होड़ लगी हुई है। मेरा इन सब से कोई विरोध नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि दुर्गोत्सव के मौके पर पूजा पंडाल नहीं बनने चाहिए, सजावट नहीं होनी चाहिए अथवा खर्च भी नहीं किया जाना चाहिए। मेरा तो मात्र यही कहना है कि दुर्गोत्सव के आनंद की लहर समाज के अंतिम व्यक्ति तक के मन को छूनी चाहिए। दीपावली के दिए की रोशनी समाज के सबसे गरीब के घर तक पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह दुर्गोत्सव, वह दीपावली असंपूर्ण है।

पिछले साल महानगर की कई पूजा समितियों ने अनाथ बच्चों से लेकर दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए भी अपने पंडालों में विशेष आयोजन किए थे। अनाथ, दिव्यांग, वृद्धों में नव-वस्त्र आदि भी बांटे गए थे। मगर इस साल ऐसा आयोजन नजर नहीं आता। मैने स्वयं करीब दो दर्जन से अधिक पूजा समितियों के अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की है। सभी से मुझे एक ही जवाब मिला, नहीं इस बार वैसा कोई आयोजन नहीं है। ऐसे में यह सवाल अब भी कायम है कि बिना अनाथ बच्चों को दुर्गोत्सव की खुशियों में शामिल किए, क्या इस उत्सव को संपूर्ण आनंददायक कहा जा सकता है। l

रूपकुंवर के सपने और हम

रूपकुंवर ज्योतिप्रसाद अग्रवाला उन महान व्यक्तियों में शाामिल हैं, जिनका हर असमवासी सुबह उठते ही श्रद्धापूर्ण स्मरण करता है। असमिया जाति को अटूट रूप से चाहने वाले इस महान व्यक्ति ने असम के साहित्य-संस्कृति जगत में अपना जो योगदान दिया है, वह हमेशा अमर रहेगा। रूपकुंवर ज्योतिप्रसाद अग्रवाला को यदि हटा दिया जाए तो असमिया साहित्य-संस्कृति का मूल्यांकन ही करना मुश्किल हो जाएगा। जब असमिया जाति एक जटिल प्रक्रिया से गुजर रही थी, उस वक्त जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए रूपकुंवर ही सबसे पहली पांत में खड़े हुए थे। असमिया जाति को विश्वपटल पर स्थापित करने के लिए जो-जो करना चाहिए था, उन्होंने वो सारे जतन किए। उनकी ही कोशिशों का नतीजा था कि असमिया जाति एक बार फिर सर उठाकर खड़ा होने में कामयाब हुई। जब असमिया भाषा के समक्ष संकट खड़ा हो गया था, वैसे समय में ज्योतिप्रसाद ने मातृभाषा को जिंदा रखने के लिए अपने दिन-रात एक कर दिए थे। उनके द्वारा लिखित गीत-कविताएं हर एक असमिया व्यक्ति के रोम-रोम में समाए हुए हैं। बाद में उनके लिखे गीतों को जिंदा रखने के लिए उन्हें 'ज्योत संगीत' के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। ज्योति संगीत का जिक्र आते ही हर एक असमिया इसके शब्द-अर्थ, सुर-ताल में खो-सा जाता है। कहा जाए तो ज्योति संगीत का हर एक शब्द ही गीत है, जिसका अर्थ

प्रशांत महासागर से भी गहरा जान पड़ता है। उनकी एक-एक कविता में एक आदर्श छिपा नजर आता है। एकता और शांति की स्थापना के लिए हर पल-हर घड़ी कोशिशों में लगे रहने के फलस्वरूप ही एक स्वस्थ समाज का गठन हो पाया था। ज्योतिप्रसाद के निधन के बाद भी उनकी श्रद्धा करने वाले-उन्हें पूजने वाले लोग रूपकुंवर की साहित्य-कला को जिंदा रखना चाहते हैं, जिसने असमिया जाति को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दिया।

रूपकुंवर ने हमेशा ही एक स्वस्थ समाज की कामना की थी। साहित्य-संस्कृति के माध्यम से असमिया जाति को विश्व की अन्य दस अग्रणी जातियों की पंक्ति में खड़ा करने की उम्मीद में उन्होंने दिन-रात असमिया साहित्य-संस्कृति को समृद्ध करने की दिशा में काम किया। उनके सुझावों ने आगे भविष्य में भी असमिया जाति को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। उनकी रचनाओं ने असमिया साहित्य को एक नई दिशा दी थी। अपनी जातीय चेतना संपन्न लेखनी के माध्यम से मातृभूमि को प्यार करने वाले हर एक व्यक्ति के मन में सुप्त पड़े मातृबोध को जागृत करने के लिए ज्योतिप्रसाद आज भी असमवासियों के दिल में रोशन हैं।

ज्योतिप्रसाद की रचनाएं आज भी असमवासियों को हर कदम पर सचेत रहने का स्मरण कराती है। मगर देखा जा रहा है कि हमारी नई पीढ़ी इस महान कलाकार की साहित्य-कला को भूलने लगी है, नजरअंदाज करने लगी है। कुछ युवा तो ज्योतिप्रसाद की रचनाओं के बारे में ठीक से जानते तक नहीं हैं, जबकि विदेशी लेखकों की पुस्तकों से इनका घर भरा रहता है। विदेशी लेखकों की किताबें पढ़े जाने पर हमें एतराज नहीं है, मगर ज्योतिप्रसाद अग्रवाला की रचनाएं भी विश्व स्तर के अन्य साहित्यकारों की तुलना में किसी भी मायने में कम नहीं हैं। यह बात अलग है कि हम ही उनके साहित्य को, उनकी रचनाओं को विश्वपटल पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। नई पीढ़ी के बीच यदि ज्योतिप्रसाद अग्रवाला के साहित्य, उनकी रचनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए तभी जाकर उनकी रचनाएं युवाओं तक पहुंचेंगी और रूपकुंवर का सपना हकीकत में बदलेगा। 1

पत्र मित्र, एसएमएस और फेसबुक

दोस्ती के बंधन को मजबूत करने और मन की भावनाओं के आदान-प्रदान के मामले में पत्र (चिट्ठी) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन काल में भी पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा बहुत से संबंध-रिश्तों को जिंदा रखा जाता था। भारत भू-खंड में भी राजा-महाराजाओं के बीच के रिश्ते को बेहतर और मजबूत बनाए रखने में पत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। दरअसल उस जमाने में पत्र के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। लंबे इंतजार के बाद यह पत्र अपने ठिकाने पर पहुंचता था। पत्र के अंदर का मजमून क्या है, यह जानने-पढ़ने के लिए जिज्ञासा का अंत ही नहीं रहता था। ऐसी बहुत-सी दोस्ती के उदाहरण हैं, जो ऐसे पत्रों के दम पर ही परवान चढ़े और जिंदा रहे। ऐसा ही होता था पत्रों के माध्यम से वैसे लोगों के साथ भी भावनाओं-विचारों के आदान-प्रदान की शृंखला चलती रही थी, जिनसे न तो कभी मिले और न ही कभी देखा। उस अनदेखे दोस्त के साथ भी पत्र-लेखक अपना सुख-दुख बांट लिया करते थे। सिर्फ यही नहीं, जिंदगी के संघर्ष से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऐसे पत्रों के जरिए पूछ लिया-बता दिया जाता था। ऐसे पत्र कभी-कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा असर करते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का इंदिरा के जीवन पर किस कदर प्रभाव पड़ा था, इस बारे में विस्तार से लिखे जाने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में हम 'पत्र-मित्र' परंपरा का भी जिक्र कर सकते हैं। यह परंपरा कब-कहां-कैसे शुरू हुई, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर ऐसे पत्र मित्र, जिनको कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी-कभी अपने विचार, अपनी सोच से सामने वाले व्यक्ति को गहरे तरह से प्रभावित करते हैं। वैसे पत्र-मित्रता की कोई वजह नहीं होती, सिर्फ कुछ मुद्दों पर दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान मात्र होता है। इसके अलावा निजी जिंदगी, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य मुद्दों पर भी पत्र मित्र के साथ

विचार-विमर्श किया जाता है। लोगों में यह आम धारणा रही है कि पत्र मित्रता आमतौर पर लड़के-लड़की के बीच ही होती है। यह सोच संपूर्ण सच पर आधारित नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि पहले लड़के-लड़की के बीच पत्र मित्रता हुई और बाद में वह मित्रता प्रेम व शादी में बदल गई। दो-चार मामलों में ऐसा हो भी जाए तो भी पत्र मित्रता पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। वैसे भी हर एक वस्तु के अच्छा और बुरा दो पहलू होते हैं। अब कौन किस वस्तु को किस तरीके से लेता है, वह सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है। याद होगा ऊषा-अनिरूद्ध की प्रेम-कथा में भी चित्रलेखा ने एक डाकिए की भूमिका निभाई थी।

आज के दौर की दोस्ती में 'पत्र' जैसा शब्द सुनने को नहीं मिलता। एसएमएस और फेसबुक ने पत्र की सोच व महत्व को धुंधला कर दिया है। मोबाइल पर मिस्ड कॉल, क्रास कनेक्शन, गलती से अन्य नंबर पर फोन करना अथवा मैजेस भेजना दोस्ती की बुनियाद बन सकता है। कभी-कभी ऐसी हरकतें जान बूझकर की जाती हैं, लिहाजा इस बुनियाद पर खड़ी दोस्ती की इमारत बहुत थोड़े से समय में ही भरभराकर गिर पड़ती है। इसके अलावा अपना निजी हित साधने के लिए भी कुछ लोग इस तरह की दोस्ती करते हैं, लिहाजा ऐसी दोस्ती करने वालों को कभी-कभी भारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। आजकल ऐसी दोस्ती करने वालों की संख्या कम नहीं है। मोबाइल अथवा फेसबुक पर परवान चढ़ने वाली दोस्ती का अंजाम कैसा होता है, इसकी भी खबरें अखबार-टीवी चैनलों में आती ही रहती हैं। ऐसी घटनाओं से हमें यह सबक मिलता है कि बिना जान-पहचान वालों से दोस्ती करने का नतीजा कभी-कभी कितना भयावह हो सकता है। एक मिस्ड कॉल अथवा एसएमएस से फटाफट होने वाले प्यार का अंजाम अपहरण, हत्या, बलात्कार भी हो सकता है। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कहता। इस बारे में आए दिन छपने वाली खबरें और टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले समाचार भी कहते हैं। लिहाजा फेसबुक अथवा मोबाइल पर दोस्ती-प्रेम करने से पहले जरा ठहरें, जरा सोचें और बाद में एक समझदारी भरा फैसला करें। l

प्रकाशोत्सव पर चीन का हमला

प्रकाशोत्सव 'दीपावली' अब प्लास्टिक-प्रदूषण के पर्व का रूप लेता जा रहा है। इस अस्वस्थ माहौल के लिए चीन में निर्मित सामग्री को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि दीपावली के मौके पर पूरा बाजार चीन में निर्मित प्लास्टिक के दीये, मोमबत्ती, आतिशबाजी और पटाखों से भर जाता है। इस दृश्य को देखने के बाद एक बार तो लगता है, जैसे दीपावली जैसे प्रकाश-पर्व को भी हमने एक बाजार बना दिया है। इस पर्व से जुड़ी हर एक सामग्री चीन में बनने लगी है। यहां तक कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश भी। हमारे देश में सदियों से दीपावली का पर्व मनाया जाता रहा है। धर्मग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्रीराम जब रावण का वध कर, अपना वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने अपने घरों के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर खुशियां मनाई थी। उसके बाद से ही मंगल का प्रतीक माने जाने वाले केले के पेड़ को घर के सामने लगाकर उस पर कतार से दीप प्रज्ज्वलित करने का रिवाज चल निकला। केले के पेड़ पर लगी बांस की तख्ती के ऊपर जलते दीपों की सुंदरता को सिर्फ दीपावली की रात को ही निहारा जा सकता है। सरसों के तेल में भींगी बाती की नोंक पर लहराती लौ को देख, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद प्लास्टिक के दीये में लगे एक छोटे से बिजली के बल्ब को जला लेने से हासिल नहीं हो सकता।

दीपावली के मौके पर प्रज्ज्वलित किए जाने वाला सरसों के तेल का दीया सिर्फ सुंदरता के ही दर्शन नहीं कराता, बल्कि फसल को विभिन्न प्रकार की बीमारी-कीड़ों से भी बचाता है। इन दीयों की रोशनी में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट-पतंग जल मरते हैं। वैसे दीपावली को हमारे देश की संस्कृति-पर्व-त्योहार के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस त्योहार पर मानो किसी की नजर लग गई है। एक ओर जहां पर्व से जुड़ी परंपराएं खत्म हो रही हैं, वहीं

दूसरी ओर से पर्व का बाजारीकरण किया जा रहा है। कुम्हार की चाक पर बनने वाले दीये आहिस्ता-आहिस्ता ओझल होने लगे हैं। नतीजन कुम्हार के चाक ठहरे हुए और चूल्हे बुझे पड़े हैं। चीन से आयातित सामग्री ने हमारे देश के अति प्राचीन कुटीर उद्योग पर सबसे पहले हमला बोला। मिट्टी का दीपक जब अस्तित्व में नहीं आ पाया तो रूई की बाती को भला कौन पूछे। ऊपर से इस साल सरसों तेल की बढ़ती कीमतों ने चीनी सामग्री को एक मौका और लोगों को एक बहाना दे दिया।

अब तो दीपावली के मौके पर केले के पेड़ के भी दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। रंगोली बनाने की जरूरत भी चीन ने खत्म कर दी है और उतना समय भी किसी के पास नहीं रह गया है। रंगोली के लिए बेहद सरल उपाय है। बाजार जाइए 'मेड इन चाइना' की रंगोली लाइए और फर्श पर चिपका दीजिए, बस हो गया काम पूरा। पहले घर के मुख्यद्वार के अलावा अन्य दरवाजों पर बंदरवार लगाने के लिए आम के पत्तों का उपयोग किया जाता था। अब शहरों में आम के पेड़ कहां से लाएं। लिहाजा चीन ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है। बाजार में चीन में बने एक से एक बंदरवार पांच सौ रुपए से लेकर पंद्रह सौ रुपए तक की रेंज में उपलब्ध हैं। यह बात हर भारतीय के दिल को कचोटनी चाहिए कि अब तो हमारे आराध्य देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश तक की प्रतिमाएं भी चीनी सांचों में ढाली जाने लगी हैं।

दीपावली के मौके पर उपयोग में लाई जाने वाली चीनी सामग्री को इधर-उधर फेंक दिया जाता है, जो आगे चलकर हमारे पर्यावरण-फसल और वातावरण को प्रभावित करती है। दीपावली के मौके पर मिट्टी के दीये में सरसों के तेल से भींगी बाती जलाने का संकल्प लेना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपने बजट के हिसाब से हम चार दीये कम जलाकर भी दीपावली की अंधेरी रात को रोशन कर सकते हैं। ऐसा कर हम अपने पर्यावरण को ही प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, बल्कि भुखमरी के शिकार राज्य के कुम्हारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। चलिए, अब की बार दीपावली में एक मिट्टी का दीया जलाएं, जो सरसों के तेल में भीगीं बाती से प्रकाशमय हो। ।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद

दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले अलग-अलग कबीलों की अपने-अपने इलाके अपनी-अपनी सीमाएं होती थीं। मगर सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहने पर भी पिछले तीन-चार दशकों से भारत-चीन की मैक-मोहन लाइन के अलावा भारत-पाकिस्तान, पश्चिम जर्मनी-पूर्वी जर्मनी, उत्तर-दक्षिण कोरिया का सीमा विवाद सर्वाधिक चर्चा में रहा है।

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा विवाद को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। 1953 में 'कोरियन आर्मिस्टक एग्रीमेंट' के बाद कोरियन लड़ाई तो खत्म हो गई, मगर उसके बाद भी दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चलता ही रहा। 30 अगस्त, 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ और अमरीका के संयुक्त प्रयासों से 'नॉर्दन लिमिट लाइन' अंकित की गई थी। फेल्ल शिबा द्वारा पश्चिम सागर पर आंकी गई सीमा लाइन को 1973 में उत्तर कोरिया ने चुनौती दी। बाद में दक्षिण कोरिया ने भी जब इसका विरोध किया तो दोनों देशों में शीत युद्ध शुरू हो गया। अभी भी यह युद्ध पूरी तरह से थमा नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस लड़ाई के नाम पर ही दोनों देशों के नेता अपनी-अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कुछ नेता इस लड़ाई को खत्म करने की दिशा में जी-तोड़ कोशिशें कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेता इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर दोनों देशों के सैन्य प्रमुख अपनी-अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए आत्मसमर्पण करने से कतरा रहे हैं। इस मामले में दक्षिण कोरिया के तनिक नरमी दिखाने पर भी उत्तर कोरिया का रवैया पूरी तरह से आक्रामक नजर आता है।

1989 तक 'बर्लिन की दीवार' पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दुश्मनी की गवाह बनी नजर आती थी। मालूम हो कि 1961 में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (पूर्व जर्मनी) ने इस दीवार का निर्माण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मन दो टुकड़ों में (पूर्व एवं पश्चिम जर्मनी) विभक्त होने

के बाद पूर्व जर्मनी ने पश्चिम जर्मनी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की ताकतों का प्रयोग किया था। एक समय दोनों देशों के बीच की कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि मौका मिलते ही दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़ते थे। अस्सी के दशक के अंत में पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के नेता इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आगे आए। इसी क्रम में 1989 में 'बर्लिन की दीवार' को ढहा दिया गया। दोनों देशों के फिर से एक हो जाने पर विश्व भर में जर्मनी एक ताकतवर देश बनकर उभरा। राजनीतिक क्षेत्र से शुरू कर खेल, संस्कृति, अर्थनीति आदि सभी मामलों में जर्मनी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा। 'द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ' के रूप में विख्यात ओलंपिक में डेढ़ दशक पहले तक पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के अलग-अलग प्रदर्शन करने पर भी दोनों देशों का प्रदर्शन काबिले तारीफ होता था, मगर जब दोनों देश एक साथ मिलकर मैदान में उतरे तो पदकों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिला। 'बर्लिन की दीवार' को गिरा दिए जाने के बाद अंत में ताकतवर रहा जर्मनी एक बार फिर ताकतवर देश के रूप में उभरा।

भारत-पाकिस्तान के सीमा विवाद की तरह भारत-चीन विवाद भी पिछले लंबे समय से चर्चा में है। पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिशों में लगा है, ठीक उसी तरह चीन भी 1962 से ही अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। भारत-चीन के बीच मैक-मोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर भी समय-समय पर विवाद होता रहा है। चीन ने तो अभी हाल ही में अपने मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को अपने देश के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के समय भी यह मुद्दा चर्चा में आया था। उस वक्त इस मुद्दे को हवा दिए जाने की घटना को भारत-चीन के बनते रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। मगर चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिमालय तक रेल लाइन बिछाने के साथ ही सड़क मार्ग बनाकर एक तरह से भारत को चुनौती देने का काम किया है। चीन द्वारा हिमालय पर हेलीपैड का निर्माण करना भी एक तरह से भारत के लिए चुनौती है। 1

फैंसी बाजार-न्यू मार्केट अग्निकांड का सबक

फैंसी बाजार के एसआरसीबी रोड स्थित न्यू मार्केट में दीपावली की रात लगी भीषण आग भले ही बुझ गई है, मगर लोगों के दिलों में उत्पन्न खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लगातार 48 घंटे तक आग और धुआं उठता रहा, अग्नि पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन, विभाग और आमलोग दिन-रात लगे रहे। मगर इस भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आए जो तमाशा देखने अथवा अपने मोबाइल पर घटनास्थल की फोटो खींचते रहे। ऐसे लोगों की भीड़ ने राहत कार्य में खलल डालने का भी काम किया। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मी इन्हें भगाते-खदेड़ते रहे, मगर यह लोग अपनी हरकतों से बाज आने का नाम तक नहीं ले रहे थे। इन सब के बीच राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर चलता रहा। प्रशासनिक अधिकारी राहत कार्य की देख-रेख में लगे थे तो दमकल विभाग के जवान दिन-रात आग बुझाने के काम में लगे थे। इसी दौरान कई जवान धुएं की वजह से बेहोश भी हुए, मगर किसी ने भी अपना हौसला नहीं खोया। कई समाजसेवी संगठनों के अलावा फैंसी बाजार के लोगों ने आग प्रभावितों की ओर जिस तरह से मदद के हाथ बढ़ाए, उस सेवा भाव की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्राकृतिक आपदा से एकजुट होकर मुकाबला करने का ऐसा उदहारण बहुत कम ही देखने को मिलता है। इन समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारी-सदस्यों के अलावा कुछ गुमनाम युवाओं ने राहत कार्य में लगे अधिकारी-जवानों को पीने के पानी की बोतलों से लेकर चाय-बिस्कुट तक की लगातार आपूर्ति की। कई ने आग बुझाने के चक्कर में अपने हाथ जला डाले तो कई ने राहत कार्य में लगे जवानों को मदद पहुंचाने के नाम पर हजारों

खर्च कर डाले। घटनास्थल के चारों ओर लगी लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने का जिम्मा मानो इन युवकों ने ही उठा रखा था। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास के उन होटल मालिकों को भी धन्यवाद देना होगा, जिन्होंने लगातार पानी की आपूर्ति कर आग को बुझाने में दमकल विभाग की मदद की।

वहीं दूसरी ओर न्यू मार्केट में लगी आग की इस घटना ने फैंसी बाजार के व्यापारियों के अलावा सरकार-प्रशासन की आंखों को भी खोल दिया है। घटनास्थल के पास ही ब्रह्मपुत्र बहने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किए जाने के कारणों की प्रशासनिक अधिकारी निश्चय ही समीक्षा कर रहे होंगे। इस घटना से सरकार को भी सबक मिल गया होगा कि उसके अग्निशमन विभाग में कहां-कहां किस प्रकार की खामी है अथवा दमकल विभाग को किस तरह की आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना चाहिए। यह आग कैसे लगी यह जांच का विषय है। कामरूप महानगर जिला दंडाधीश डॉ. एम. अंगामुत्थु ने घटना के दूसरे दिन ही इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। इस घटना का जांच कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, मगर इसे ही काफी नहीं मान लिया जाना चाहिए। इस घटना से सबक लेते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में यदि ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो बिना अफरा-तफरी के उससे निपटा जा सके।

फैंसी बाजार के व्यापारियों को भी इस घटना से यह सबक लेना चाहिए कि आग से बचने के उपाय नहीं करने का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। एक नन्हीं-सी चिंगारी का भड़कना अथवा किसी की एक छोटी-सी गलती भीषण आग का कारण बन सकती है। बेहतर होगा आग लगने के बाद उस पर काबू पाने के उपाय खोजने के बजाए ऐसे कदम उठाने पर अधिक ध्यान दिया जाए जिससे आग ही न लगे। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग बुझाने के उपकरण लगा कर, अति ज्वलनशील पदार्थों को दुकान में नहीं रखकर आग लगने के खतरे को कम किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात-किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए सतर्कता और जागरूकता को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। l

अलग से मारवाड़ी साहित्य सभा की जरूरत क्या है

असम में सदियों से निवास करने वाले मारवाड़ी संप्रदाय के कुछ लोगों ने मारवाड़ी साहित्य सभा का गठन किए जाने की जरूरत को रेखांकित किया है। असम की धरा पर रहकर 'आई असमिया' की हवा-पानी का सेवन करने वाले तथा तन और मन से स्वयं को असमिया बताने वाले ये लोग क्यों अलग से मारवाड़ी साहित्य सभा का गठन करने की कोशिशों में लगे हैं, यह बात समझ से परे है। मारवाड़ी संप्रदाय के बहुत से साहित्यकार असमिया भाषा में पुस्तकें लिखकर असम के साहित्य जगत को समृद्ध करते आए हैं। असम साहित्य सभा के साथ ओत-प्रोत ढंग से जुड़े मारवाड़ी साहित्यकारों की भी संख्या कम नहीं है। निचली, ऊपरी अथवा मध्य असम कोई भी हिस्सा क्यों न हो, सभी जगहों पर बहुत से मारवाड़ी असमिया साहित्य की चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। असमिया भाषा में कहानी, कविता, नाटक आदि लिखने वाले मारवाड़ी साहित्यकारों की सूची बहुत लंबी है। असम साहित्य सभा के इतिहास के पन्नों पर यदि नजर डाली जाए तो पता चलता है कि साहित्य सभा में मारवाड़ी लोगों का अतुलनीय योगदान रहा है। असम साहित्य सभा ने बिना किसी संकोच के अपने मंच पर ऐसे मारवाड़ी साहित्यकारों को जगह दी है। आनंदराम अग्रवाला को तो असम साहित्य सभा के अध्यक्ष पद से अलंकृत किया जा चुका है। असम साहित्य सभा ने परोक्ष रूप से इन साहित्यकारों को असम और असमिया जाति के एक अंग केरूप में स्वीकार किया है। कई साहित्यकारों को साहित्य सभा ने आजीवन सदस्य बनने तक का मौका दिया है और ऐसे लोग साहित्य सभा के हर एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे एक विराट जातीय संगठन का हिस्सा बनने के बजाए अलग से मारवाड़ी साहित्य सभा गठन की

पैरवी करने वालों का नजरिया मेरी समझ से परे है।

असम के साहित्य-सांस्कृतिक जगत में रूपकुंवर ज्योतिप्रसाद अग्रवाला के योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता। असम को दिल की गहराइयों से प्यार करने वाले ज्योतिप्रसाद अग्रवाला की वजह से ही असमिया फिल्म जगत आज एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच पाया है। उनकी कई पुस्तकों ने असमिया साहित्य जगत को समृद्ध किए रखा है। समस्त असमवासी जिस व्यक्ति का प्रातः उठते ही स्मरण करते हैं, वे हैं ज्योतिप्रसाद अग्रवाला। चंद्र कुमार अग्रवाला के योगदान को कौन भूल सकता है। छगनलाल जैन ने असमिया साहित्य को समृद्ध करने के लिए क्या नहीं किया था। इन सारे प्रातः स्मरणीय व्यक्तियों ने कभी भी अलग से मारवाड़ी साहित्य सभा गठन की बात नहीं कही थी। मगर आज के दिन कुछ लेखक असम में असम साहित्य सभा जैसी मारवाड़ी साहित्य सभा के गठन में लगे हुए हैं। यदि असम में मारवाड़ी साहित्य सभा का गठन किया जाता है तो असमिया लोग मारवाड़ियों को वृहत्तर असमिया समाज का अविच्छेद अंग के रूप में स्वीकार करने से कुछ हद तक हिचकेंगे। असम में निवास करने वाले लगभग सभी मारवाड़ी खुद को 'असमिया मारवाड़ी' के रूप में परिचय देकर गौरव का अनुभव करते हैं। अधिकांश लोगों ने असमिया माध्यम से ही पढ़ाई की है। अब अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालय खुल गए हैं, फिर भी आज के दिन असमिया माध्यम से पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों की भी संख्या कम नहीं है। बोहाग बिहू से शुरू कर हर एक पर्व-उत्सव में भाग लेने वाले असम के मारवाड़ियों के लिए अलग से मारवाड़ी साहित्य सभा के गठन का प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो यह होगा कि असमिया साहित्य की बेजोड़ पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किए जाने पर ध्यान दिया जाए। इसी तरह राजस्थान की कालजयी पुस्तकों का भी असमिया भाषा में अनुवाद किए जाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। असमिया साहित्य सृजन के लिए मारवाड़ियों की अलग से साहित्य सभा बनाने की दलील समझ में नहीं आती। हम सभी को टकराव नहीं, सद्भावना के लिए काम करना चाहिए।

भारत–नेपाल दोस्ती पर चीन की नजर

भारत–नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते को लगता है दीमक लग गई है। पिछले दिनों नेपाल का घटनाक्रम तो कम–से–कम इसी बात की ओर इशारा करता है। पिछले एक साल से परस्पर दोस्त रहे भारत–नेपाल के रिश्तों में दरारें दिखने लगी हैं। नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से तो दोनों देशों के रिश्तों में और भी कड़वाहट घुल गई है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से ही नेपाल के विभिन्न हिंदू संगठन नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसके समानांतर नेपाल सरकार भारत विरोधी भूमिका में नजर

आ रही है। विगत 29 नवंबर को भारत के 13 एसएसबी के जवानों को हथियार समेत नेपाल में प्रवेश करने के बाद वहां की पुलिस ने छह घंटे तक इन जवानों को रोके रखा और बाद में रिहा भी कर दिया। मगर भारत ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया है। नेपाल जैसे देश द्वारा भारत के एसएसबी के जवानों को रोके रखना यह भारत केआत्मसम्मान पर सीधी चोट है। इतने दिनों भारत-नेपाल दोनों ही आपस में मधुर संबंध होने का दावा करते आ रहे थे। दोनों देशों के बीच आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक-कला के क्षेत्र में एक मजबूत संबंध था, जबकि राजनीतिक मामलों में भी भारत के सामने नेपाल का एक अलग ही स्थान था। नेपाल को एशिया के कमजोर देशों में शामिल समझा जाता है और आर्थिक तौर भी नेपाल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। नेपाल पर जब भी कोई संकट आता है, मददगार के रूप में भारत ही सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाता है। इसके अलावा नेपाल भी अतीत काल से ही भारत के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाते आया है।

नेपाल जैसा देश जो कल तक काफी हद तक भारत पर निर्भरशील था वह आज भारत को आंखें दिखाने लगा है तो यह कम गंभीर बात नहीं है। भारत की सैन्य शक्ति के सामने नेपाल कहीं भी नहीं ठहरता, इसके बावजूद यदि वह भारत के एसएसबी के 13 जवानों को अपने यहां रोके रखने की हिम्मत दिखाता है तो समझ लेना चाहिए कि नेपाल अब कमजोर राष्ट्र नहीं रह गया है। यहां सवाल यह भी उठता है कि नेपाल में हिम्मत कैसे आई कि वह भारत की ओर अपनी आंखें तरेर सके, इसकेपीछे किसी तीसरी शक्ति का उकसावा तो नहीं है? तीसरी शक्ति ने कहीं नेपाल को यह कहकर तो नहीं भड़का दिया है कि वहां के हिंदू संगठनों के विरोध के पीछे भारत का हाथ है। नेपाल में चल रहे इस आंदोलन में अब तक 40 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं।

नेपाल के करीब आने और नेपाल का समर्थन हासिल करने के लिए चीन हर संभव कोशिशों में लगा हुआ है। आज के दिन नेपाल के बाजार चीन में निर्मित सामग्रियों से भरे पड़े हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था में चीन के बढ़ते प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल नेपाल में आए भीषण भूकंप

के समय राहत पहुंचाने को लेकर भारत और चीन के बीच एक प्रकार से प्रतियोगिता का दौर चल पड़ा था। इसके अलावा नेपाल को विभिन्न मौके पर मदद करने के मामले में चीन भारत से अधिक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करते आया है। नेपाल को सभी प्रकार की मदद करने के सदैव आगे रहने की चीनी प्रवृत्ति को कूटनीति अथवा साजिश से जोड़कर देखा जाता है। भारत और चीन के बीच के रिश्ते कभी भी उतने मधुर नहीं रहे, जितने वे ऊपर से दिखते हैं। दोनों देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए लाख कोशिशें करते दिखें, हकीकत यही है कि भारत–चीन के बीच शीत युद्ध चलता ही रहता है। चीन ने पाकिस्तान को भी विभिन्न प्रकार की सैन्य सहायता उपलब्ध कराकर वहां के मित्र राष्ट्र का दर्जा हासिल कर रखा है। ऐसे में इतने सालों तक भारत का मित्र रहे नेपाल भी यदि अपना पाला बदलकर चीन से हाथ मिला ले और भारत विरोधी रवैया अपना ले तो चीन के लिए भविष्य में कभी भी भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के वक्त घोषणा की थी कि वे पड़ोसी देशों के साथ के संबंधों को और अधिक मधुर व दोस्ताना बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसी की कड़ी के रूप में श्री मोदी ने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। इसके बावजूद अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते ही गए। भारत यदि अब भी अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधार नहीं पाता है तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा।

भारत, नेपाल और भूटान के बीच दोस्ताना संबंधों के बारे में सभी को पता है, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि तीसरी शक्ति इन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करेगी। लिहाजा अब वक्त आ गया है, जब भारत अपनी विदेश नीति पर एक बार फिर से विचार करे। विदेश नीति को लेकर विश्व के सभी देशों के नजरिए में बदलाव आया है तो भारत को भी पुरानी लकीर का फकीर बने बैठे नहीं रहना चाहिए। ।

प्रदूषण के चलते रहने लायक नहीं रह गए बड़े शहर

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे कम करने के लिए यातायात नियमों में कुछ पाबंदी, कुछ कड़ाई किए जाने संबंधी कदम उठाए हैं। देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में आज के दिन प्रदूषण जिस स्तर पर पहुंच गया है, उस गति से यदि प्रदूषण का बढ़ना जारी रहा तो पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक साल बाद दिल्ली किसी के रहने लायक नहीं रह जाएगी। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक योजना के तहत दो दशक पहले दिल्ली में जगह-जगह नीम के पेड़ लगाए गए थे। इससे प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम भी हुआ था। मगर बाद में जब दिल्ली की सड़कों पर पुराने वाहनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने लगी तो इनसे निकलने वाले धुएं ने प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ा दिया।

आज के दिन दिल्ली ही भयावह प्रदूषण की चपेट में है, ऐसी बात नहीं है। विश्व के सभी छोटे-बड़े महानगर प्रदूषण के दुष्परिणाम को भुगत रहे हैं। हाल ही में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चीन के बीजिंग में रेड अलार्ट घोषित किया गया था। चीन की राजधानी बीजिंग में पहली बार इस प्रकार के रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। बीजिंग में बढ़ते प्रदूषण और घने धुएं की वजह से लोगों

का सांस लेना दूभर हो गया है। हमारे देश के और बहुत से शहर-महानगर प्रदूषण की चपेट में हैं। ऐसे शहर-महानगरों के वायुमंडल में तय मात्रा से कई गुणा अधिक प्रदूषण पाया गया है। विश्व में बढ़ते प्रदूषण और इसके प्रभाव पर अध्ययन करने वालों ने दिल्ली और बीजिंग को विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ऐसे भयावह प्रदूषण को लेकर विश्ववासियों को सतर्क किया था। बढ़ते प्रदूषण के साथ ही पूरे विश्व का तापमान भी बढ़ने लगा है। पहले शीत प्रधान देशों में तापमान यदि 20 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता था तो कहा जाता था बहुत गर्मी है, मगर अब ऐसे देशों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने पर भी उसे सामान्य करार दिया जाता है। और तो और अटलांटिक महादेशों में भी बड़ी तेजी से बर्फ गलने लगी है। आज से 20 साल पहले अटलांटिक जाने वाले शोधकर्ता अथवा यात्रियों को जो दृश्य देखने को मिलते थे, वैसे दृश्य अब नजर नहीं आते। उपग्रह से खींची गई तस्वीरों में बड़े-बड़े हिमखंडों के पिघलने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा वैज्ञानिक वायुमंडल के ओजोन की परत में छेद होने की बात भी कह रहे हैं। इस वजह से इंसानों के अलावा जीव-जंतुओं में भी नई-नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। कई साल पहले जो बीमारियां लोगों में बहुत कम देखने को मिलती थीं, वे बीमारियां आजकल आम हो गई हैं। बढ़ते प्रदूषण का इंसानों पर बढ़ते असर का ही परिणाम है कि पहले जो बीमारियां लोगों को आसानी से नहीं होती थीं, वैसी बीमारियां आज के दिन पूरी दुनिया के सामने चुनौती बन खड़ी हैं।

पूरे विश्व में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से लोगों में सांस संबंधी बीमारियां एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आई हैं। विश्व के जिन देशों में बड़े-बड़े उद्योग आदि हैं, वैसे देशों में तो यह समस्या और भी अधिक गंभीर बनी हुई है। प्रदूषण के फैलने का सिलसिला यदि इसी तरह से जारी रहा तो एक दिन बड़े शहर लोगों के रहने लायक ही नहीं रह जाएंगे और लोग संभवत: फिर से शहर छोड़ गांवों का रुख करने लगेंगे। ।

वनभोज पर जाने वाले साफ-सफाई का भी रखें ध्यान

यह वनभोज पर जाने का मौसम है। दिसंबर के गुजरने के साथ ही राज्य के विभिन्न स्थानों से वनभोज पर जाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे भी यदि देखा जाए तो समूचा असम ही वनभोज पर जाने वालों के लिए आदर्श जगह है। पहाड़, हरी-भरी घाटियां, नदियां-झरने क्या नहीं हैं यहां, जो वनभोज पर निकलने वालों को अपनी ओर आकर्षित न करते हों। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे शांत-शीतल स्थान पर वनभोज का एक अलग ही आनंद है। वनभोज पर जाने वाले क्या खाते हैं, क्या नहीं, इस पर बहस नहीं करनी है। मगर यह भी सही है कि आजकल वनभोज पर जाने का अर्थ अधिकांश लोगों के लिए शराब का सेवन तक ही सिमट कर रह गया है। इस कड़ी में उन लोगों को शामिल नहीं भी माना जा सकता है, जो अपने परिवार, रिश्तेदार-मित्र आदि के साथ वनभोज पर जाते हैं। वनभोज पर जाने वाले ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो वनभोज खाने के नाम पर पूरी वनस्थली को गंदा करते हैं। जहां-तहां कचरा फेंक आते हैं। जनवरी के बाद किसी भी वनभोज स्थल पर जाने पर जहां-तहां बिखरी पड़ी शराब की बोतलें, प्लास्टिक के पैकेट, कचरा-गंदगी, जूठन आदि के दर्शन होने आम बात है। हमें ऐसी स्थिति से बचने और वनभोज स्थल की साफ-सफाई पर भी ध्यान देने की भी जरूरत है। 25 दिसंबर से साल के पहले दिन तक को वनभोज पर जाने वालों की इस कदर होड़ लगी रहती है कि एक-एक वनभोज स्थल पर कभी-कभी वनभोज खाने वाले 50-60 ग्रुप एक साथ पहुंच जाते हैं। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि एक स्थान पर यदि दो-तीन हजार लोग दो वक्त का खाना-नाश्ता कर उसका कचरा-जूठन और गंदगी को छोड़ें तो वहां कितनी गंदगी जमा हो सकती है। सवाल यह उठता है कि हम यदि अपने घर-रसोई को साफ-सुथरा रख सकते

हैं तो वनभोज स्थल के उस हिस्से को साफ क्यों नहीं रख सकते, जहां हम साल का सबसे खूबसूरत वक्त गुजराते हैं, चाहे 5-7 घंटे के लिए ही क्यों न हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जहां वनभोज के लिए जाते हैं, उनमें से अधिकांश सिर्फ वनभोज के लिए ही नहीं, पर्यटन स्थल के रूप में भी विख्यात है। चानडूबी, दीपोर बिल, आमसै, मदन-कामदेव, दुसुंतिरमुख, पागलादियार पार, हाहिम महामाया, सूर्यपहाड़, महाभैरव, भालुकपुंग, शिवसागर, जोरहाट, काजीरंगा, मानस, पबितरा, दीर्घेश्वरी, मनिकणेश्वरी आदि विभिन्न स्थानों पर इन दिनों वनभोजकारियों की भारी भीड़ उमड़ी नजर आती है। उक्त स्थानों का ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन के नजरिए से भी खासा महत्व रहा है। इन स्थानों में ही असम का इतिहास छिपा है, इन स्थानों को हम विनष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आसपास का वातावरण यदि दूषित होता है तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा।

वनभोज स्थलों को गंदा करने वालों का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं, उसी तरह से परिवेश को दूषित मुक्त रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके दायरे में रहने वाले सभी को नुकसान पहुंचाता है। कामरूप महानगर जिला प्रशासन ने अब की बार वनभोज पर जाने वालों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हमें न सिर्फ प्रशासन की उक्त पहल का स्वागत करना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिए। यह बात भी मानकर चलना चाहिए कि हर बात थोपी नहीं जा सकती, जबरन नहीं करवाई जा सकती। ऐसे में वनभोज पर जाने वालों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी का अहसास करना होगा। उनको खुद आगे बढ़कर साफ-सफाई पर ध्यान देना होगा। क्या बुरा हो, यदि वनभोज पर जाते वक्त हम एक बैग अपने साथ ले जाएं और वनभोज के समय जमा होने वाले कचरे, गंदगी और जूठन को भर कर उन स्थानों पर डाल दें, जो नगर निगम द्वारा पहले से ही तय हैं। इसके अलावा वनांचल-अभयारण्य में विचरण करने वाले वन्य जीवों की शांति में खलल न पड़े, इसके लिए हम सभी को वनभोज के समय उच्च स्वर में लाउड स्पीकर बजाने की प्रवृत्ति से भी बचना चाहिए। l

कितना सही है कानून को अपने हाथ में लेना

समाज में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के हाथों है। देश की कानून व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्तर पर हो अथवा जिला स्तर पर, शांति-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। अर्थात पुलिस प्रशासन समाज की कानून व्यवस्था का ख्याल रखे और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था का। पुलिस विभाग इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बना है। पुलिस इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वह तय नियमों का पालन करते हुए समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखे और किसी को भी तय नियम से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। हमारे देश के संविधान ने किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया

है। किसी भी घटना अथवा दुर्घटना के दौरान उत्पन्न अप्रिय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जनता को पुलिस प्रशासन की मदद लेनी ही पड़ेगी। ऐसी किसी भी घटना-दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचना देना नागारिक जिम्मेदारी की सूची में शामिल है। बाद में यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य बनाए अथवा उस पर नियंत्रण पाए। किसी भी घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने से जनता की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जनता को पुलिस की मदद-सहयोग भी करना पड़ेगा।

हाल के दिनों में समाज में एक गलत परिपाटी देखने को मिल रही है। कुछ उद्दंड युवक हमेशा किसी न किसी बहाने समाज में अशांति फैलाने की फिराक में लगे रहते हैं। इसके पीछे राजनीतिक, धार्मिक और निजी हित भी देखने को मिलते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों जनता द्वारा कानून को अपने हाथों में लेने की घटना देखने को मिल रही है। कुछ शैतानी प्रवृत्ति के लोग किसी भी निरीह ग्रामीण पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे न सिर्फ गांव से बाहर खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं, बल्कि उसका खेत-जमीन तक हड़प जाते हैं। कई स्थानों पर तो गुस्साई भीड़ द्वारा चोरी के आरोप में निर्दोष व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या तक किए जाने की घटना घट चुकी है। छोटी-छोटी गलतियों पर जनता द्वारा किसी की भी बेरहम पिटाई कर देना आम बात हो चली है। मगर एक बार रुककर यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या जनता को इस तरह से कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार है। ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत से लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए निरीह, निरपराध व्यक्ति को इस प्रकार के आरोपों में फंसा कर अपना हित साध लेते हैं। यह बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है कि किसी ने अगर कोई गलती अथवा अपराध किया है तो उसका फैसला करने के लिए कानून और अदालत हैं। ऐसे अपराधियों को पकड़ने-गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, थाने-चौकी हैं तो बजाए आरोपी को पुलिस के हवाले करने के उस पर टूट पड़ना कितना उचित है। जनता यदि आरोपी को पुलिस के हवाले कर देती है तो इससे

समाज में शांति-व्यवस्था कायम होने का मार्ग प्रशस्त होता है, मगर इसके विपरीत यदि कोई कानून को ही अपने हाथों में लेता है, इससे समाज में जारी शांति प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आदिम युग में ऐसा होता था, जब कुछ लोग अथवा कबीले का प्रमुख व्यक्ति किसी के गुण-दोष फैसला करता था, मगर अब वक्त बदल गया है। बदलते वक्त के साथ जंगलराज सभ्य समाज में बदल चुका है, लिहाजा सभी को सामाजिक-कानूनी नियमों का पालन करना ही होगा। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि किसी उद्दंड व्यक्ति के उकसावे में आकर आम व्यक्ति भी तैश में आकर कानून को अपने हाथों में ले लेता है। हमें ऐसे उद्दंड लोगों के उकसावे में आने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपराधिक किस्म के लोग हमेशा आम लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसा कर खुद पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में पुलिसिया कार्रवाई होने पर वह लोग तो साफ बच निकल जाते हैं और साधारण-सा आम आदमी पुलिस की चंगुल में फंस जाता है। पुलिस के सामने ही किसी को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई करना, पुलिस पर पत्थर फेंकना, आरोपी के घर को जला डालने जैसी घटनाओं को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता और न ही ऐसा करने वालों को निर्दोषी करार दिया जा सकता है। यह भी सही है कि कभी-कभी उत्तेजित भीड़ के आगे पुलिसकर्मी खुद को असहाय महसूस करते हैं, कभी-कभी भीड़ के गुस्से का भी शिकार बनते हैं। इसके बावजूद इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि कानून को हाथों में लेने की प्रवृत्ति समाज की शांति और कानून व्यवस्था पर कुठाराघात है और सभी को ऐसी उत्तेजित प्रवृति से बचना चाहिए। ।

फ्रांसिसी कलाकार ने किया 'पारिजात हरण' का मंचन

संस्कृति का कोई तय दायरा नहीं होता है। किसी एक समाज के लोगों के सांस्कृतिक जीवन की तस्वीर उनकी संस्कृति में ही नजर आती है। इस तस्वीर का न तो कोई निर्दिष्ट रूप रहता है और न ही वर्ण। संस्कृति को जिस रूप में ढाला जाता है, यह उसी रूप में नजर आती है। संस्कृति में हर एक माहौल में घुलमिल जाने की क्षमता होती है और इसके लिए भाषा की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दुनिया के एक कोने के लोग दूसरे कोने में बसे लोगों की संस्कृति को बड़ी आसानी व सहजता के साथ आत्मसात कर लेते हैं। संस्कृति के आदान-प्रदान के लिए बहुत आत्मीयता और लगाव की जरूरत पड़ती है। जहां आत्मीयता नहीं है, वहां संस्कृति का विकास होना असंभव है। इसलिए संस्कृति से जुड़े लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर वहां के सांस्कृतिक माहौल के साथ घुल-मिल जाने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। विगत 3 जनवरी को गुवाहाटी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में ये सारी बातें सच होती प्रतीत हुईं।

नेपोलियन के देश फ्रांस से आए कलाकारों के एक दल ने कलाक्षेत्र के मंच पर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के अंकिया भाओना 'पारिजात हरण' का मंचन किया। हजारों दर्शकों की उपस्थिति में फ्रांस के कलाकारों ने अपनी जिस अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया, वह बेजोड़, अद्‌भुत और प्रशंसनीय था। फ्रांस के बेलियास इंस्टिट्यूट पेरिस से आए कलकारों ने फ्रांसीसी भाषा में 'पारिजात हरण' का मंचन कर दर्शकों से तालियां व वाहवाही बटोरी। इन सभी विदेशी अभिनेता-अभिनेत्रियों की पोशाक-परिधान से लेकर वार्तालाप करने की भंगिमा तक काबिले तारीफ थी। असमिया भाषा-संस्कृति के साथ दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होने के बावजूद इन कलाकारों का अभिनय देखने के बाद कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि ये सारे कलाकार असमिया संस्कृति से पूरी तरह अनजान और अनभिज्ञ हैं। 'पारिजात हरण' में विभिन्न चरित्र निभाने वालों की सूची में सूत्रधार के रूप में मेथिस डेल्टन, श्रीकृष्ण के रूप में बेनेदेटो, रुक्मिणी के रूप में फेनी, सत्यभामा के रूप में मेईटे, देवर्षि नारद के रूप में मालो, देवराज इंद्र के रूप में फेत्रिश, इंद्र की पत्नी शशि के रूप में पेट्रियाश, नरकासुर के रूप में निकोस डेल्टन, गरूड़ पक्षी के रूप में जेभियार जेलाइश के नाम शामिल हैं।

शिक्षाविद् डॉ. दयानंद पाठक ने 'पारिजात हरण' नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि नाट्य दल के लोगों ने बाद में इस नाटक को अंग्रेजी से फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉ. भवानंद बरबायन ने इन सभी विदेशी कलाकारों को प्रशिक्षण दिया। अंकिया भाओना के अंत में उन्होंने दर्शकों से सभी कलाकारों का परिचय कराया। भाओना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विदेशी कलाकारों द्वारा स्वदेशी रूप में सज-धजकर दर्शकों के सामने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करना था।

श्रीमंत शंकरदेव की रचना को विश्व फलक पर स्थापित करने का इसे एक शानदार प्रयास कहा जा सकता है। श्रीमंत शंकरदेव की रचना को विश्व फलक पर स्थापित करने के नाम पर हम चाहे कितना भी हो-हल्ला मचाएं, मगर जब तक इस काम को पूरा करने के लिए हम स्वयं आगे बढ़कर नहीं

आएंगे तब तक यह काम होना असंभव है। मगर विदेशी कलाकार इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से अपने-अपने देशों में भाओना का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं और ऐसा होने से ही भाओना का विश्व फलक तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ने इसके मार्ग को खोलने का काम किया है। इस मामले में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र समाज के सचिव नारायण कुंवर, कलाक्षेत्र के उपाध्यक्ष सूर्य हजारिका आदि के प्रयासों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कलाक्षेत्र के साथ-साथ दर्शकों को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में जो भूमिका निभाई, उसकी प्रशंसा के लिए शब्द भी कम हैं। इससे पहले भी बहुत से महानुरागियों ने इस प्रकार की कोशिशें की थीं, मगर वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे, मगर इस बार उक्त व्यक्तियों की जी तोड़ मेहनत और कोशिशों के दम पर कोशिश कामयाब रही। वैसे भी देखा जाए तो अच्छी चीजों के प्रति हर एक व्यक्ति के मन में आदर-सम्मान की भावना होती है, बस जरूरत उस चीज को सही स्थान-मंच पर स्थापित करने की रहती है। अंकिया भाओना के मामले में भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर ही उभरकर सामने आती है। श्रीमंत शंकरदेव की रचनाओं को विश्व पटल पर ले जाने से पहले हमारी नई पीढ़ी को इनके प्रति आकर्षित करना होगा और ऐसा आसानी से किया भी जा सकता है। किसी के कह देने भर से नहीं होगा कि महापुरुष की रचनाओं को आज तक असम से बाहर स्थापित नहीं किया जा सका। सवाल उठता है-यह काम करेगा कौन? क्या सिर्फ सरकार, हम-आप यह कार्य क्यों नहीं कर सकते। इन विदेशी कलाकारों की ओर मदद-सहयोग का यदि हाथ बढ़ाया जाए, अभिनय करने का मौका दिया जाए तो यही कलाकार विदेशी भूमि पर भाओना का मंचन कर इसे विश्व पटल पर स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। भाषा की भिन्नता कभी भी दूरी की वजह नहीं बन सकती, फ्रांस के कलाकारों ने अंकिया भाओना का सफल प्रदर्शन कर इस बात को साबित कर दिया है। ।

पठानकोट पर हमला और भारत-पाक वार्ता

पठानकोट स्थित भारतीय वायु सेना के ठिकाने पर हाल ही में किए गए हमले में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के शामिल होने की प्रमाण सहित जानकारी ने एक बार फिर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पूरे विश्व के सामने उजागर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान का औचक रूप से किए गए दोस्ताना दौरे के जवाब में पाक सेना की शह पर पठानकोट में किया गया आतंकी हमला वाकई में सन्न कर देने वाला था। इस हमले में भले ही सभी आतंकी मारे गए हों, मगर यह भारत के विश्वास और आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की भी कलई को खोलकर रख दिया है। मुंबई कांड जैसी घटना के बाद भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन द्वारा भारत में बेरोकटोक घुस कर वायुसेना के ठिकाने पर हमला करने जैसी घटना भी कम गंभीर मामला नहीं है। वायुसेना, नौसेना और थल सेना के ठिकाने भारत के अति संवेदनशील, बेहद सुरक्षित प्राण केंद्र स्वरूप हैं। ऐसे ठिकानों पर ही सेना की रणनीति बनाई जाती है और सैन्य अभ्यास भी किए जाते हैं। देश की जल-नभ-थल सुरक्षा व्यवस्था इन्हीं ठिकानों से नियंत्रित होती है। लिहाजा वायु सेना के ठिकाने पर हमला होना, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गहरी एवं गंभीर चूक मानी जानी चाहिए। इस हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह साबित करने की कोशिशों में लगा है कि पठानकोट का हमला पाकिस्तान की शह पर किया गया हमला है। भारत की कूटनीति और भारी दबाव के बाद पाकिस्तान ने भारत को उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन देने के साथ ही पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक उच्च स्तरीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन कर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मगर आखिरकार इस जांच का नतीजा क्या निकलेगा, इसका सभी को भान है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को

लेकर इस जांच दल का गठन कर पाकिस्तान पूरे विश्व से सहानुभूति और विश्वास हासिल करना चाहता है। इधर पाकिस्तान पर अमरीका का भी भारी दबाव रहने के कारण वह इस मामले को हल्के से लेने की गलती नहीं करना चाहेगा।

1947 में धर्म के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म होने के बाद से ही पाक सरकार और वहां की सेना का भारत विरोधी रुख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अथवा राष्ट्रहित में जब भी पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंध सामान्य व मधुर बनाने की कोशिश करता है पाक सेना उसे नाकाम करने में जुट जाती है। पाक सेना द्वारा कभी आतंकियों के माध्यम से कश्मीर में युद्ध जैसे हालात पैदा किए जाते हैं तो कभी बम धमाकों द्वारा लोगों को दहशत में डालने की कोशिशें होती हैं। भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर धमाकों की आवाज गूंजना आम बात है। कारगिल युद्ध के मंजर को देश आज भी भूला नहीं है। अभी कारगिल युद्ध की यादें धुंधली भी नहीं हुई थीं कि पठानकोट कांड हो गया। इसके बावजूद भारत सरकार हमेशा ही चुप्पी साधे रहती है। भारत की इसी सहनशीलता को लगता है पाकिस्तान ने इसकी कमजोरी समझ लिया है। इसीलिए पाक हमेशा मौके की ताक में रहता है और जब भी मौका मिलता है अपनी घटिया करतूतों से बाज नहीं आता।

कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से अचानक पाकिस्तान पहुंचकर पूरी दुनिया को भौंचक्का कर दिया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में श्री मोदी की मेहमान के रूप में अचानक से हुई उपस्थिति पर पूरे विश्व के लोगों ने राहत की सांस ली थी। और तो और अमरीका के राष्ट्रपति ने भी मोदी के इस दौरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता प्रकट की थी, मगर भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे पर एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी जात दिखाने से बाज नहीं आया और एक बार फिर भारत की इज्जत पर हमला करने की जुर्रत कर बैठा। पठानकोट हमले की घटना से लगता है भारत ने कोई सीख नहीं ली। हमेशा अपनी चाणक्य नीति के अनुसार नरम पंथ पर चलते हुए भारत पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाता आया है, इस नीति का भारत को कुछ फायदा भी मिला है। मगर देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से कब जाकर बाज आता है। l

श्रीमंत शंकरदेव का योगदान अविस्मरणीय

असमिया समाज-संस्कृति में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जो अमूल्य व असीम योगदान है वह सदियों से अविस्मरणीय रहा है और भविष्य में भी रहेगा। महापुरुष की हर एक रचना ने असमिया जाति को एक नई गति देने का काम किया है। जब असमिया जाति साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद पिछड़ी हुई थी, उस दौरान श्रीमंत शंकरदेव ने कालजयी ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने बरगीत की रचना कर असमिया समाज को भक्ति रस का स्वादन कराया। इसी भक्ति रस ने आगे चलकर असमिया जाति को एकजुट करने का काम किया। बरगीतों के प्रचार-प्रसार से लोगों में हत्या-हिंसा की भावनाएं खत्म होने लगीं। इस तरह श्रीमंत शंकरदेव ने असमिया समाज को एक शक्तिशाली समाज के रूप में प्रतिष्ठित ही नहीं किया, बल्कि विश्व पटल पर भी असमिया जाति को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का काम किया। उनकी विचारधारा आज भी जारी है। चूंकि असमिया समाज के हर एक स्पंदन को महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव महसूस कर पाए थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं कीं, जिन्हें सभी तबके के लोग स्वीकार कर पाएं।

महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को सिर्फ साहित्य के दायरे में ही कैद कर नहीं रखा जा सकता। वे एक समाज सुधारक-संस्कारक भी थे। समाज में व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राज्य के इस छोर से उस छोर तक का भ्रमण किया था। राज्य के विभिन्न स्थानों पर सत्र स्थापित कर वहां भक्ति रस की गंगा प्रवाहित कर उन्होंने लोगों के मन को साफ-स्वच्छ करने का काम किया था। इसी का नतीजा था कि बाद में असमिया समाज ने सिर्फ एक नई गति ही हासिल नहीं की, बल्कि समाज में संकीर्णता की भावना भी काफी हद तक कम हो गई। श्रीमंत शंकरदेव ने अपनी विचारधारा की जिस मजबूत डोर से असमिया समाज को बांधकर रखने का काम किया था, आज उसी समाज

को कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, समाज के विभिन्न लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना और समन्यव की डोर भी टूटने की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में यह चिंतन किए जाने की जरूरत है कि समाज की मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। मगर इस बिंदु पर विचार करने के लिए लगता है कि किसी के पास भी वक्त नहीं है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए कुछ लोग समाज में विभाजन लाने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक हितों के लिए समाज का विभाजन किए जाने के बावजूद कुछ नि:स्वार्थ लोगों के चलते असमिया समाज आज भी अटूट है और कोई भी इसे ध्वस्त नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में श्रीमंत शंकरदेव की वाणी के प्रचार-प्रसार की जरूरत और भी बढ़ गई है। समाज को यदि एकजुट रखना है तो नई पीढ़ी के बीच पूरे विस्तार और व्यापकता के साथ श्रीमंत शंकरदेव की वाणी और आदर्शों का प्रचार-प्रसार करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ श्रीमंत शंकरदेव के आदर्शों के दम पर असमिया समाज को विभाजित किए जाने से रोका जा सकता है। उन्होंने आपसी भाईचारे की डोर को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए थे, आज के माहौल में वैसे कदम उठाए जाने की बेहद जरूरत है। नामघर के माध्यम से प्रतिदिन नाम प्रसंग, भाओना के जरिए आज भी सभी को एकजुट किया जा सकता है। क्योंकि विज्ञान की चमक की ओर मनुष्य कितना ही आकर्षित क्यों न हो जाए, धर्म की अनुभूति से वह स्वयं को अलग नहीं कर पाया है।

भाओना ने हमारे समाज में एक अलग ही स्थान हासिल कर रखा है। भाओना के प्रति हर एक असमिया व्यक्ति के मन में एक तरह की कमजोरी रहती है। भाओना शब्द आते ही सभी के मन में एक प्रकार का हिलोर उठने लगता है। असमिया समाज के लोग भले ही लाख व्यस्त हों, भाओना का नाम सुनते ही भाओना देखने-सुनने से खुद को रोक नहीं पाते। भाओना से सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन ही होता है, ऐसी बात नहीं है। यह लोगों को नीति-ज्ञान की शिक्षा भी देता है। भाओना असमिया संस्कृति को एक नई दिशा देने का काम करता है। इसीलिए आजकल विभिन्न जाति-जनजाति के लोगों के बीच शांति-सद्भावना की डोर को मजबूत करने के लिए भाओना का प्रदर्शन होने लगा है। हमें इसी धारा को और अधिक शक्तिशाली करने का काम करना है। ।

लोक विश्वास-परंपराओं के बीच में बोहाग बिहू

विश्व भर में किसी-न-किसी नाम से लोक विश्वास अथवा पुरातन परंपरा के अनुसार कोई-न-कोई पर्व-उत्सव मनाने की परिपाटी सदियों से चलती आ रही है। ऐसे उत्सव के साथ कोई-न-कोई कहानी अथवा लोक विश्वास जरूर जुड़ा होता है। इसी के आधार पर उत्सव का रूपरंग, खानपान, पोशाक-परिधान, नृत्य-गीत आदि तय किए जाते हैं। विज्ञान की विकास यात्रा में शामिल रहने के बावजूद कोई भी लोक विश्वास को नकार नहीं सकता। भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण संस्कारों पर टिकी है, लिहाजा ऐसे उत्सव के साथ लोक विश्वास का जुड़ा रहना स्वाभाविक है। असमिया संस्कृति को प्रकाशमय करके रखने वाला बोहाग बिहू को लेकर भी कई लोक कथाएं-लोक विश्वास प्रचलित हैं। असम में कृषि आधारित उत्सव का शुभारंभ बोहाग बिहू अर्थात रंगाली बिहू से होता है और इसका समापन माघ बिहू अर्थात भोगाली बिहू से होता है। रंगाली-भोगाली बिहू उत्सव कृषि पर आधारित होने के कारण ही इनके साथ भूमि, अग्नि और गौ-पूजा जैसे पहलू जुड़े हैं। इन उत्सवों का स्वरूप असमिया जाति को एक सहज-सरल हृदयवाली जाति के रूप में स्थापित करता है।

हमारे देश में बिना गाय के कृषि कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से यदि देखा जाय तो देश की पूरी ग्रामीण आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था की धुरी ही गाय रही है। खेत में हल जोतने से लेकर फसल को ढोकर खेत से खलिहान तक ले जाने, घर की सफाई-पुताई करने, यहां तक की बच्चों के लिए दूध का प्रबंध करने तक में गाय ही सबसे आगे रहती है। इसलिए बोहाग बिहू का पहला दिन गोरू बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय-मवेशियों को नदी-पुखरी, खाल-बिल में नहलाने के बाद उनको दो विशेष प्रकार के पेड़ के पत्तों से हल्के-हल्के ढंग से मारा जाता है। लोक विश्वास

है कि ऐसे पत्तों से मवेशियों के शरीर पर मारने से मच्छर तथा अन्य पतंगे उनको नहीं काटते। बोहाग बिहू के मौके पर गांव के लोग तरह-तरह के पत्तेदार साग विशेष तौर पर खाते हैं। कहीं-कहीं तो सौ प्रकार के साग खाने का भी उल्लेख मिलता है। वैसे यह नहीं बताया गया है कि बोहाग बिहू पर किस प्रकार का साग खाना चाहिए। मगर आमतौर पर घर-गांव में जो साग उपलब्ध होता है, वहीं खाया जाता है।

इन सब लोक विश्वासों के बीच बोहाग बिहू एक नए स्वरूप में न सिर्फ असमवासियों के, बल्कि विश्ववासियों के सामने है। आज विश्व का कोई भी ऐसा देश बचा नहीं होगा, जहां एक भी असमिया प्रवासी न रहता हो और बोहाग बिहू न मनाया जाता हो। बदलते वक्त के साथ कृषि आधारित बोहाग बिहू ने भी अपना रूप-रंग बदला है। खेत-खलिहानों से निकलकर बिहू मंच तक पहुंच गया है। इस प्रक्रिया में कई दशक लगे हैं। अब बोहाग बिहू सिर्फ कृषि कार्य करने वालों तक ही सिमटकर नहीं रह गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही नहाने-खिलाने के लिए गाय न मिले, अमरीका में भले ही भारतीय गांवों में पाए जाने वाले साग के दर्शन न हों, इन सब के बावजूद वहां बोहाग बिहू जरूर मनाया जाता है। बोहाग बिहू में असम का बिहू नृत्य भी होता है, बिहू गीत और ढोल-पेपा भी। वक्त भले अपने सफर को तय करते-करते इस मुकाम तक पहुंच गया हो, मगर इस दौर में भी बोहाग बिहू ने अपना आकर्षण-गरिमा को नहीं खोया है। असमिया युवती-महिला चाहे वह किसी भी उम्र, परिवेश की क्यों न हो, अपने मेखला चादर को वर्षों तक इसलिए सहेजकर रखती है ताकि साल दर साल बोहाग बिहू में वह मेखला पहनकर ढोल-पेपा की धुन पर थिरक सके। बैशाख का महीना आते ही हमारे युवाओं में भी बोहागी का नशा सर चढ़कर बोलने लगा है। विभिन्न बिहू तोलियों में रात-रात भर चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपने चहेते गायक-गायिकाओं के गीतों पर थिरकती युवाओं की टोली को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है, बोहागी बिहू का आकर्षण कल भी था, आज भी है और आने वाले कल को भी रहेगा। 1

वेलेंटाइन डे के नाम पर अपसंस्कृति को बढ़ावा देना कितना सही

संत वैलेंटाइन की स्मृति में पूरे विश्व भर में 14 फरवरी का दिन 'वैलेंटाइन डे' के रूप में मनाया जाता है। मगर देखने में आया है कि कई देशों में वैलेंटाइन डे मनाने के नाम पर अपसंस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे देशों की सूची में भारत भी शामिल है। आज की युवा पीढ़ी की नजर में वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ प्रेमी-प्रेमिकाओं का एक-दूसरे के आलिंगन में दिन गुजारना भर रह गया है। मगर इस दिवस का मतलब प्रेमी-प्रेमिकाओं का नदी किनारे एकांत में बैठकर दिन गुजरना भर नहीं है। संत वैलेंटाइन का प्रेम पवित्र था। उन्होंने स्वर्गीय प्रेम की अनुभूति के साथ इसे एक नया स्वरूप प्रदान किया था। भारतीय संस्कृति में हम बजाए ऐसे दिन मनाने के सलीम-अनारकली, ऊषा-अनिरुद्ध, नल-दमयंती और सती जयमती के प्रेम को ही अधिक महत्व देते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो किसी दूसरे की संस्कृति को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर अपनी संस्कृति को तिलांजलि देकर अन्य की संस्कृति को अपनाने की बात कम से कम मेरे तो गले नहीं उतरती। यह बात भले ही पीड़ादायक लगे, मगर सच है कि आज की पीढ़ी संत वैलेंटाइन के बारे में जितना अधिक जानती है, सलीम-अनारकली, ऊषा-अनिरुद्ध के बारे में उतनी ही कम जानकारी रखती है।

आज की युवा पीढ़ी की नजर में वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच कीमती उपहारों का आदान-प्रदान ही रह गया है। इस दिन न सिर्फ आपस में कीमती उपहारों का लेन-देन होता है, बल्कि होटल, रेस्टूरेंट आदि में पार्टी, लंच-डिनर का दौर चलता है। युवा जोड़े, पार्क, नदी-समुद्र किनारे हाथों में हाथ डालकर अपना वक्त गुजारते हुए वैलेंटाइन डे के अर्थ को सार्थक करते प्रतीक होते हैं। कई दशक पहले विदेशों से आयात की गई इस

संस्कृति ने हमारे देश में प्रेम को भी एक बाजार बनाकर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने वैलेंटाइन डे पर उपहार दिए जाने वाली सामग्रियों से बाजार को भर दिया है। भारतीय सोच और संस्कृति बताती है कि प्रेम किसी एक खास दिन प्रदर्शित की जाने वाली भावना नहीं है और न ही यह किसी दिखावटी वस्तु अथवा अनुभूति का नाम है। प्रेम का मतलब कीमती उपहार देने-लेने का ही नाम नहीं है। इसी प्रकार के लेनदेन की मानसिकता ने भारतीय प्रेम की गहराई और महत्व को काफी कम कर दिया है। देखा जाए तो भोगवादी सोच और सभ्यता ने प्रेम जैसी स्वर्गीय अनुभूति को भी बाजार के स्वरूप में ढाल दिया है। अब तो ऐसा भी देखने को मिलने लगा है कि बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने अथवा प्रचार-प्रसार करने के लिए वैलेंटाइन डे का सहारा लेने लगी हैं। इन कंपनियों के प्रचार को देखकर ऐसा लगता है मानो वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ कीमती उपहारों तक ही सीमित है। ऐसी कंपनियां लेकिन सलीम-अनारकली, ऊषा-अनिरूद्ध, सती जयमती की कहानियों का प्रचार नहीं करतीं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा कर उन्हें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। आज से 15 साल पहले हमारे असम में वैलेंटाइन डे के बारे में जानकारी रखने वाले मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे। मगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रचार-प्रसार का असर देखिए कि आज के दिन 90 प्रतिशत युवा इस दिन के बारे में न सिर्फ आप-हमसे अधिक जानकारी रखते हैं, बल्कि महीने भर पहले से इसकी तैयारी में भी जुट जाते हैं। इनकी तैयारियों में गुलाब फूल खरीदने से लेकर महंगे उपहारों की सूची बनाना तक शामिल होता है। कोई अपने प्रियतम को कितना महंगा उपहार देता है, इसी बात पर युवाओं में एक प्रकार की होड़-सी लग जाती है। इसी प्रकार की मानसिकता की वजह से वैलेंटाइन डे वाले दिन अपराध तथा असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। हम वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं करते, मगर इस विशेष दिवस को मनाने के नाम पर अपसंस्कृति को हवा मिले, यह भी नहीं चाहते। यह सही है कि आज के दिन किसी के पास भी यह देखने का वक्त नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम समाज को किसी दूसरे ही रास्ते पर धकेल दें। ।

कम सिहरनकारी नहीं है हमारे सैनिकों की वीरता की दास्तां

अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए सरहदों पर तैनात हमारे वीर सैनिकों को जिंदगी के सारे सुख नसीब नहीं हैं। प्यार-स्नेह, परिवार-बच्चे, समाज-रिश्तेदारों को छोड़ तपते रेगिस्तान से लेकर बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात इस सैनिकों के बारे में सोचने और उनकी पीड़ा को दिल की गहराई से महसूस करने का किसके पास समय है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन-रात अटल प्रहरी बनकर खड़े रहने वाले सैनिकों के बारे में हमने भला कब सोचा है। जब हम उत्सव-त्योहार के आनंद-उमंग में डूबे रहते हैं, ठीक उसी वक्त देश की सरहद पर तैनात सीमा प्रहरी दुश्मन देश के सैनिकों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। जब हम कड़ाके की सर्द रातों में गर्म रजाई में दुबके होते हैं, तब कोई एक जवान हिमालय पर गिरती बर्फ के बीच अटल खड़ा रहता है। हमारे सुख की नींद के लिए अपनी रातों को कुर्बान करने वाले इन सैनिकों के प्रति हम इतने असंवेदनशील क्यों हैं? बर्फ से ढंकी हिमालय की ऊंची-ऊंची चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का जितना भी मान-सम्मान किया जाए, कम है।

पिछले दिनों विश्व के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ खिसकने से 30 फुट नीचे दबे रहने के बाद जीवित निकाले गए लांस नायक हनमंथप्पा कोप्पाड ने जिस वीरता के साथ मौत से लड़ाई लड़ी और बाद में

हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए, उस वीर गाथा को जमाना हमेशा गाता-सुनाता रहेगा। 29 हजार फुट ऊंचे सियाचिन में 30 फुट बर्फ के नीचे दबे रहने वाले हनमंथप्पा को सेना ने किस तरह से निकाला और आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल तक लाया गया, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। तीन दिन बर्फ के नीचे दबे होने के बाद भी हनमंथप्पा का जिंदा निकल आना भी किसी अचरज से कम नहीं है।

भारतीय सैनिकों को क्यों अदम्य साहसी कहा जाता है, सियाचिन की घटना ने इसको एक बार फिर साबित कर दिया। विगत 3 फरवरी को भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के निकट सियाचिन में तैनाती के समय प्रचंड हिमपात की वजह से सेना की 19वीं मद्रास रेजीमेंट के10 जवान बर्फ के नीचे दब गए थे। सेना ने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि बर्फ के नीचे दबे 10 सैनिकों में से किसी को जिंदा भी निकाला जा सकेगा। मगर सेना के सभी अनुमानों को झूठा सबित कर माइनस 55 डिग्री सेल्सियस ठंड में पत्थर बनी बर्फ के बीच हनमंथप्पा को निकाला गया। इस घटना को अलौकिक घटना भी कहा जा सकता है।

छह दिन तक बर्फ के नीचे दबे अपने साथी को जिंदा निकालने के बाद सेना अपने बाकी बचे साथियों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर जुट गई। बचाव कार्यों के लिए चिकित्सा दलों को भेजा गया और आपात स्थिति में उपचार के लिए पोस्ट स्थापित कर दी गई। विशेष बचाव श्वानों को भी मौके पर भेजा गया था। अधिकारियों के अनुसार, डॉट और मीशा नाम के कुत्तों ने जबर्दस्त काम किया। ग्लेशियर में विशेष रूप से प्रशिक्षित दलों समेत 150 से अधिक प्रशिक्षित सैनिकों को भी भेजा गया। हनमंथप्पा को बचाने के लिए चिकित्सकों ने अपने हर संभव प्रयास किए, मगर इस वीर जवान को बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग की दुआएं भी बेअसर साबित हुईं और हनमंथप्पा हमेशा-हमेशा के लिए चले गए। आने वाले कल को हम अपने बच्चों को उनकी वीरता की कहानी जरूर सुनाएंगे। ।

मगर दिल हार गए पाक-बांग्लादेशी खिलाड़ी

खेल के मैदान में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होती। खेल के मैदान में तो सिर्फ आपसी प्रेम और भाईचारा ही होता है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भाग लेने आए पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ी तथा अन्य अधिकारी कुछ इस तरह का ही पैगाम लेकर अपने वतन लौटे हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के प्रति असमिया लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं है। यह बात कहने-सुनने में भले ही अप्रिय लगे, लेकिन सच है कि इन पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ अभी भी धड़ल्ले से जारी है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगी कंटीली बाड़ भी इस घुसपैठ को नहीं रोक पाई है। हमेशा बांग्लादेश को तिरस्कार और उपेक्षा की नजर से देखने वालों ने खेलों में भाग लेने आए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपने सीने से लगाकर रखा और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिखाया कि खेल के माध्यम से लोगों के दिल की दूरियों को कम किया जा सकता है। प्यार-दुलार को दो देश की सीमाओं के दायरे में कैद करके नहीं रखा जा सकता। किसी भी देश का नागरिक दूसरे देश के लोगों के लिए घृणा का पात्र नहीं हो सकता। भौगोलिक सीमा और अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए हर देश कोशिशें करता है। राजनीतिक तौर पर ऐसी समस्याओं को जिंदा भी रखा जाता है। किसी देश के कुछ लोग किसी तय मुद्दे-मसले पर दूसरे देश का विरोध करते हैं अथवा उसके खिलाफ विद्रोह की घोषणा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि विद्रोह करने वाले देश के सारे नागारिकों का समर्थन विद्रोहियों के साथ है। पाकिस्तान में जिस प्रकार भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं तो भारत को प्यार करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। यही कारण है कि भारत की गीता जैसी युवती कई साल तक पाकिस्तान में पूरी तरह सुरक्षित रहने के बाद वापस अपने वतन लौट आने में सफल रही। पाकिस्तान में ऐसा एक युवक भी है, जिसने क्रिकेटर विराट कोहली ने जब ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ा था,

तब मारे खुशी के उसने अपने घर की छत पर तिरंगा फहरा दिया था। इस अपराध के कारण इन दिनों वह पाकिस्तानी जेल की सलाखों के पीछे है। इधर, भारत में भी ऐसे नेता-संगठनों की संख्या कम नहीं है, जो खाते भारत का हैं, गाते पाकिस्तान का हैं। कश्मीर के मुद्दे पर भारत के बदले पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादी नेता-संगठनों के बारे में भला कौन नहीं जानता। इसका अर्थ यह भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के सभी लोग इन अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को असम में जो आदर-सम्मान और अपनापन मिला, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। असम के प्यार-स्नेह, अपनेपन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भाव विभोर कर दिया था। अपने वतन लौटते वक्त हर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एक ही बात कही, मौका मिला तो वह लोग फिर असम आना चाहेंगे। असम में महिलाओं की स्वाधीनता और खुलापन देख पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी तो भौंचक्की रह गईं। पाक खिलाड़ियों ने असमवासियों को उदार दिल, सहज-सरल और सभी से मिल-जुलकर रहने वाला बताया। यह भी कहा जा सकता है कि असम में मिले सम्मान और स्नेह ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मन में भारत के प्रति जो गलत धारणा थी, उसे पूरी तरह से बदलकर रख दिया।

बांग्लादेशी घुसपैठ असम के लिए सबसे गंभीर और ज्वलंत समस्या रही है। घुसपैठ आज भी जारी है और इस वजह से असम के मूल निवासियों केसमक्ष अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को बनाए रखने का संकट पैदा हो गया है। इस स्थिति में जब दक्षिण एशियाई खेलों में शिरकत कर रहे बांग्लादेश के खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरे, उन्हें असम के दर्शकों का भरपूर समर्थन और अपनापन मिला। खेल के बाद भी बांग्लादेश की महिला खिलाड़ियों ने खुलकर गुवाहाटी की सैर की और जमकर खरीदादारी भी की। असमिया जाति के आतिथ्य को देख बांग्लादेश-पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी तो सब आत्मविभोर हो उठी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि असमिया समाज में महिलाओं को इतना आदर-इतना सम्मान और इतना प्यार हासिल है। इस खेल में हिस्सा लेने के बाद अपने देश को लौटा हर एक खिलाड़ी-अधिकारी एक गतिशील असमिया समाज की छवि अपने साथ लेकर गया है। एक ऐसे गतिशील समाज की छवि जहां हर क्षेत्र में महिला-पुरुष को बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान हासिल है। ।

एकता में पिरोती है असम साहित्य सभा

असम में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति के मन में असम साहित्य सभा के प्रति अगाध सम्मान और विश्वास है। असमिया जाति की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली असम साहित्य सभा अपने जन्मकाल से ही असम की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अग्रणी भूमिका निभाती आई है। असमवासी साहित्य सभा को अन्य संगठनों की अपेक्षा एक अलग ही सम्मान भरे भाव से देखते हैं। सभी के मन में असम साहित्य सभा के प्रति गहरा लगाव और प्रेम होने की वजह से ही आज भी इसका बड़े दायरे में फैलाव देखने को मिलता है। असम साहित्य सभा एक ऐसा संयुक्त मंच है, जहां सभी को शामिल होने की इजाजत है। असम के हर एक क्षेत्र में असम साहित्य सभा का समान प्रभाव रहे, इसके लिए साहित्य सभा के अधिवेशन अलग-अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। सभी को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए और साहित्य जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी असम साहित्य सभा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में खामोशी के साथ काम करने वाले विशिष्ट साहित्यकारों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आयोजित पुरस्कार अथवा सम्मान प्रदान कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आम जनता की उपस्थिति से साहित्य सभा की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

असम साहित्य सभा द्वारा शुरू किए गए 'वासुदेव जालान स्मृति पुरस्कार' समारोह में मैं भी शामिल था, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त न होने के बावजूद असमिया साहित्य-संस्कृति के प्रति मेरे पिताजी के मन में गहरा अनुराग था। साहित्य चर्चा करने वाले साहित्यकार-साहित्य प्रेमियों के साथ उनके गहरे संबंध थे। अबकी बार शिवसागर महाविद्यालय के असमिया विभाग के अवकाशप्राप्त प्रधान अध्यापक, साहित्यकार तथा शोधकर्ता नाहेंद्र पादुन को वासुदेव जालान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवसागर युवा दल के थानेश्वर दत्त स्मृति प्रेक्षागृह में शिवसागर साहित्य सभा के सहयोग तथा असम साहित्य सभा के तत्वावधान में विगत 28 फरवरी को उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में साहित्य सभा अध्यक्ष डॉ. ध्रुवज्योति बोरा, पूर्व अध्यक्ष इमरान शाह, साहित्यकार डॉ. अनिल सइकिया के अलावा और भी कई वरिष्ठ-विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में श्री पादुन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सहज-सरल और बहुत ही नम्र स्वभाव के श्री पादुम से एक बार मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति उनको भूल नहीं सकता। भाषा-साहित्य के प्रकांड पंडित, निरहंकारी श्री पादुन की बातें सुनकर कभी भी मन नहीं भरता। उनकी सरल भाषा में उनके सरल हृदय के भी दर्शन मिलते हैं। वासुदेव पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस जिम्मेदारी के साथ वे साहित्य सभा के साथ जुड़े हैं, उस जिम्मेदारी को लेकर वे सदैव जागरूक और सतर्क रहते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार हासिल करने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी के भाव के चलते साहित्य सृजन का काम किया है। उन्होंने शोध को भाषा के विकास के लिए जरूरी बताया और कहा कि इसलिए वे असमिया भाषा साहित्य के साथ ही मिसिंग समाज-संस्कृति के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। दुमदुमा के फिलोबाड़ी में 19 मार्च, 1941 को जन्मे श्री पादुन ने फिलोबाड़ी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से असमिया विभाग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। बाद में वे साहित्य सृजन के काम में लग गए। 1

विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों ?

विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना असम माध्यमिक शिक्षा परिषद (सेबा) के लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसी कोई न कोई गड़बड़ी जरूर होती है, जिसका सीधा संबंध मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से होता है। मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के गाय के खाने और बरसात के पानी में उत्तर पुस्तिकाओं के नष्ट होने जैसी घटनाएं घट चुकी हैं। इसके बावजूद सेबा ने लगता है कोई सीख नहीं ली है। जोरहाट में मैट्रिक परीक्षाओं की छह हजार उत्तर पुस्तिकाओं के जल जाने की घटना तो कम-से-कम सेबा के ऐसे ही किसी लापरवाही भरे कदम की ओर इशारा करती है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी मिल जाएंगे, जिनका भविष्य मैट्रिक की परीक्षा के एडमिट कार्ड में भयंकर गलती, समय पर एडमिट नहीं मिलने अथवा सही ढंग से पंजीकारण नहीं होने की वजह से चौपट हो गया। परीक्षा फल में उम्मीद के अनुसार अंक नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों के आत्महत्या तक कर लेने की घटनाएं घट चुकी हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्निरीक्षण के दौरान नंबर देने अथवा जोड़ने में बड़ी गलतियों की घटनाएं आम हैं। ऐसा भी देखने को मिला है कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्निरीक्षण के बाद विद्यार्थी का नाम टॉप-10 की सूची में शामिल होने योग्य पाया गया। ये तो सेबा के कुछ ही कर्मों का लेखा-जोखा है, यदि ऐसे कर्मों की सूची बनाई जाए तो निश्चय ही वह बहुत लंबी सूची होगी। इतना कुछ होने के बाद भी लगता है कि सेबा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होने के मूड में नहीं है और उसके इसी रवैए ने राज्य के बुद्धिजीवियों को चिंतित कर रखा है।

वैसे यदि देखा जाए तो हमारे असम में कोई भी घटना घट सकती है। इतनी बड़ी और गंभीर घटना होने के बाद सेबा के सचिव अथवा संबंधित प्रबंधन गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर सिर्फ अपना ही बचाव करते नजर आते हैं। ऐसी घटनाएं यदि हर साल होती रहीं तो सेबा के प्रति आम जनता की भावना कैसी

होगी, इसका बड़ी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा जगत के पहले पायदान पर ही यदि मुंह के बल गिरना पड़े तो उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, सेबा प्रबंधन को इस बात को तनिक संवेदना के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेबा केअध्यक्ष हर साल परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित कराने की घोषणा करते हैं, मगर उनकी ऐसी घोषणाएं सच साबित नहीं हो पातीं। लगता है सेबा द्वारा आयोजित परीक्षाएं अब केवल एक मजाक बनकर रह गई हैं। सही मायने में जोरहाट में कितनी उत्तर पुस्तिका जली, इसका सही आंकड़ा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और संभवत: यह आंकड़ा सार्वजनिक होगा भी नहीं। सही आंकड़ा लोगों के सामने प्रस्तुत न कर सेबा फिर एक बार विद्यार्थियों के भविष्य को अंधेरे में धकेल देना चाहता है। एक बार परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी को एक महीने बाद फिर उसी विषय की परीक्षा देनी पड़े तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इस बारे में भी सेबा को एक बार सोचना चाहिए।

सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेबा उचित कदम नहीं उठा सकता क्या? इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि सेबा के पास सही सोच-सही योजना का अभाव है। इस तरह की घटनाएं क्या लगातार घटती ही रहेंगी या इन पर लगाम भी लगेगी।

सही मायने में यदि देखा जाए तो समय और तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए सेबा को भी अपने अंदर भारी बदलाव लाने होंगे। सेबा को विद्यार्थियों के पंजीकारण के समय से ही सतर्क होना होगा। विद्यार्थियों केनाम, पता आदि सही हों इसकेलिए जरूरी है कि डाटा बेस तैयार करने वालों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाए। प्रश्नपत्र परीक्षा पूर्व खुले बाजार में उपलब्ध न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी निष्ठावान अधिकारियों को लेनी ही होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका ले जाने वाले वाहनों के अलावा उन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे, जहां उत्तर पुस्तिकाओं को रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े हर छोटे-बड़े अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का अहसास होना होगा। यह तो मानकर चलना ही चाहिए कि शिक्षा विभाग में काम करना सिर्फ सरकारी नौकरी करना भर नहीं है। ।

होली का मतलब ही है रंगों का उत्सव, लेकिन...

रंगों का त्योहार है होली। हमारे देश में जाति-धर्म-वर्ण की परिधि से बाहर निकलकर सभी लोग इस त्योहार में शामिल होते हैं और एक-दूसरे के साथ होली की खुशियां बांटते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले वसंत ऋतु के उत्सवों में होली ही एक ऐसा उत्सव है, जिसमें सतरंगी छटा देखने को मिलती है। भगवान श्रीकृष्ण वसंत काल में अपनी गोपियों के साथ होली खेला करते थे। होली के त्योहार की शुरुआत कब से हुई, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा रचित ग्रंथों में होली का उल्लेख मिलता है। विशेषकर हिंदू धर्म के लोग होली का त्योहार प्रमुखता के साथ मनाते हैं। यह त्योहार भले ही एक दूसरे पर रंग डालने का हो, मगर सभी पूरी पवित्रता के साथ इसमें शामिल होते हैं। आज कल होली के नाम पर एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकने और रसायनयुक्त रंग लगाने की परंपरा चल पड़ी है। इस वजह से जहां एक ओर होली की पवित्रता-शालीनता प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों की धार्मिक भावनाओं पर भी चोट पड़ रही है।

धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि होली के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण का ही ध्यान-भजन किया जाना चाहिए। असमिया संस्कृति में होली का एक विशेष

स्थान है। निचली असम के बरपेटा में होली के गीतों को जिस तरह सुरीली और लयबद्ध आवाज में गाया जाता है, उसकी मधुरता और मादकता बिना अपने कानों से सुने महसूस नहीं की जा सकती। जवान-बूढ़े सभी होली के गीत गाने-सुनने केकार्यक्रम में शामिल होते हैं और जो होली के गीत गाते हैं, वे तो भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम में एकाकार हो जाते हैं। प्रभु चरणों में समर्पित इन होली गीतों से तन-मन दोनों ही पुलकित हो उठते हैं। वैसे तो असम के लगभग सभी शहर-नगर-गांवों में होली का त्योहार मनाया जाता है, मगर बरपेटा-बटद्रवा आदि स्थानों में होली के विराट रूप को देखा जा सकता है। राज्य भर में जगह-जगह स्थापित सत्रों के आसपास होली का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है।

वैसे भी होली का पवित्र त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। मगर आज केआधुनिक दौर में कुछ असामाजिक तत्वों की करतूतों की वजह से इस त्योहार की पवित्रता धूमिल पड़ती जा रही है। रंग के नाम पर बाजार में ऐसे रासायनिक पदार्थ मिले रंग बिकते हैं, जो त्वचा को सीधे-सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो होली खेलने के तुरंत बाद त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे हानिकारक रंग बेचने वाले दुकानदारों पर यदि कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में लोग त्वचा खराब होने के डर से होली खेलना छोड़ देंगे। लोगों ने यदि होली खेलना छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा, जब रंगों के त्योहार होली की चर्चा सिर्फ किताबों में ही सिमटकर रह जाएगी। मालूम हो कि प्राचीन काल में प्राकृतिक रूप से रंग तैयार किए जाते थे। ऐसे रंग बनाने के लिए गुलाब, टेसू, चमेली आदि फूलों का उपयोग किया जाता था और वसंत पंचमी के बाद से ही लोग होली की तैयारियों में जुट जाते थे। बाद में धीरे-धीरे होली का स्वरूप बिगड़ने लगा। रंगों की जगह कीचड़ और तारकोल ने ले ली तथा प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले रंग रासायनिक पदार्थ मिलाकर बनाए जाने लगे। इन्हीं कारणों के चलते होली के दिन रंग लगाने-लगवाने वालों की संख्या साल-दर साल कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सभी को रंगों के त्योहार होली के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस बारे में चिंतन किया जाना चाहिए। l

गुजर गई होली, अब सफाई की बारी

रंगों का त्योहार होली एक बार फिर लोगों के तन-मन को गुलाबी कर गुजर गया। लंबे समय से होली की तैयारियों में लगे नगरवासियों ने जमकर होली का आनंद उठाया। एक-दूसरे पर रंग-गुलाल लगाया। गलबाहियां की, चरण छुए और आशीर्वाद भी लिया। अब सफाई की बारी की है। सड़क-दीवारों पर लगे रंगों को धोना है, दीवारों पर जमी गुलाल को उड़ाना है और साथ ही साथ अपने शरीर पर लगे सुर्ख लाल रंग को भी साबुन से रगड़-रगड़ कर छुड़ाना है। इसी के साथ-साथ हमारे समाने अपने मन पर लगे राग-द्वेष, नफरत-क्रोध के उस काले रंग को भी उतारना है, जो गुजरते समय के साथ-साथ गहरा ही होता जा रहा है। हम यदि अपने दिलों को साफ नहीं कर पाए, समाज को अलगाववाद-जातिवाद, अमीर-गरीब के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाए तो इस बार भी होली का त्योहार बेमकसद ही रहेगा।

होली के मौके पर पहले जिस प्रकार की सामाजिक एकता, संस्कृति और जुड़ाव के दर्शन होते थे, आज के दौर में वैसे मंजर देखने को नहीं मिलते। समाज की होली, गली-मोहल्ले की होली फ्लैट-सोसायटी की होली बनकर रह गई है। फ्लैट के चार परिवार मिलकर ही आपस में रंग-गुलाल लगा लेते हैं और हो गई होली। भले ही समय के साथ होली मनाने का तरीका बदल जाए, मगर होली का अर्थ, होली मनाने का महत्व नहीं बदलना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए होली एक-दूसरे पर रंग लगाने का ही त्योहार नहीं है। दिल पर लगी

कालिमा को धो डालने का भी त्योहार है।

बदलते वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। होली का मतलब भी अब पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले तो वसंत पंचमी के दिन से ही होली के चंग बजने लगते थे, लोग रातों को होली के गीत गाते-सुनते नजर आते थे। समाज के गणमान्य लोगों के घरों में होली का रंग घोला जाता था। गोठ-मिलन समारोह का भी दौर चलता रहता था। वही होली अब सिमटते-सिमटते दो दिन की होली ही रह गई है। पहले लोग मस्ती में एक-दूसरे को रंग लगाते थे, अब परंपरा का निर्वाह करने के लिए रंग लगाते हैं। वह तो भला हो इन टीवी सीरियल वालों का, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय त्योहारों को जिंदा कर दिया है, चाहे उनमें आधुनिकता का तड़का ही क्यों न लगा हो। युवा पीढ़ी इन सीरियल को देख भारतीय त्योहारों के बारे में जानना चाहती है, उनको समझना चाहती है।

युवाओं की इस जिज्ञासा को समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है। युवाओं को यह बताया जाना चाहिए कि होली का सामाजिक, धार्मिक और इसके साथ-साथ वैज्ञानिक महत्व भी क्या है। हमारे युवा विज्ञान की भाषा सबसे पहले व प्रभावशाली ढंग से समझते हैं। होली के बहाने ही हम सभी को समाज के अलावा अपने तन-मन को स्वच्छ साफ करने का महत्व तो समझा ही सकते हैं। होली को हमने जिस उत्साह-उमंग के साथ मनाया और विदा किया, उसी उत्साह और उमंग के साथ हमें स्वच्छता के मंत्र को अपने जीवन में उतारना होगा। स्वच्छता एक ऐसा मंत्र है, जिसको किसी भी पर्व-त्योहार के मौके पर उच्चारित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि होली के गुजर जाने के बाद सभी लोग अपने शरीर, घर के फर्श, दीवार, दरवाजे पर लगे रंगों को उतारने की कवायद में जुट गए होंगे। चलिए, इस बार कम-से-कम सप्ताह में एक दिन मोहल्ले की गली-सड़कों की सफाई करने का प्रण करें। मुझे यकीन है, आपको स्वच्छता अभियान में लगे देख उन लोगों को शर्म जरूर आएगी, जो जाने-अनजाने चारों ओर गंदगी फैलाने में लगे रहते हैं। दोस्तो! होली तो गुजर गई, अब सफाई की बारी है। क्या मेरी तरह आप लोग भी तैयार हैं अपने अंदर की और घर के बाहर की सफाई करने के लिए? ।

मतदान करें, यह आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है

लोकतंत्र में जनता अर्थात मतदाताओं को राजा का दर्जा दिया गया है। मतदान के द्वारा ही हम किसी राजनीतिक पार्टी अथवा राजनेता को देश के शासन की जिम्मेदारी सौंपते हैं। चुनाव के दौरान हर एक मतदाता को अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई जनप्रतिनिधि मतदाताओं के उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करता है तो पांच साल बाद मतदाता उसे सत्ता से बेदखल भी कर देते हैं। लिहाजा जनप्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की पसंद-नापंसद का ध्यान रखना ही पड़ता है। मतदान नागारिक का एक संवैधानिक अधिकार है और कोई भी इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है।

मगर कोई मतदाता यदि अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है तो? यह सवाल बहुत गंभीर है। स्वाधीनता के बाद से आज तक हमारे देश में सौ फीसदी मतदान नहीं हुआ है। आजकल तो देखने में आता है कि शहरी इलाके के पढ़े-लिखे लोग मतदान वाले दिन छुट्टी मनाते हैं और ग्रामीण इलाके का मतदाता अपना जरूरी से जरूरी काम छोड़ मतदान के लिए जरूर जाता है। इस स्थिति को सुखद तो नहीं कहा जा सकता। कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति यदि बिना किसी ठोस वजह के अपना वोट नहीं डालता है तो एक तरह से वह लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है। हमारे देश में हर एक मतदाता के वोट का मूल्य बराबर है। इतिहास गवाह है एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अपने वोट के दम पर ही हम जनप्रतिनिधि तो क्या सरकार तक को बदल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है ग्रामीण मतदाता की तरह

शहरी बाबू भी अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलें, मतदान केंद्र तक पहुंचें और कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान करना हर एक भारतीय नागरिक का पवित्र कर्तव्य ही नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। कहना न होगा आज की युवा पीढ़ी देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी है। देशहित से जुड़े सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे युवा आगे रहते हैं। हमें वह सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी ताकि हमारे देश का युवा मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। विश्व के सबसे युवा देश की युवा पीढ़ी यदि मतदान से वंचित रहती है तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।

4 अप्रैल और 11 अप्रैल को असम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर लोकतंत्र का पर्व कहे जाने वाला 'चुनाव' हमारे दरवाजे पर खड़ा है। इस चुनाव की सार्थकता तभी है, जब अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमें वैसे मतदाताओं को भी जागरूक बनाना होगा, जो मतदान के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपना वोट डालने के साथ-साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी भी वोट डाले। राज्य के अंदरुनी हिस्सों में रहने वाले लोगों में आज भी मतदान के प्रति जागरूकता का अभाव दिखता है। यही वजह है कि अंदरूनी इलाके के मतदाता बड़ी आसानी से किसी के भी प्रलोभन में आ जाते हैं। भोले-भाले ग्रामीणों को ऐसे प्रलोभन से बचाने के लिए हमें इनके बीच जाकर काम करना होगा। गांव वालों को उनके वोट के महत्व और ताकत के बारे में बताना होगा। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, समझना होगा हमारे लोकतंत्र में अब भी कमी है। लोग जब तक अपने मतदान के प्रति जागरूक नहीं होते, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना संभव नहीं दिखता। मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार, चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, सरकारी, गैर-सरकारी संगठन सभी को आगे बढ़कर आना होगा। इस अभियान में हम सभी को अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। चलिए अबकी बार मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश 'भारत' का नागारिक होने पर गर्व करें। l

प्रतिभा विकास में कितने रीयल हैं रियलिटी शो

'रियलिटी शो' आजकल एक आम शब्द है। गाहे बगाहे किसी-न-किसी वजह से यह शब्द सुनने को मिल ही जाता है। बड़ी तेजी से बढ़ते टीवी चैनलों के प्रचार-प्रसार ने 'रियलिटी शो' को लोगों के दिलों की गहराई में इस कदर जगह बना दी है कि लाख चाहने पर भी उसे मिटाया नहीं जा सकता। रियलिटी शो की इसी लोकप्रियता ने कुछ लोगों के लिए इसे एक व्यापार बन दिया है, ऐसे लोग दर्शक-श्रोताओं की इस दुखती रग को पहचान गए हैं और उसका फायदा उठाने में चूक भी नहीं रह रहे हैं। आजकल विभिन्न टीवी चैनलों पर गीत, संगीत, नृत्य सहित विभिन्न कलाओं पर आधारित रियलिटी शो देखने को मिलते हैं। ऐसे रियलिटी शो के पीछे एक व्यापारिक नजरिया भी छिपा है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है और कोई इनकार कर भी नहीं सकता। रियलिटी शो में भाग लेने वाले कलाकारों की प्रतिभा के मूल्यांकन के लिए वोटिंग के नाम पर मंगाए जाने वाले एसएमएस के पीछे कौन-सा व्यापारिक हित छिपा है, यह सभी के सामने स्पष्ट है। रियलिटी शो को लेकर अलग-अलग पक्षों की अलग-अलग दलीलें हैं और बाहर से यदि इन दलीलों को सुना-समझा जाए तो दोनों पक्षों की दलील ही सही लगती है।

रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले अथवा हिस्सा लेने की चाहत रखने वाले अधिकांश बच्चे एक प्रकार की मानसिक पीड़ा के दौर में नजर आते हैं। लगभग सभी टीवी चैनलों में रियलिटी शो प्रसारित होने के फलस्वरूप सिर्फ बच्चे ही क्यों, युवा भी इस बीमारी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। माता-पिता अपने बच्चों को सभी क्षेत्र में पारंगत बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई-लिखाई से लेकर हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करे। इसके लिए समाज एवं अभिभावकों में एक तरह की अस्वाथ्यकर प्रतियोगिता शुरू हो गई है।

अभिभावक भी अपने बच्चों को नृत्य, संगीत, गीत, चित्रकला, खेलकूद आदि सभी में निपुण बनाना चाहते हैं और इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि आखिरकार उनके बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। जरूरी नहीं कि किसी बच्चे की नृत्य, संगीत, गीत, चित्रकला में ही रुचि हो। उसकी रुचि मार्शल आर्ट, पर्वतारोहण अथवा अन्य क्षेत्र में भी हो सकती है। एक तरह से यदि देखा जाए तो माता-पिता अपने बच्चे में वह सारी सफलताएं देखना चाहते हैं, जिनको हासिल करने में वे स्वयं असफल रहे हैं। अपने इन अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने के चक्कर में अभिभावक न सिर्फ बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि उनके अंदर छिपी प्रतिभा का सही ढंग से विकास ही नहीं होने देते। इस प्रकार के रियलिटी शो में सफल होने के लिए योग्यता के साथ-साथ ढेर सारे एसएमएस की भी जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि योग्यता होने के बावजूद एसएमएस की गिनती के आधार पर जज एक प्रतिभाशाली कलाकार को खारिज कर देते हैं। बाद में उसी कलाकार को किसी अन्य बड़े मंच पर श्रेष्ठ कलाकार का खिताब लेते हुए देखा जाता है। कहीं-कहीं प्रतियोगिता के जजों के फैसले को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं।

यहां इस बात का भी जिक्र करना होगा कि देश के महान गायक लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार आदि ने कभी भी रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लिया। साथ-ही-साथ यह बात भी सही है कि रियलिटी शो ने देश को कई चमकते सितारे, गायक दिए हैं। इसके साथ-साथ इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि रियलिटी शो में विजयी घोषित किए गए कलाकार साल-दो साल में ही अपनी चमक, अपनी पहचान खो देते हैं। दूसरे राज्यों की बात छोड़ भी दें तो हमारे असम में ही ऐसी कई प्रतिभाएं समय के अंधेरों में गुम हो चुकी हैं। अनामिका चौधरी, देबजीत साहा, जयदेव, डिंपी सोनोवाल जैसे रियलिटी शो के कलाकारों को हम कितना याद रख पाए हैं, जबकि इन्हीं सितारों ने एक समय पूरे असम को पागल कर रखा था। हमें एक बात समझनी होगी रियलिटी शो मनोरंजन का मंच तो हो सकते हैं, मगर प्रतिभा को परखने का अंतिम विकल्प कभी नहीं बन सकते। l

ब्रिटेन के शाही दंपति का काजीरंगा भ्रमण

शाही दंपति ब्रिटेन के राजकुमार ड्यूक ऑफ कैंब्रिज प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी राजकुमारी केट मिडल्टन ने अपने काजीरंगा भ्रमण के दौरान असमिया कला-संस्कृति को आत्मसात करने की कोशिशों का जो शानदार उदहारण प्रस्तुत किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। गले में पहनाए गए फुलाम गामोछा से लेकर गगना हाथों में लेने तक के संपूर्ण घटनाक्रम को राज्यवासियों ने बड़े ही गौर से देखा और असमिया संस्कृति के प्रति शाही दंपति के मन में हिलोर मारते अपार अनुराग को महसूस भी किया। शाही दंपति विगत 12 अप्रैल को एक विशेष विमान द्वारा तेजपुर के शालिनीबाड़ी हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उसकी अगवानी के लिए पहले ही मौजूद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और उनकी पत्नी डॉली गोगोई ने दोनों का असमिया परंपरा के अनुसार चेलेंग-गामोछा आदि पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। राजकुमार-राजकुमारी ने वहां असमिया परंपरागत व्यंजन पीठा, पोना, लड्डू आदि का स्वाद चखा। मुख्यमंत्री से मिले उपहारों को स्वयं अपने हाथों में उठाकर अपनी गाड़ी तक ले जाना और काजीरंगा पहुंचने पर उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने कमरे में रखना असमिया संस्कृति के प्रति शाही दंपति के सम्मान को ही दर्शाता है। आमतौर पर यदि देखा जाए तो यह बात कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर सूक्ष्मता से यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें ब्रिटेन के राजकुमार ड्यूक ऑफ कैंब्रिज प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी राजकुमारी केट मिडल्टन की विशाल हृदयता तो नजर आती ही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन के ही पूर्व राजाओं ने कभी हमारे देश पर राज भी किया था। उसी देश के भ्रमण पर आए शाही दंपति ने अपने व्यवहार से यह साबित करने की कोशिश की कि भले ही उनकेपूर्वजों ने कभी किसी जमाने में भारत पर राज किया हो, मगर

उनके मन में भारतीय सभ्यता-संस्कृति के प्रति किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं था। तब ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भारतीय संपदाओं को ब्रिटिश ले जाना भर ही था और इसीलिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से भारत का शासन भार अपने हाथों में लिया। यह भी सही है कि ब्रिटेन राजनैतिक तौर पर भारत का दमन करना चाहता था, लेकिन भारत की सभ्यता-संस्कृति के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। ब्रिटेन के राजकुमार-राजकुमारी ने अपने असम भ्रमण के दौरान एक फिर इसी बात को स्थापित करने की कोशिश की है। शाही दंपति ने न सिर्फ हमेशा फुलाम गामोछा को अपने गले में डाले रखा, बल्कि बिहू नृत्य में हिस्सा लेते हुए गगना भी बजाया। कभी वह जमाना भी था, जब अंग्रेजों के राज में सूर्य अस्त नहीं होता था, इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी भी देश की सभ्यता-संस्कृति पर हमला नहीं किया।

असमिया समाज में बिहू के दिनों बड़ों से आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। लिहाजा एक मधुर माहौल में ब्रिटेन के राजकुमार-राजकुमारी ने गोरू बिहू के दिन बोकाखात के निकटवर्ती पानबाड़ी आदर्श गांव के नामघर में जाकर आशीर्वाद लिया। नामघर के दर्शन करते वक्त दोनों ने इसके धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। एक साधारण दंपति की तरह दोनों ने नामघर में उपस्थित अन्य भक्तों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान दोनों के आचरण-व्यवहार में कहीं से भी उनके शाही दंपति होने का अहसास नहीं हुआ। दोनों का यह भ्रमण सिर्फ नामघर तक ही सीमित नहीं रहा। वे पास के ही एक घर में गए और तांतघर में किस तरह कपड़ों की बुनाई की जाती है, इस बारे में वहां मौजूद महिला बुनकर के साथ विस्तार से चर्चा की। पानबाड़ी के वन्य जीव शोध एवं राहत केंद्र में जाकर दोनों ने एक गैंडे के बच्चे को दूध भी पिलाया। इसके अलावा उन्होंने निर्माणाधीन हाथी चिकित्सालय को भी देखा। कार्बी आंग्लोग के कोयला माटी में कार्बी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। ध्यान देने वाली बात है कि इस शाही भ्रमण के दौरान कहीं भी राजकुमार-राजकुमारी के शाही रुतबे के दर्शन नहीं हुए। अपने वतन लौटते-लौटते यह शाही जोड़ा हमें सिखा गया, एक दूसरे समाज के साथ किस तरह से मेलजोल बढ़ाया जा सकता है। l

रंगाली बिहू, प्रकृति का तांडव और बिहू मंच

असमिया में कहावत है बैशाख के महीने में आंधी (बरदैशिला) अपने मायके जाती है। असमवासियों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही असम के लोग बैशाख के महीने में आंधी-तूफान का कहर देखते-झेलते आए हैं। प्रकृति का यह कहर कितना भयावह और विध्वंसक हो सकता है, इसके उदहारणों की भी कमी नहीं है। बैशाख के महीने में आंधी जब अपनी मां के घर जाती है तो राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने गुजरने के विध्वंसक पद-चिन्ह छोड़ जाती है। पेड़ों में जब नए पत्तों में कोंपले फूटती हैं तो प्रकृति के मिजाज पर नजर और उसकी जानकारी रखने वाले गांव के लोगों को यह संकेत मिल जाता है कि आंधी-तूफान, बरसात-ओला वृष्टि के दिन आ गए। वैसे भी यह प्रकृति का नियम भी है। मगर इस बार रंगाली बिहू के मौके पर प्रकृति का ऐसा विध्वंसक रूप देखने को मिला, जैसा इससे पहले संभवत: कभी देखने को नहीं मिला होगा। इधर रंगाली बिहू प्रारंभ हुआ, उधर प्रकृति का तांडव नृत्य भी शुरू हो गया। पखवाड़े भर के आंधी-तूफान, बरसात-ओला वृष्टि ने ऊपरी असम के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। वज्रपात की वजह से एकाधिक लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। जगह-जगह टेलीफोन-बिजली के खंभे, पेड़ आदि उखड़ गए। बराकघाटी में लोगों के घरों की छतें उड़ गईं। देखने-ही-देखते सैकड़ों लोग बेघर हो गए। रंगाली बिहू वस्तुत: प्रकृति, मवेशी, पेड़-पौधे आदि को लेकर ही मनाया जाता है। प्रकृति के स्वरूप और सौंदर्य पर ही केंद्रित है रंगाली बिहू। प्रकृति का त्योहार कहे जाने वाले रंगाली बिहू के समय राज्य भर में बरपे प्राकृतिक कहर हमें यह संदेश देता है कि हमारी करनी और कथनी के बीच का फासला कितना बढ़ गया है। एक ओर तो हम रंगाली बिहू के पहले सात दिन गछ बिहू, गोरू बिहू, जेंग बिहू, गोहाईं बिहू आदि के नाम पर मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर हम बड़ी ही बेदर्दी से पेड़-पहाड़ आदि को काटने-ध्वस्त करने में लगे हैं। इस बार रंगाली

बिहू पर प्रकृति का जो कहर बरपा, वह हम मनुष्यों द्वारा प्रकृति पर किए जा रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया मात्र है। सभी जानते हैं कि प्रकृति की भी एक क्षमता होती है, जब वह क्षमता पार कर जाती है तो प्राकृतिक विध्वंश की संभावनाएं कई गुणा बढ़ जाती हैं। इस बार रंगाली बिहू पर प्रकृति ने दिखा दिया कि पेड़-पहाड़ की अंधाधुंध कटाई का दुष्परिणाम कितना भयावह हो सकता है।

आमतौर पर बोहाग बिहू के दिनों खेतों में बारिश की रिमझिम शुरू हो जाती है और चारों ओर हरियाली की चादर-सी बिछ जाती है। पेड़ों में फूटने वाली कोंपलें इंसान के दिलों को भी सतरंगी बना देती हैं। इसी माहौल में हमको ढोल, पेपा, गगना के मादक सुरों के बीच बिहू गीत सुनने और मादकता से भरपूर बिहू नृत्य देखने को मिलते हैं। सभी प्रकृति देवी की आराधना में मतवाले हो उठते हैं, मगर जब यही प्रकृति देवी अपना रौद्र रूप दिखाती है तो पल भर में उत्सव के माहौल को फीका कर जाती है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। प्रकृति के कहर के कारण महानगर सहित राज्य के कई हिस्सों में या तो बिहू के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े अथवा उन्हें रद्द करना पड़ा। बिहू के दिनों हुई भारी बरसात से राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और लाखों हेक्टेयर कृषि-भूमि, खड़ी फसल बाढ़ की कहर की भेंट चढ़ गई। विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर अपना जीवन निर्वाह करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान उठना पड़ा और देखते ही देखते रंगाली बिहू के उत्साह पर प्रकृति के कहर ने पानी फेर दिया। प्रकृति के इस कहर का नतीजा उन लोगों को सबसे अधिक भुगतना पड़ा, जो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के किनारे रहते हैं। बरसात की वजह से नदियों में आई बाढ़ और उस करण हुए भूकटाव की चपेट में आकर बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए और देखते ही देखते उनका सब कुछ नदी में समा गया। ऐसे लोगों के लिए रंगाली बिहू आनंद नहीं, विषाद का पैगाम लेकर आया। इतना कुछ होने के बावजूद असम के लोगों ने अभी से ही अगले बरस आने वाले रंगाली बिहू का इंतजार करना प्रारंभ कर दिया है। मगर इस साल हम सभी को यह संकल्प भी लेना होगा कि हम प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे और न ही किसी को काटने देंगे। पहाड़, जलाशय आदि का संरक्षण करेंगे ताकि अगले साल जब बैशाख के महीने में आंधी (बरदैशिला) अपने मायके जाए तो हम उसे खुशी-खुशी विदा कर सकें। ।

डायन के नाम पर हत्याओं का सिलसिला कब तक

हर एक घटना के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है, बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं होता। न घटना–न दुर्घटना। मगर हमारे समाज में आज भी ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं, जिनके पीछे छिपी वजहों पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। भले ही ऐसी घटनाओं के लिए अंधविश्वास को जिम्मेदार ठहराया जाता हो, मगर इसे पूरी तरह सच भी नहीं माना जा सकता। ऐसी ही घटनाओं की सूची में शामिल है राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी डायन के नाम पर की जाने वाली हत्याओं का सिलसिला। अंधविश्वास के नाम पर अपने निजी हितों को साधने के लिए ही इस प्रकार की अधिकांश हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। राज्य के अंदरुनी–अशिक्षित गांवों में अंधविश्वास के नाम पर गांव के निरीह व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आधुनिकता के इस दौर

में आज भी मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं।

अभी हाल ही में कोकराझाड़ जिले में डायन होने के शक में कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवक की हत्या कर उसके शव को जमीन में गाड़ दिया गया। जिले के विषमुरी पुलिस चौकी के अधीन काजलगांव में विगत 22 अप्रैल से लापता अचिंत बसुमतारी का शव बरामद होने के बाद मानवता को कलंकित कर देने वाला यह अध्याय एक बार फिर खुलकर सामने आया है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर इस बात को सभी के सामने ला दिया है कि बर्बरता ने अभी भी मानवता के दामन को छोड़ा नहीं है। अंधविश्वासियों द्वारा डायन करार देकर एक अबोध छात्र की भी हत्या की जा सकती है, यह बात गले नहीं उतरती। यहां इस बात कर भी उल्लेख करना जरूरी है कि वर्ष 2013 में भी गांव के कुछ लोगों ने अचिंत की मां पर डायन होने का संदेह कर उस पर भी अमानुषिक अत्याचार ढाए थे। सिर्फ यही नहीं, उसी साल 28 दिसंबर को गांव वालों ने एक सार्वजनिक सभा बुलाकर अचिंत के परिवार पर झूठे आरोप लगाकर 501 रुपए का जुर्माना भी वसूला था। इसके कुछ दिन बाद जब फिर से अचिंत की मां पर गांव वाले अत्याचार करने लगे तो वह अलग से घर लेकर रहने लगी। घटना वाली रात अचिंत का बड़ा भाई अपने ससुर के घर गया था, इसी बात का फायदा उठाते हुए गांव के कुछ लोग अचिंत पर टूट पड़े और उसकी हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया। इस बात को माना जा सकता है कि यह हत्या गांव के कुछ लोगों की सोची-समझी साजिश का नतीजा थी, मगर इस हत्या को डायन नाम के साथ जोड़ दिया गया। वैसे भी राज्य के जनजाति बहुल इलाकों में किसी से बदला चुकाना हो तो संबंधित व्यक्ति के डायन होने का संदेह प्रकट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। डायन करार देकर हत्या कर देने की घटना सिर्फ जनजाति इलाके में ही घटती है, ऐसी बात नहीं है। समाज के पढ़े-लिखे लोग भी कभी-कभी ऐसी घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। ऐसे लोगों का उद्देश्य डायन के नाम पर व्यक्ति विशेष की हत्या कर उसकी संपत्ति अथवा जमीन पर कब्जा जमाना भी रहता है। कुछ लोग किसी पुरानी रंजिश

का बदला चुकाने के लिए भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य के अनपढ़ और पिछड़े लोगों को आज तक सरकारी योजनाओं में शामिल नहीं किए जाने की वजह से ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हमारे राज्य में अब भी ऐसे कई अंदरुनी गांव हैं, जहां आज तक कोई चिकित्सक नहीं गया। गांव के बच्चों को स्कूल जाना हो तो 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। सरकारी चिकित्सालय और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से गांव के अनपढ़ लोगों को बीमारी के इलाज के लिए नीम हकीम अथवा झाड़फूंक करने वाले फकीर-कबीराज की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे ही झाड़फूंक करने वाले, ताबीज बनाने वाले किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ समाज के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कुछ लोग अपना हित साधने के लिए भी इन लोगों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। झाड़फूंक करने वाले, ताबीज बनाने वाले गांव के लोगों के मन में यह बात डाल देते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण ही गांव में बीमारी-महामारी फैल रही है अथवा गांव भर का बुरा हो रहा है।

ऐसी घटनाएं प्रकाश में आने के बाद जब इनका विरोध हो रहा था, ठीक तभी जोरहाट में डायन के नाम पर एक महिला पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। मगर ऐसी बहुत-सी घटनाएं सामने आती भी नहीं और गांव की गुमनाम गलियों में खोकर रह जाती हैं। ऐसी घटनाएं साबित करती हैं कि हम भले ही आधुनिकता, सभ्यता के ऊंच शिखर तक पहुंच गए हों, मगर अंधविश्वास ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। यदि हम सभी एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ खड़े न हुए तो डायन के नाम पर की जाने वाली हत्याओं का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। l

लोकतंत्र का प्रहरी होता है विपक्ष

लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत हद तक सरकारी नीतियां भी खास मायने रखती हैं। जनता पांच साल के अंतराल पर देश अथवा राज्य का शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, माना जाता है कि उस पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश मिला है। जिन पार्टियों को सत्ता संभालने का जनादेश नहीं मिलता, लोकतंत्र में वैसी पार्टियों की भी सरकार से कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ऐसे सांसद अथवा विधायकों की भी संसद या विधानसभाओं में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विपक्ष के निष्क्रिय होने पर सरकार का चरित्र और काम करने का तरीका लोकतंत्र से उलट किसी तानाशाह जैसा भी हो सकता है। यह एक विपक्ष ही है, जो सरकार को लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर काम करने पर मजबूर कर सकता है। उसी तरह सरकार की सफलता भी परोक्ष रूप से विपक्ष की भूमिका पर ही निर्भर करती है। विपक्ष जितना ताकतवर और प्रभावशाली होगा, सरकार की गलतियां और कमियों को लेकर भी संसद-विधानसभा में उसी तरह से हमला करेगा। इसलिए विपक्ष को लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया है कि सरकार अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने का काम करती है अथवा कभी-कभी अपने तुगलकी फरमान आम जनता पर लादने की कोशिश करती है। सरकार की इस बेजा कोशिश को नाकाम बनाने के लिए विपक्षी पार्टियां ऐसे मामलों को संसद से सड़क तक ले जा सकती हैं। इस तरह से एक जनमत गठन कर अथवा आंदोलन खड़ा कर सरकार को अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर सकती हैं। सरकारी अफसरशाही से लेकर नेता-मंत्रियों तक पर पैनी नजर रखकर विपक्ष भ्रष्टाचार-घोटालों पर पूरी तरह से रोक लगा सकता है। ऐसा तभी संभव है जब सरकार के सामने एक सक्षम, ताकतवार विपक्ष खड़ा हो, जिसे देख सरकार

हमेशा सर्तक रहे कि कहीं गलती से भी कोई गलती न हो जाए। इसीलिए हमारे देश अथवा राज्य के लिए एक सक्रिय सरकार की जितनी जरूरत है, एक सक्षम और ताकतवर विपक्ष की भी उतनी ही जरूरत है। विपक्ष यदि कमजोर होगा तो खामियाजा न सिर्फ देश को, बल्कि आम जनता तक को उठाना पड़ सकता है। एक ताकतवर विपक्ष सरकार को तख्त से उतारने तक की क्षमता रखता है। कभी-कभी तो विपक्ष के कारण सरकार को अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी है। इसीलिए देश की जनता सरकार के समानांतर एक ताकतवर विपक्ष खड़ा करने की चाहत रखती है।

इसी कड़ी में हम अगली 19 मई को होने वाले असम विधानसभा चुनाव की मतगणना की अग्रिम चर्चा कर सकते हैं। मतगणना के बाद जो भी पार्टी राज्य की बागडोर संभाले, असमवासी एक ताकतवर और स्थायी सरकार बनाने के साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि राज्य का विपक्ष भी सरकार से कम ताकतवर न हो। वैसे यदि हम पिछले पांच सालों में विपक्ष की भूमिका पर नजर डालें तो असम विधानसभा में विपक्षी पार्टियों की भूमिका बेहद कमजोर रही है। यही कारण था कि सरकार को अपनी मनचाही करने की छूट मिल गई। सरकार राज्य के विकास को भूल अपनों के ही आरोप-प्रत्यारोप में उलझ गई और विपक्ष भी इस स्थिति में लचर-बेबस नजर आया। विपक्ष जनता को यह बात समझाने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ कि उसने सरकार को जनसेवा के लिए चुना था और सरकार जनकल्याण छोड़ अपनों के ही बीच लड़ने-लड़ाने में लगी हुई है। नतीजा यह हुआ कि पिछले दो सालों में राज्य का विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस बार जनता फिर से ऐसी स्थिति का गवाह नहीं बनना चाहती। जनता चाहती है राज्य में ताकतवर सरकार हो, ताकतवर विपक्ष भी हमेशा तैयार रहे। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 67 और भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक हैं। पूरी दिल्ली विधानसभा पर 'आप' का राज है और तीन सदस्यीय विपक्ष की उपस्थिति तो नजर तक नहीं आती। असम की राजनीति, असम की जनता और असम की विधानसभा दिल्ली विधानसभा जैसी स्थिति से जरूर बचना चाहेगी, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत बनकर उभरेगा, जब विपक्ष मजबूत होगा। l

जागरूकता से ही बंद होगा ड्रग्स का अवैध धंधा

पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में ड्रग्स विरोधी अभियान बड़े ही जोर-शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान न सिर्फ भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए, बल्कि इस अवैध धंधे में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि ड्रग्स व्यापारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सेना से लेकर आम लोगों तक ने सहयोग दिया। निश्चय ही यह एक सराहनीय कार्य है। वैसे यदि आज के हालात पर नजर डाली जाए तो पूरा राज्य ही नशीले पदार्थों (ड्रग्स) का बाजार बना नजर आता है। युवा पीढ़ी नशे के गर्त में गिरती ही जा रही है। हाईस्कूल से लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तक नशे की लत के शिकार नजर आते हैं। समाज और परिवार के लिए यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, उसकी तस्वीर भी अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। ऐसे ड्रग्स की लत की वजह से एक पूरी पीढ़ी बर्बादी की कगार तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह से युवाओं

में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और एक छोटी-सी बात भी देखते-ही-देखते अंतिम फैसले की हद तक जा पहुंचती है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती की बढ़ती घटनाओं को ड्रग्स सेवन के बढ़ते प्रकोप के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसी भी खबर छनकर आई है कि समय पर ड्रग्स न मिलने पर स्कूल के विद्यार्थी ने आत्महत्या तक कर ली हो। देखा जाए तो ड्रग्स का सेवन सिर्फ समाज की ही नहीं, परिवारों की भी समस्या बन चुका है। हाल ही में दक्षिण शरणिया में एक मां द्वारा अपने नशेड़ी बेटे को पुलिस के हवाले कर देने की घटना इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करने के लिए काफी है।

कुछ साल पहले तक नशे का व्यापार पूर्वोत्तर के नगालैंड, मेघालय, मणिपुर आदि राज्यों तक ही फैला था और असम इस समस्या से काफी हद तक मुक्त था। मगर आज राज्य के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, गोलाघाट, शोणितपुर, कामरूप, मंगलदै, मोरीगांव, नलबाड़ी, कार्बी आंग्लोंग, धुबड़ी आदि जिलों में ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं की गतिविधियां उफान पर हैं। रातों-रात लखपति बनने का ख्वाब देने वाले ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क इतना ताकतवर है कि इसे नष्ट करना आम जनता के वश की बात नहीं है। ऐसे ड्रग्स माफिया का विरोध करने के चक्कर में बहुत से लोगों को अपनी जानें तक गंवानी पड़ी हैं। ऐसा भी देखने को मिला कि जांबाज पुलिस अधिकारी तक को इन ड्रग्स माफिया की गोली का शिकार होना पड़ा है। ऐसे में इन काले व्यापारियों के नेटवर्क को एक दिन में ही नष्ट कर पाना तो कतई संभव नहीं है। समाज के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ दो-चार दिन अभियान चलाकर ही असम को ड्रग्स सेवनकारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता। हाल ही में जनता के सहयोग से पुलिस ने भले ही कई ड्रग्स व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया हो, मगर उनको शह देने वाले असली अपराधियों को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक इस काले धंधे की कमर नहीं तोड़ी जा सकती। सिर्फ ड्रग्स व्यापारियों को ही गिरफ्तार करने से भी बात नहीं बनेगी, जब तक समाज का हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा। 1

ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देना होगा नई सरकार को

परिवर्तन के नाम पर राज्य के अधिकांश मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर जहां एक ओर भाजपा और उसकी मित्र दल की सरकार को सत्ता तक पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर 15 साल से सत्ता सुख भोग रही कांग्रेस को बड़ी ही बेरहमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले एक साल से राज्य भर में सिर्फ एक ही शब्द परिवर्तन सुनाई पड़ रहा था। जनता किस तरह का परिवर्तन चाहती है, इसकी व्याख्या भी अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपने-अपने तरीके से की। मगर यह भी उल्लेखनीय बात रही कि जनता ने पहली बार परिवर्तन को सामने रखकर वोट डाला। 19 मई को मतगणना के साथ-साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता किस प्रकार का परिवर्तन चाहती है।

आखिरकार राज्य में एक नई सरकार बन ही गई। भाजपा, बीपीएफ और अगप गठबंधन ने परिवर्तन लाने के नाम पर सबसे अधिक सीटें हासिल की और इस तरह भाजपा और उसके मित्र दलों की सरकार का भी गठन हो गया, जैसी सरकार को जनता सत्ता में देखना चाहती थी। अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। किसी भी सरकार के लिए जनता की उम्मीदों पर शत-प्रतिशत खरा उतर पाना संभव नहीं होता, मगर सरकार यदि जनता के मनचाहे काम करे तो उस सरकार को सफल कहा जा सकता है। सत्ता में बैठे नेता-मंत्री यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता उनसे क्या चाहती है, किस प्रकार का परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है। चुनाव पूर्व अधिकांश राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा जनता के सामने रखते हैं, यह अलग बात है कि चुनाव जीतने अथवा हारने के बाद सभी अपने चुनावी घोषणापत्र को भूल जाते हैं। चुनावी घोषणापत्र दरअसल उन वादों की एक सूची होती है, जो वादें राजनीतिक दल चुनाव के समय जनता से करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लंका में जाता है, वही रावण हो जाता है। मगर यह बात भी सच है कि उसी लंका में राम भक्त विभीषण भी रहा करता था। लिहाजा यह जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा, वह खराब ही होगा। सरकार को चलाने वाला प्रमुख व्यक्ति यदि जनहित में सही ढंग से काम करे तो उसके सहयोगियों को भी उसी तर्ज कर जनहित में काम करने ही पड़ते हैं। किसी भी पेड़ की हरियाली उसकी जड़ पर निर्भर करती है कि जड़ कितनी जीवंत है। इसी तरह से मुख्यमंत्री यदि ताकतवर हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लगातार जनहित में काम करे, जनता के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखे तो उसकी सरकार के अन्य मंत्री चाहकर भी अपनी सरकार के उद्देश्यों से दूर नहीं भाग सकते।

अबकी बार सत्ता में आई नई सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। राज्य में शांति-सद्भावना स्थापित करने से लेकर बेरोजगारी, भूकटाव, सीमा विवाद, घुसपैठ, सांस्कृतिक विकास के मसलों पर नई सरकार को सर्वाधिक ध्यान देना होगा। नई सरकार को राज्य की ज्वलंत समस्याओं से भी दो-चार होना होगा।

अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनसे किस तरह से निपटती है। क्षेत्र विशेष की समस्याओं की सूची बनाकर सरकार यदि उनके आधार पर काम करे तो जनता को इसका फायदा मिल सकता है। राज्य के कई इलाकों के लोग जंगली हाथियों के तांडव से परेशान हैं तो माजुली जैसे बहुत से क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के कटाव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस भूकटाव की वजह से अब तक राज्य की लाखों बीघा जमीन ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां लील चुकी हैं। बाढ़-भूकटाव की वजह से बेघर हुए लोगों को आज तक एक छोटा-सा आशियाना नसीब नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत से लोग-परिवार आज भी शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। विकास के इस दौर में अब भी असम में ऐसे बहुत से गांव बाकी हैं, जहां आज तक बिजली का एक बल्ब तक नहीं जला है। गांव में बिजली की लाइन तो दूर, एक खंभा तक नहीं गाड़ा गया है। हर साल बाढ़ जैसी तबाही में भारी नुकसान झेलने वाले हमारे असम में बहुत से गांव के लोग जंगल, नद-नालियों, झरनों और तालाबों के पानी से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे गांवों के लोग विशुद्ध पेयजल के लिए तरसते रहते हैं। राज्य में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की भी ऐसी स्थिति नहीं है, जिसको देख नई सरकार निश्चित हो सके। यातायात व्यवस्था के नाम पर सिर्फ शून्य होने की वजह से कई गांव के लोग अपने मरीजों को ठेलों में लादकर शहर तक लेकर जाते हैं। नई सरकार के सामने ऐसी समस्याओं की सूची कम लंबी नहीं है। लिहाजा आज से सरकार को जुट जाना होगा, इन सभी समस्याओं के समाधान कार्य में ताकि आगे चलकर मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सके। ।

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए सरकार

देश के वैसे राज्यों की यदि सूची बनाई जाए, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक गई हुई हैं तो उस सूची में असम का नाम भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा ट्रक रुकवाकर दस-दस रुपए की रिश्वत बटोरने से लेकर सरकारी महकमों में बैठे अधिकारियों द्वारा लाखों-करोड़ों रुपए के वारे-न्यारे करने की खबरें आम हैं। भ्रष्टाचार की इस बहती गंगोत्री में बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं, जिनकी ईमानदारी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। जहां तक राज्य भर में फैले सरकारी महकमों की बात है, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि इनमें से एक भी महकमा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अफसरशाही, लालफीताशाही आदि से मुक्त है। इस भ्रष्टाचार ने राज्य के विकास को जितना प्रभावित किया है, विकास-मार्ग पर जितने रोड़े अटकाए हैं, उतना किसी ने भी नहीं किया। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक

पहुंची हुई हैं कि बिना रिश्वत दिए एक छोटा-सा काम तक नहीं होता। सर्वानंद सोनोवाल की नई सरकार को इस स्थिति से निपटना है। चारों ओर पसरे भ्रष्टाचार के कीचड़ में स्वच्छता-ईमानदारी का कमल खिलाना है। वैसे भी भाजपा राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कहती आई है। अब भाजपा के हाथ मौका आया है कि वह इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठा सकती है।

हमारे यहां लोगों में आम धारणा है कि किसी सरकारी विभाग में काम करवाना हो तो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी से लेकर आला अधिकारी तक को रिश्वत देनी पड़ती है। इन अधिकारियों में जो सच्चे और ईमानदार होते हैं, उनको एक प्रकार से उपेक्षित कर दिया जाता है। ऐसे निष्ठावान और ईमानदार अधिकारियों को उनके ही साथी-सहयोगियों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता। कोई एक काम करवाना हो तो संबंधित फाइल को ऐसी जगह ले जाकर फंसा दिया जाता है, जहां बिना रिश्वत का चक्का लगाए फाइल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। ऐसे भ्रष्टाचार-रिश्वतखोरी को रोकने के लिए सरकार को सबसे पहले एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का यदि किसी भी प्रकार का सरकारी काम हो तो आवेदन करने के साथ ही उसे एक कंप्यूटरीकृत पर्ची दे दी जाए। उस पर्ची में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि सामने वाले का काम कब तक पूरा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था यदि संभव होती है तो उस व्यक्ति को टेबुल-टेबुल घूमने-भटकने अथवा भ्रष्ट अधिकारियों को चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आज के काम को सप्ताह भर और सप्ताह भर के काम को साल भर तक के लिए फेंक कर रखने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, लेकिन उसी काम के लिए भ्रष्टाचारियों की मुट्ठी गर्म कर दी जाए तो फिर सप्ताह का काम एक दिन में भी हो जाता है। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की ऐसी सोच को नया 'स्लिप सिस्टम' लागू कर बदला जा सकता है। इससे सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकता है। आज यदि सरकारी महकमे में कोई काम लेकर जाता है तो उससे खुलेआम रिश्वत मांगी जाती है और बड़ी ही बेशर्मी से यह भी बताया जाता है कि इस रिश्वत का हिस्सा अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक पहुंचता है। एक ही बात सुनते-सुनते अब

आम लोग भी यह मानने लगे हैं कि रिश्वत की गंगा अधिकारियों के घर से होकर मंत्रियों के आंगन तक जाती है। भ्रष्टाचार के कई उदाहरण तो लोगों को रोज खुलेआम बीच सड़क पर देखने को मिलते हैं। लोगों में विश्वास जगाना है तो सरकार को इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर सबसे पहले लगाम लगानी होगी, जो खुलेआम आम जनता के सामने और बड़ी ही बेशर्मी के साथ किए जाते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार की घटनाएं लोगों को यह संदेश देती हैं कि रिश्वतखोरी–भ्रष्टाचार अब देश, समाज के लिए कोई मसला नहीं रह गया है और सभी ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार बीच सड़क पर दिनदहाड़े होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सड़क के किनारे क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरों को भी लगाया जा सकता है। हो सकता 'कोई देख रहा है' का डर रिश्वतखोरी की घटना को कम करने में कामयाब साबित हो। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार की समस्या सरकार से कम, समाज से अधिक जुड़ी हुई है। लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए सरकार से पहले समाज के बुद्धिजीवी, युवा, महिला सभी को आगे निकलकर आना होगा। समाज के लोग यदि सिटी बस अथवा सिनेमा हॉल में लोगों का सिगरेट पीना बंद करवा सकते हैं तो चाहने पर भ्रष्टाचार का भी दम निकाल सकते हैं। सरकार जनता को विश्वास में ले और यह विश्वास भी दे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आगे बढ़ो, सरकार आपकेसाथ है तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। l

मैट्रिक के नतीजे और कालेजों में दाखिले की समस्याा

मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के नतीजे निकल चुकेहैं। पहले की तुलना में इस बार मैट्रिक का परीक्षा परिणाम और भी बेहतर हुआ है। मैट्रिक की टॉप-20 की सूची में कुल 232 मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। यह एक रिकॉर्ड है, जिनमें छात्रों के साथ-साथ छात्राओं ने भी बराबर की बाजी मारी है। असम माध्यमिक शिक्षा परिषद (सेबा) द्वारा संचालित परीक्षा को लेकर जारी विवादों के बीच मैट्रिक की परीक्षा में 62.79 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। परीक्षा के ही बीच आग में उत्तर पुस्तिकाओं के जल जाने अथवा प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने विद्यार्थियों के अलावा अभिभावकों को भी चिंतित कर रखा था, मगर शानदार परीक्षाफल ने ऐसे सारे विवादों को खत्म कर दिया।

इस बार 54,197 विद्यार्थियों ने पहली श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनमें से 5,449 विद्यार्थियों को डिस्टिंक्शन मिला और 11,703 विद्यार्थियों ने स्टार मार्क हासिल किए। जिलेवार यदि नजर फिराई जाए तो धेमाजी जिला सफलता के शीर्ष पर था। मैट्रिक की परीक्षा का यह शानदार नतीजा साबित करता है कि इन दिनों राज्य भर में प्रतियोगिता का एक दौर चल रहा है। राज्य के विद्यार्थी अब प्रतियोगिता के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजी विषय में राज्य के 26,406 विद्यार्थियों ने लेटर मार्क हासिल किए। अंग्रेजी में लेटर मार्क हासिल करने वाले सारे विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय केही हैं, ऐसी बात भी नहीं है। असमिया माध्यम में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का अंग्रेजी में लेटर अंक हासिल करना यह साबित करता है कि वे अंग्रेजी को भी उतना ही महत्व देते हैं, जितना असमिया विषय को। असमिया में 16,471 विद्यार्थियों के लेटर अंक हासिल करना इस बात की चुगली करता है कि अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बावजूद आज की युवा पीढ़ी में असमिया भाषा के प्रति मोह, सम्मान, लगाव तनिक भी कम नहीं हुआ है। असमिया

माध्यम के विद्यालय के बच्चे का पूरे राज्य भर में शीर्ष स्थान पर आना भी कम बड़ी बात नहीं है। जिनका यह कहना है कि असमिया माध्यम के विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने वाले अथवा असमिया भाषा में लिखने-पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, असमिया माध्यम के विद्यालय की यह सफलता उनकी बातों को झूठा साबित करती है। असमिया और अंग्रेजी भाषा को बराबर का महत्व देकर मैट्रिक के विद्यार्थियों ने समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह लोग वक्त के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं।

परीक्षा नतीजों की घोषणा के बाद अब अभिभावकों में अपने बच्चे को अगली कक्षा में दाखिला दिलाने की मारामारी लगी हुई है। यह मारामारी इस कारण भी है कि अबकी बार करीब 55 हजार विद्यार्थियों ने पहली श्रेणी में परीक्षा पास की है। इन सभी विद्यार्थियों के लिए ही स्कूल-महाविद्यालयों में पर्याप्त सीटें नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई का क्या होगा, जिन्होंने द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में परीक्षा पास की है। मैट्रिक की परीक्षा में निरंतर बढ़ती उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार को समुचित कदम उठाने ही होंगे। राज्य सरकार को चाहिए कि वे निजी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक अनुदान आदि देकर प्रोत्साहित करे ताकि शिक्षा के क्षेत्र का विकास किया जा सके। बदलते माहौल को देखकर इस बात को समझा जा सकता है कि शिक्षा क्षेत्र को विकसित करना एक अकेले राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से ही विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या से निपटा जा सकता है। सरकार को यह भी समझना होगा कि राज्य के मेधावी विद्यार्थियों का अन्य राज्यों में होने वाले पलायन और उच्च शिक्षा के नाम पर बाहरी राज्यों में जाने वाली सैकड़ों करोड़ों रुपए की धनराशि को रोकने के लिए सरकार को निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कदम बढ़ाना ही होगा। पिछले कई सालों से मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की फौज को उच्च शिक्षित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को शिक्षा की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। तभी जाकर राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के पलायन को रोका जा सकेगा। ।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में असम का गामोछा

इलाहाबाद में हाल ही में संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बार असम सभी के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा। कार्यकारिणी बैठक में शामिल सभी भाजपा नेताओं ने असम के परंरापगत फुलाम गामोछा को अपने गले में डालकर न सिर्फ असम का मान बढ़ाया, बल्कि अपने ही अंदाज में भाजपा को शानदार जीत दिलाने के लिए असमवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। यह पहला मौका था, जब भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किसी राज्य विशेष को इतना मान-सम्मान दिया है। विधानसभा चुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाकर असम के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने सर्वानंद सोनोवाल को सभी ने सिर-आंखों पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सभा में श्री सोनोवाल की शान में कसीदे पढ़े और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई। भाजपा ने इससे पहले किसी भी राज्य के विधानसभा चुनावों में पार्टी के किसी भी नेता को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था। असम में शानदार जीत हासिल करने के बाद भाजपा के हौसले बुलंदियों पर हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर वह उत्साह से सरोबार नजर आ रही है। असम में भाजपा की जीत ने उसके दिल्ली और बिहार में मिली करारी हार के गम को काफी हद तक कम कर दिया है। कार्यकारिणी में शामिल सभी नेताओं ने फुलाम गामोछा पहनकर जिस तरह से असम और असमवासियों का मान बढ़ाया, उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस कार्यकारिणी बैठक में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे जितने चर्चा के केंद्र में रहे, असमिया फुलाम गामोछा

भी उतना ही चर्चा में रहा।

जिस वक्त हमारे राज्य में असमिया फुलाम गामोछा जैसे यहां के परंपरागत वस्त्रों के भविष्य को लेकर चिंता-चर्चा का दौर चल रहा है, वैसे में यहां से हजारों मील दूर इलाहाबाद में सैकड़ों लोगों के गले में फुलाम गामोछा का नजर आना कम-से-कम इसके बेहतर भविष्य की ओर तो इशारा करता ही है। पिछले कई दशकों से असमिया फुलाम गामोछा राजनेताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। कांग्रेसी नेता तथा फिल्म अभिनेता स्व. सुनील दत्त का असमिया गामोछा से लगाव जग जाहिर है। उनके गले में हमेशा फुलाम गामोछा नजर आता था। उसी तरह टीम अन्ना के सदस्य रहे योगेंद्र यादव भी हमेशा फुलाम गामोछा में ही नजर आते हैं। इन बातों से यह तो साबित होता है कि असमिया हस्तकला-वस्त्र, कला-संस्कृति, परंपरा आदि अन्य प्रांत अथवा देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। मगर यह हमारी ही उदासीनता और सरकारी लापरवाही का नतीजा है कि असमिया महिला बुनकरों द्वारा बुने गए वस्त्रों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह लोकप्रियता व जगह हासिल नहीं हो पाई है। इलाहाबाद में हुई भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में असम के फुलाम गामोछा को लेकर किए गए प्रयोग ने यह बात भी साबित कर दी है कि ऐसे आयोजनों से किसी वस्तु विशेष को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसे प्रयोग इसलिए कहना पड़ रहा है कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने फुलाम गामोछा का अन्य प्रांतवासियों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रकार का कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश भाजपा ने कार्यकारिणी बैठक में शामिल सभी नेताओं का असमिया गामोछा से स्वागत कर एक अनुकरणीय कदम उठाया है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए जाएं तो आने वाले दिनों में देश के हर राज्य के लोगों के गले में असमिया फुलाम गामोछा को देखा जा सकता है। इससे न सिर्फ असम का मान बढ़ेगा, बल्कि असमिया फुलाम गामोछा के उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। मगर इसके लिए देश के अन्य राज्यों का मुंह देखने से ही नहीं होगा, राज्यवासियों को भी अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश करनी होगी। l

वनांचलवासियों की मदद से रोकी जा सकती है गैंडों की हत्या

वन्य जीव तस्करों द्वारा अवैध रूप से एक सींग वाले गैंडों की हत्या किए जाने की घटनाएं लंबे समय से राज्यवासियों में चर्चा व चिंता का विषय रही हैं। नई सरकार के सत्ता संभालने को अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ कि एक के बाद एक दो गैंडों की हत्या किए जाने की घटना ने स्वयं वन मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म को परेशानी में डाल रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कई दिन पहले एक पत्रकार सम्मेलन में नई सरकार को घेरते हुए कहा था कि गैंडों की हत्याएं अभी भी हो रही हैं, मगर अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। गैंडों की हत्याओं का सिलसिला यदि इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन गैंडा अजायबघर में सजावटी वस्तु बनकर रह जाएगा। पिछले तीन दशकों से राज्य में जिस तरह से जंगलों का सफाया किया रहा है, वह हरे-भरे असम को मरुभूमि में तब्दील करने का संकेत है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, इस वजह से जहां एक ओर हाथी-मानव में संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर तेंदुए, हिरण, सांप जैसे वन्य जीवों के जन बस्तियों में घुसने और लोगों के मारे जाने की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही हैं।

वन्य जीव तस्करों के हाथों सिर्फ वन्य जीव ही मारे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। धेमाजी के घूसखोर डिवीजनल फॉरेस्ट अधिकारी महत्त चंद तालुकदार जैसे बेईमान अधिकारियों की शह पर जंगलों का भी बड़े पैमाने पर सफाया हो रहा है। जिन लोगों के हाथों जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही लोग अगर जंगल के सफाए में लग जाएं तो असम की हरियाली के भविष्य का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तालुकदार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों ने एक बार फिर राज्य की प्रकृति प्रेमी जनता को चिंता में डाल दिया है। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर जंगलों में आरा मशीनें बैठा दी गई

हैं, जहां दिन-रात पेड़ों की कटाई व लकड़ियों की चिराई होती है। लकड़ी तस्करों का हौसला देखिए कि अब तो वे दिन दहाड़े वन कार्यालय के सामने से तस्करी की लकड़ी के कुंदों से लदे ठेले ले जाते हैं और किसी में इसका विरोध तक करने की हिम्मत नहीं होती। वन अधिकारी, वन्य जीव तस्कर और असामाजिक तत्वों की आपसी मिलीभगत ने राज्य के वनांचल के वातावरण को ही बिगाड़कर रख दिया है। लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत जंगलों को साफ कर वहां खाली हुई जमीन पर संदिग्ध लोगों को बसाया जा रहा है। इस तरह से विभिन्न वनांचलों में संदिग्ध लोगों की बस्तियां गुलजार होने लगी हैं। इन बस्तियों में रहने वालों को जिन प्रभावशाली नेता-अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोग इनके सामने अपना मुंह तक नहीं खोल सकते। इन संदिग्ध लोगों ने कई जगह तो स्थानीय लोगों को ही उनके पुराने निवास स्थल से खदेड़ दिया है। पिछली सरकार के दो वन मंत्रियों ने सिर्फ लंबी-लंबी हांक कर ही अपना काम निकाल लिया था। वन सुरक्षा कर्मियों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने संबंधी प्रस्ताव की फाइल आज भी किसी अन्य सरकारी फाइल के नीचे दबी पड़ी होगी। नव-नियुक्त वन मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म को भी ये सब समस्या बड़ी गंभीर लगने लगी है। ऐसे में सिर्फ वनांचल के आसपास बसे गांवों के लोगों पर ही जाकर उम्मीदों की नजर टिकती है। इन गांवों में वैसे लोग बसते हैं, जो वनांचल और वन्य जीवों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। इन गांवों के लोग पेड़ काटने में नहीं, वृक्षारोपण में और वन्य जीवों की हत्या में नहीं, उनके संरक्षण में विश्वास रखते हैं। गैंडों को तस्करों के कहर से बचाने और जंगलों को फिर से आबाद करने के लिए सरकार को वनांचल केआसपास बसे ऐसे गांववासियों की मदद लेनी चाहिए। जंगलों से जुड़ी सुरक्षा और समस्या का निदान ये गांववासी जितनी आसानी से कर सकते हैं, वन विभाग और सरकार नहीं। इसकी वजह भी साफ है वन अधिकारी समझते हैं जंगलों को बचाना उनकी नौकरी का हिस्सा है और वनांचल के आसपास के गांववालों के लिए किसी पेड़ को कटने से अथवा किसी गैंडे को मौत के मुंह से बचाना अपने बच्चे को बचाना जैसा लगता है। l

लोकप्रियता का असर : अंबुवासी मेले में उमड़ी भारी भीड़

नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित मां कामाख्या धाम में इस साल भी अंबुवासी मेला सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अबकी बार अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। कामरूप महानगर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और मेला संचालन समिति की कोशिश थी कि देश की जनता में अंबुवासी को भी कुंभ के मेले की तरह लोकप्रिय बनाया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय टीवी चैनलों से लेकर स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिए गए और महानगर में जगह-जगह होर्डिंग भी लगाए गए। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग यदि अंबुवासी मेले को कुंभ मेले जैसा लोकप्रिय बनना चाहता है तो उनके इस कदम की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मगर कोई यदि अंबुवासी मेले को लघु कुंभ कहे तो यह बात बहुतों के गले नहीं उतरने वाली। यह बात समझाने की जरूरत नहीं है कि कुंभ और अंबुवासी का अलग-अलग स्वरूप, अलग-अलग महत्व है। इसमें किसी भी प्रकार का घालमेल नहीं किया जाना चाहिए।

वैसे यदि मेले की तैयारियों की चर्चा की जाए तो उसके लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और मेला संचालन समिति धन्यवाद के पात्र हैं। मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का अंदेशा कर जिला प्रशासन की ओर से उसी पैमाने पर तैयारियां की गई थीं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेला परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और इसे तंबाकू व प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। उस हिसाब से तैयारियां भी की गईं, जिसकी झलक मेले के दौरान नजर भी आई। अबकी बार अंबुवासी मेले में अन्य सालों की अपेक्षा कम गंदगी देखने को मिली और तंबाकू के धुएं के छल्ले उड़ाने वाले भी अन्य सालों की अपेक्षा कम ही नजर आए।

इस साल भी अंबुवासी मेले के प्रारंभ होने के कई दिन पहले से ही महानगर के विभिन्न स्थानों पर साधु-संन्यासियों का जमावड़ा लगने लगा था। पूरी नीलाचल पहाड़ी श्रद्धालु, साधु-संन्यासियों की भीड़ से पट गई और जिधर देखो उधर ही माता के जयकारे की टंकार सुनने को मिली। इस साल अंबुवासी मेले में केंद्रीय तथा प्रांतीय नेता-मंत्रियों की भी भारी भीड़ देखने को मिली। इस साल भी अंबुवासी मेले के दौरान विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने जी खोलकर श्रद्धालुओं की सेवा की। संस्थाओं द्वारा लगातार कई दिनों तक प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर श्रद्धालुओं के बीच खाद्य सामग्री, जल आदि का वितरण किया गया। मेले के दौरान कहीं भी अव्यवस्था फैलने, किसी के बीमार होने अथवा किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई। इतने बड़े आयोजन को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करा लेना निश्चय ही प्रशासन और संबंधित विभागों की सफलता कही जाएगी। यहां इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि लगातार कई दिनों तक लाखों की भीड़ के टिके रहने के बावजूद नीलाचल पहाड़ी और इसके आसपास के हरे-भरे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य पर तनिक भी आंच नहीं आई। भीषण धूप की परवाह किए बिना कतारों में श्रद्धालुगण अपनी पारी के आने का इंतजार करते रहे और कहीं भी धक्का-मुक्की अथवा अफरा-तफरी की स्थिति देखने को नहीं मिली। श्रद्धालुओं के इस अनुशासन ने मेले की सफलता में चार चांद लगाने का काम किया। अंबुवासी मेले को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और मेला संचालन समिति ने अबकी बार जो कदम उठाए हैं, उसकी निरंतरता को ही इसकी सफलता की गारंटी माना जा सकता है। वैसे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और राज्य के पर्यटन मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा इस मसले को लेकर खासे गंभीर नजर आते हैं। डॉ. शर्मा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मेले के आयोजन के लिए एक स्थाई समिति का गठन किया जाएगा, जो अंबुवासी मेले के छह महीने पहले से ही अपना काम शुरू कर देगी। अंबुवासी मेले को कुंभ मेले जैसा स्वरूप देने संबंधी सरकार की यह कोशिशें सफल हों, इसके लिए हम समस्त राज्यवासियों को मां कामाख्या से प्रार्थना करनी चाहिए। ।

भारत के एनएसजी में शामिल होने पर चीन को आपत्ति क्यों ?

भारत के पड़ोसी देशों में चीन हाल के दिनों में भारत के लिए सबसे अधिक जटिलताएं पैदा करने वाला देश रहा है। वह चाहे पाकिस्तान के साथ प्यार की पींगे बढ़ाना हो अथवा एनएसजी में भारत के शामिल होने के मुद्दे का खुलेआम विरोध करना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मामलों में चीन और भारत के बीच की कटुता ने दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। हाल ही में सियोल में आयोजित परमाणु सामग्री आपूर्ति संगठन एनएसजी की बैठक में भारत को शामिल करने के मुद्दे का अधिकांश देशों ने समर्थन किया, मगर चीन ने खुलकर इसका विरोध कर भारत की राह में रोड़ा अटका ही दिया। चीन न सिर्फ भारत का विरोध कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को एनएसजी में शामिल किए जाने की मांग भी कर रहा है। पिछले पांच सालों में एशिया के पावर हाउस के रूप में उभरा चीन पिछले दो साल में भारत का संपूर्ण विकास देख मारे ईर्ष्या के जल-भून गया है। आकाश, जल, थल आदि

सभी मामलों में भारत को आत्मनिर्भर होते देख चीन अंदर ही अंदर शंकित हो उठा है। लिहाजा चीन अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा भारत को हर मामले में दबाकर रखना चाहता है। पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की हालत पतली है और विश्व पटल पर वह क्रमशः अकेला पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की इस खस्ताहाली का फायदा उठाकर चीन ने उसके कंधे पर बंदूक रख अपना हित साधने की योजना बनाई है। आज के दिन चीन को एक बड़ा बाजार चाहिए, भारत को नाराज करने के बाद अब उसकी नजर पाकिस्तानी बाजार पर है। पाकिस्तानी बाजार भारतीय बाजार जितना बड़ा और समृद्ध तो नहीं है, फिर भी चीन के हितों को काफी हद तक साध सकता है। ऐसे में चीन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत से अधिक पाकिस्तान को तवज्जो देकर अपनी मित्रता को जग जाहिर करना चाहता है। इसी का नतीजा था कि चीन ने भारत के एनएसजी में शामिल होने का विरोध और इस संगठन में पाकिस्तान को शामिल किए जाने की मांग तक कर डाली। अमरीका जैसी महाशक्तियों द्वारा भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने के मसले पर अग्रणी भूमिका ग्रहण करने के बाद इसमें चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने से पूरा का पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सियोल में आयोजित विशेष अधिवेशन से पूर्व चीन के करीब 250 सैनिक अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विचरण करते हुए देखे गए थे। सिर्फ यही नहीं, उसने दस हजार नागरिकों को भारत छोड़कर चले जाने का आदेश भी दिया था। चीन द्वारा इतने तीखे तेवर दिखाने के बाद भी भारत ने इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया प्रकट करने के बजाय वह अंदर ही अंदर अपने किसी विशेष अभियान में लगा हुआ था। इसी विशेष अभियान का नतीजा था कि जब भारत के एनएसजी में शामिल होने के मुद्दे पर विश्व भर में चर्चा-परिचर्चा का बाजार गर्म था, ठीक उसी समय भारत बड़ी ही शांति से मिसाइल तकनीक नियंत्रण संघ (एमटीसीआर) में बतौर सदस्य शामिल होने में कामयाब रहा। एमटीसीआर का सदस्य बनने से भारत परमाणु शक्ति मिसाइल कार्यक्रम की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया। फ्रांस, नीदरलैंड आदि देशों को लेकर गठित एमटीसीआर की

सदस्यता लेने के लिए विगत 27 जून को नई दिल्ली में देश के विदेश सचिव एस. जयशंकर ने फ्रांस, नीदरलैंड सहित कई देशों के राजदूतों की उपस्थित में एमटीसीआर के सदस्यता पत्र पर हस्ताक्षर किए और उक्त संस्था में 35वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया। भारत इस संस्था में बिना किसी बाधा इसलिए शामिल होने में सफल रहा, क्योंकि इसमें चीन शामिल नहीं है। चीन को अभी तक एमटीसीआर की सदस्यता हासिल नहीं हो पाई है।

चीन भ्रमण के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के माध्यम से दोनों देशों के बीच की दूरियों को पाटने की कोशिश की थी, मगर चीन बाहर से दोस्ती का दिखावा करता रहा और अंदर ही अंदर भारत के विरोध में सक्रिय रहा। एनएसजी में भारत को शामिल किए जाने के मसले पर चीन हमेशा से ही कूटनीतिक पैंतरेबाजी करता आया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चीन ने भारत को आश्वासन दिया है कि भविष्य में यदि एनएसजी में भारत को शामिल किए जाने के मसले पर चर्चा होती है तो चीन उसमें अपना सकारात्मक रुख दिखाएगा। चीन ने दलील दी है कि भारत ने अभी तक न्यूक्लियर नॉन प्रॉलिफिरेशन (एनपीटी) समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण ही चीन ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर चीन ने पाकिस्तान को एनएसजी में शामिल किए जाने का खुला समर्थन करते हुए कहा है कि एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत को जो छूट दी जा रही है, पाकिस्तान को भी वही छूट दी जानी चाहिए। आने वाले दिनों में चीन भारत के खिलाफ कौन-सा पैंतरा बदलता है, यह देखने वाली बात होगी। ।

केवल जरूरतमंदों को ही जारी किए जाएं राशन कार्ड

देश स्वाधीन होने के इतने साल गुजर जाने के बाद भी हमारे देश को गरीबी से आजादी नहीं मिल पाई है। देश की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। गरीबी खत्म करने के लिए हजारों करोड़ों की सरकारी योजनाएं बनती हैं, पैसे खर्च भी होते हैं, मगर ऐसी योजना का पूरा फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी योजनाओं के मद में खर्च की जाने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि गरीबों के लिए केंद्र द्वारा जारी एक रुपए का सिर्फ 11 प्रतिशत हिस्सा ही उन तक पहुंच पाता है। देश भर में स्थापित सुलभ मूल्य की दुकान और राशन कार्ड व्यवस्था सरकार की ऐसी ही जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। मगर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से इस योजना का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है, वह भी तब जबकि इस योजना को प्रारंभ किए कई दशक बीत गए हैं।

हमारे समाज के बहुत से लोगों को आज भी यह पता नहीं है कि उनके नाम जारी किया गया राशन कार्ड किस सुलभ मूल्य की दुकान के अधीन है। बहुत से लोग राशन कार्ड के माध्यम से राशन नहीं खरीदते, लिहाजा उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने अपना राशन कार्ड कहां रखा है अथवा इससे पहले कब सुलभ मूल्य की दुकान से राशन खरीदा था। इन दिनों पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि को परिचय अथवा स्थायी पते के शिनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड से पहले राशन कार्ड का परिचय अथवा स्थायी पते के शिनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके बावजूद बहुत से लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। धनी परिवारों में एक अन्य प्रकार की घटना देखने को मिलती है। ऐसे परिवार के नाम जारी राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाला राशन उनकी जगह कोई और व्यक्ति ही अपने घर ले जाता है। कुछ लोग राशन कार्ड को सुलभ मूल्य की दुकान तक लाने-ले जाने की जहमत से बचने केलिए अपने राशन कार्ड को सुलभ मूल्य दुकान के मालिक के पास ही रख छोड़ते हैं। सरकार द्वारा सुलभ मूल्य पर प्रति महीने दिए जाने वाले राशन की आपूर्ति राशन कार्ड धारक को ही की जाती है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है, बोलकर इसका लाभ कोई अन्य व्यक्ति ही उठा ले जाता है। यह 'अन्य व्यक्ति' कौन है, सरकार और विभागीय अधिकारियों से मैं इसकी जांच कराए जाने की अपील करता हूं। अब तक जारी राशन कार्डों की अच्छी तरह से जांच कर यदि योग्य और जरूरतमंद लोगों को ही राशन कार्ड जारी किया जाए तभी जाकर इस पूरे मामले में चल रहे घोटाले-भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा। ऐसे सुलभ मूल्यों की दुकानों में सरकार की ओर से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है। हर एक सुलभ मूल्य की दुकान के राशन कार्ड धारकों की संख्या के अनुसार आवंटित खाद्य सामग्री का सही ढंग से वितरण होता है या नहीं, इस पर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। सरकार यदि समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए सुलभ मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है तो इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं है, मगर समाज का धनी तबका भी ऐसे ही राशन कार्ड के माध्यम से सुलभ मूल्य पर मिलने वाली

खाद्य सामग्री खरीदता है तो इस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। सुलभ मूल्य पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री की यदि समाज के धनी तबके के परिवारों में आपूर्ति न की जाए तो इससे सरकार को न सिर्फ हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो सकेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा।

इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह तमाम राशन कार्ड की ठीक से जांच कराए और जो व्यक्ति-परिवार सरकार की इस योजना के दायरे में नहीं आता, वैसे लोगों के राशन कार्ड को रद्द कर दे। आज कल चूंकि पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट का ही चलन है, लिहाजा राशन कार्ड के न रहने पर भी किसी को अपनी पहचान और पते की शिनाख्त कराने में असुविधा नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि वह परिवार के मुखिया की वार्षिक आय के आधार पर राशन कार्ड पाने वालों की योग्यता तय करे। सरकार द्वारा यदि ऐसा कदम उठाया जाता है तो पहले-पहले तो तनिक असुविधा होगी, मगर बाद में जनता भी इसमें सहयोग करने के लिए आगे आएगी। l

एम्स की स्थापना को लेकर हंगामा क्यों ?

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को लेकर जारी विरोध असमवासियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यह भी सच है कि एम्स की स्थापना के नाम पर जारी आंदोलन की आग में पूरा मध्य असम जल रहा है। इसको लेकर नगांव जिले के रोहा में स्थिति सबसे अधिक तनावपूर्ण है। एम्स स्थापना की मांग में राजमार्ग अवरोध के दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों की जद में आने से मिंटू कुंवर नामक एक युवक की जान भी जा चुकी है। कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं। इस आंदोलन ने राज्य भर के लोगों को आकर्षित किया है। अब तो जागीरोड और बराकघाटी में भी एम्स की स्थापना के नाम पर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वैसे यदि देखा जाए तो राज्य के हर एक कोने के लोग अपने इलाके में एम्स खोले जाने की मांग कर सकते हैं। रोहा ही क्यों, धुबड़ी से लेकर सदिया तक किसी भी गांव-शहर के लोगों को लोकतांत्रिक तरीकेसे ऐसी मांग करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन किसी अंचल विशेष के लोगों द्वारा ऐसी मांग करने के दौरान यदि दूसरे अंचल के लोगों को नुकसान पहुंचता है तो फिर इसको लेकर नाराजगी-गुस्सा पनपना स्वाभाविक है। रोहा में एम्स की स्थापना को लेकर वहां की जनता द्वारा किया जा रहा आंदोलन पहले तो शांतिपूर्ण था, मगर बाद में आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस की गोली से एक युवक को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अब सवाल यह है शांतिपूर्वक चल रहा आंदोलन अचानक से हिंसक कैसे हो गया। आंदोलनकारियों को यह हक नहीं था कि राजमार्ग से गुजरने वाले निरीह लोगों को बीच सड़क पर बंदी बना लिया जाए। यह जरूरी नहीं है कि किसी मांग को लेकर शुरू किया गया आंदोलन हिंसक होने से वह आंदोलन सफल

कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को उनका हक दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन ही किया था और बापू अपने मकसद में कामयाब भी रहे। अहिंसा के दम पर बापू ने न सिर्फ अंग्रेजों को खदेड़कर देश से बाहर किया, बल्कि देशवासियों को आजाद होने का गौरव भी प्रदान किया। यह सही है कि बापू का अहिंसा आंदोलन लंबा चला, मगर बेनतीजा भी नहीं रहा। देशवासियों के सहयोग व समर्थन के बल पर अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना ही पड़ा। हम सभी बापू के अहिंसक आंदोलन को छोड़ हिंसा के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन छेड़ने लगे तो ऐसे आंदोलन को कितने लोगों का समर्थन हासिल होगा, यह कहना मुश्किल है। रोहा में चल रहा आंदोलन भी कुछ ऐसी ही दिशा लेने लगा है। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन के एकाएक हिंसक हो जाने का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता और यह कोई अच्छा संकेत भी नहीं है। आंदोलनकारी यदि निरीह जनता को गिरवी रखकर सरकार से अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं तो इस कृत्य का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। एम्स की स्थापना रोहा में हो या जागीरोड अथवा चांगसारी में, इस बात को लेकर जनता में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये सभी शहर असम के ही हिस्से हैं। केंद्र सरकार ने भी जब घोषणा की थी तो उसने अपनी घोषणा में असम में ही एम्स खोले जाने की बात कही थी। केंद्र सरकार की घोषणा में असम के किस स्थान पर एम्स खोला जाएगा, इस बात का जिक्र नहीं था। केंद्र सरकार की उक्त घोषणा के बाद ही उत्तर गुवाहाटी, रोहा सहित राज्य के अलग-अलग शहरों में एम्स की स्थापना की मांग उठने लगी। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस इलाकेमें एम्स खुलेगा, उस इलाके का विकास होना तय है और इससे इलाके का महत्व भी बढ़ेगा। क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के साथ ही व्यापार-रोजगार आदि में भी बढ़ोतरी होगी। मगर सिर्फ रोहा अथवा चांगसारी के आसपास के लोगों के बारे में ही सोचने से नहीं होगा, हमें असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पड़ोसी राज्यों के मरीजों के बारे में भी सोचना होगा। एम्स की स्थापना ऐसे स्थान पर हो, जहां से यातायात का संपूर्ण साधन उपलब्ध हो। एम्स की स्थापना रोहा, सदिया, धुबड़ी, जागीरोड, चांगसारी कहीं भी हो-अशांत असम कोई भी नहीं चाहता। l

तुर्की का तख्तापलट और पाक के नापाक इरादे

तुर्की में विगत 16 जुलाई की देर रात तख्तापलट की सैन्य कोशिशों को वहां की जनता ने भले ही नाकाम कर दिया, मगर तुर्की में चल रहे गृह युद्ध की स्थिति को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। तुर्की के जागरूक और देशभक्त नागरिकों के कारण तख्तापलट का प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। तख्तापलट करने में लगी ताकतों के सामने तुर्की सरकार की सेना कमजोर होने के बावजूद वहां की देशभक्त जनता तोप और बंदूकों के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई और विद्रोहियों के पूरे गणित को ही गड़बड़ा दिया। राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में 6 हजार विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तुर्की के बड़े शहरों में रात भर हुई हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे विश्व भर में तहलका मचा दिया, सभी ने एक स्वर में तख्तापलट की कोशिश की निंदा की। क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ सैन्य बल द्वारा विद्रोह की घोषणा करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तुर्की में भले ही सेना अपने नापाक इरादे में नाकाम रही, मगर देश की अंदरुनी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। तख्तापलट की कोशिश के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन का नाम लिया जा रहा है। उन पर सेना के अधिकारियों को भड़काने का आरोप है। इस बगावत की वजह से राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा सारे अधिकार अपने ही पास रखने की कोशिश बताई जा रही है। उन्होंने सत्ता में आते ही कई सैन्य अफसरों पर मुकदमे चलाए। इससे असंतोष बढ़ा। देश का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ा है, जबकि सेना पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र समर्थक है। सरकार के अमरीका और यूरोप के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं, जबकि सेना नाटो का सदस्य होने के नाते सौहार्द्रपूर्ण रिश्ते चाहती है। लिहाजा तुर्की में तख्तापलट के लिए सैनिक टैंकों के साथ सड़कों पर उतर आए। आठ करोड़ की आबादी वाले दो बड़े शहर अंकारा और इस्तांबुल में अहम पुलों और इमारतों पर कब्जा कर लिया। साथ ही सेना ने हेलिकाप्टरों और छोटे विमानों से भी लोगों पर गोलियां बरसाईं। 15 जुलाई से

सरकार विरोधी और सरकारी सेना के बीच चली लड़ाई में किसी तीसरे पक्ष का हाथ नहीं रहा होगा, इस बात से भी किसी ने इनकार नहीं किया है। क्योंकि हाल ही में विभिन्न देशों में हुई घटनाओं में कट्टरपंथी संगठनों का हाथ होने की जानकारी सामने आई है। विशेषकर आईएस हमले इस घटना के पीछे जिहादी संगठनों का हाथ होने का इशारा करते हैं।

तुर्की की घटना के साथ-साथ इन दिनों पाकिस्तान भी चर्चाओं में है। क्योंकि तुर्की में तख्तापलट कोशिशों के बाद पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा है कि सेना द्वारा तख्तापलट की ऐसी कोशिशें यदि पाकिस्तान में होती हैं तो वे सेना का समर्थन करेंगे। पाठकों को याद होगा कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के जरिए ही वहां के सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सत्ता पर कब्जा जमाया था। मुशर्रफ ने बाद में क्या-क्या किया यह सभी को मालूम है। तुर्की की घटना से एक दिन पहले आईएस ने फ्रांस में भी हमला कर खून की नदी बहाई थी। वहां के राष्ट्रीय दिवस 'वेस्टिल दिवस' पर आईएस ने चलते ट्रक से वहां के सुरक्षा इंतजामों को रौंदते हुए अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर 84 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फ्रांस केहमले की सफलता पर आईएस ने विजय उत्सव भी मनाया था। निहत्थों पर गोलियां चलाना मानो आईएस का धर्म बन गया है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के ढाका में भी ऐसा ही एक हमला किया गया था, जिसमें एक भारतीय मूल की युवती सहित कई लोग मारे गए थे। पहली जुलाई को आतंकवादियों ने ढाका के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकेमें स्थित एक होटल में हमला कर यह साबित कर दिया कि सभी क्षेत्र उनकी जद में हैं और ऐसी घटनाओं में उन्हें कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त है। इतने दिन बांग्लादेश ने भारत विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के कई उग्रवादी संगठनों के नेता-कैडरों ने शरण दे रखी थी। बांग्लादेश भले ही स्वयं को भारत का मित्र देश बताता हो, मगर समय-समय पर उसका इस तरह का दोहरा चरित्र सामने आता रहा है। उग्रवादी-आतंकवादियों को शह देने का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति पर नजर डालें तो उसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। l

कश्मीर की आजादी पर जनमत, पाक का ख्याली पुलाव

कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान हमेशा से ही नकारात्मक भूमिका ग्रहण करता आया है। जब भी भारत अपने इस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने की योजना बनाता है अथवा उस दिशा में कदम बढ़ाता है, पाकिस्तान सरकार, सेना अथवा कोई न कोई दल-संगठन उससे पहले ही कश्मीर का रोना लेकर बैठ जाते हैं। भारत ने जब भी पाकिस्तान की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तभी कश्मीर मसले के नाम पर पाकिस्तान की ओर से इस रिश्ते को परवान चढ़ने से रोका गया है। विगत 22 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में जो टिप्पणी की वह दोनों देशों के बीच और दूरियां पैदा कर सकती हैं। मालूम हो कि नवाज ने मुजफ्फराबाद में कहा था कि जितना मैं पाकिस्तानी हूं, उतना ही कश्मीरी हूं। मेरे लिए पाकिस्तान और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सत्ताधारी दल पीएमएलएन के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद की थी। पिछले दो सालों में नवाज शरीफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार मुलाकातें कर चुके हैं। इसके बावजूद शरीफ के व्यवहार में शराफत नहीं दिखती। हाल ही में उन्होंने यह विवादित टिप्पणी भी की थी कि हमें इंतजार है, जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। देश विभाजन के बाद से पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी नापाक नजरे गड़ाए हुए है। कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर एक बार नहीं, चार-चार बार हमले किए, मगर पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सैनिकों ने हर बार पाकिस्तानी सैनिकों को इस तरह से खदेड़ा कि उनकी रूह भी पनाह मांगने लगी। कारगिल युद्ध के दौरान कई आतंकवादी संगठनों के सशस्त्र आतंकियों ने सैनिक बनकर पाकिस्तानी सेना की मदद की थी और भारत द्वारा लगाया गया यह आरोप बाद में सही साबित भी हुआ था। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकी संगठनों को पालता है, यह बात उस समय प्रामाणिक तौर पर विश्व के सामने

आई, जब अमरीकी सेना ने विश्व भर में आतंक का पर्याय बने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की ही भूमि पर मार गिराया था। अमरीकी सैनिक जाते-जाते लादेन का शव भी अपने साथ ले गए, मगर पाकिस्तान पर लगे आतंकियों को शह देने के आरोप को और भी पुख्ता कर गए। कश्मीर पर कब्जा जमाने की नीयत से दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पाकिस्तान हमेशा कोई न कोई गुल खिलाता ही रहता है। भारत-पाक सीमा पर कभी पाकिस्तानी सैनिक अभियान चलाते हैं तो कभी आतंकियों को आगे कर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। पाकिस्तान कश्मीर की आजादी का मुद्दा उछालकर कश्मीरियों के जनमत संग्रह की भी मांग करता रहा है। पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ तक में उठा चुका है। कई अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान अपनी शह और सहयोग देकर कश्मीर को अशांत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अलगाववादी नेता पाकिस्तान का समर्थन करने वाले युवाओं को लेकर प्रदर्शन से लेकर पत्थरबाजी तक कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ने के बाद अलगाववादियों ने उनकी जमीन, उनके घरों पर अपना कब्जा जमा रखा है और आज के दिन यदि देखा जाए तो कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर इन अलगाववादियों का कब्जा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ ही अलगाववादी ताकतें एक ऐसी जगह बनाने में लगी हैं, जहां पाकिस्तानी समर्थक भारत समर्थकों से अधिक नजर आएं। ऐसे मंजर को सामने रखकर कश्मीर की आजादी के मुद्दे पर पाकिस्तान जनमत संग्रह कराने की बात कहता आया है, मगर यह मांग पाकिस्तान का ख्याली पुलाव है, जो कभी नहीं पक सकता। विगत 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की सैन्य मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर पाकिस्तान ने अपना जो रुख दिखाया, वह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। पाकिस्तान की इस काली करतूत में अलगाववादी हुर्रियत कांफ्रेंस और जेकेएलएफ ने भी आग में घी डालने का काम किया था। इसी के बहाने एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्राह कराने की बात कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मसले पर भारत की अग्नि परीक्षा लेता रहा है, लेता रहेगा और भारत भी चाणक्य नीति के तहत पाकिस्तान की करतूतों का जवाब देकर उसे विश्व मंच पर हंसी का पात्र बनाता रहेगा। ।

भारत को सबसे बड़ा खतरा किससे, चीन या पाकिस्तान से

भारत की हमेशा से ही कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध मित्रतापूर्ण रहे और वह अपने सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सके। राजा-महाराजा के दिनों से भारत चाणक्य नीति का अनुसरण करते हुए न सिर्फ पड़ोसी देश, बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी शांतिपूर्वक और दोस्ताना संबंध बनाए रखने की नीति पर अमल करता आया है। लेकिन भारत की इस मित्रवत नीति के विपरीत पाकिस्तान और चीन का नजरिया भारत के प्रति हमेशा नकारात्मक ही रहा है। स्वाधीनता हासिल करने के बाद से ही भारत पाकिस्तान और चीन के आक्रमण का शिकार रहा है। देश के स्वाधीन होने के बाद से अब तक चीन ने एक बार और पाकिस्तान ने चार-चार बार भारत पर आक्रमण किए हैं। यह भी सच है कि भारतीय सेना के शौर्य के दम पर पाकिस्तान को हर एक युद्ध में मुंह का खानी पड़ी थी, जबकि 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' की गलतफहमी में डूबे हमारे देश को चीन के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी-कभी पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती का दम भरता

है और चीन भारत का मित्र होने का दिखावा करता है। मगर जब भी मौका मिलता है दोनों देश विश्व पटल पर भारत को नीचा दिखाने अथवा उसकी टांग खींचने से बाज नहीं आते। पाकिस्तान और चीन हमेशा भारत को अस्थिर रखने की फिराक में रहते हैं और हाथ आए किसी भी मौके को गंवाने से नहीं चूकते। दोनों देश किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्धाभ्यास करते रहते हैं।

जैसे-तैसे कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान दिन-रात कूटनीति चलता रहता रहता है, जबकि चीन की गिद्ध-दृष्टि अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि पाकिस्तान ने कश्मीर को और चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में शामिल दिखाया। कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान ने अब तक जितने पैसे खर्च किए हैं, उतने पैसे यदि अपने विकास पर खर्च करता तो उसका भाग्य संवर जाता। इतने पैसों में वहां एक हजार बड़े-बड़े स्टेडियम बन जाते। पाकिस्तान भारत पर हमला करने के मौके की ताक में लगा रहता है और आज भी भारत को ध्यान में रख अमरीका, चीन, फ्रांस, इजरायल आदि देशों से लड़ाकू विमान खरीदने में लगा है। वह सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर उसके नाम पर आए दिन भारत को हड़काता भी रहता है। उसने दिल्ली को लक्ष्य कर अपने हथियारों को तैनात कर रखा है। कारगिल युद्ध में भारत के हाथों करारी शिकस्त पाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज आने को तैयार नहीं दिखता। भारत आज भी उसके निशाने पर है और इसीलिए वह गाहे-बाहे भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव फैलाने के लिए कोई न कोई साजिश करता रहता है। कभी-कभी वह अपनी सेना की मदद से भारतीय सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, मगर सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की चौकस निगाहें उसके ऐसे नामुराद मंसूबों को नाकाम करके ही दम लेती हैं।

इधर, चीन भी चुप नहीं बैठा है, वह अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाने के लिए हर प्रकार की कोशिशों में लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत-चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ने को उतावला चीन पिछले कई सालों

से इस योजना पर काम करता आ रहा है। हिमालय के निकट चीन द्वारा बनाई गई सड़क को चीन की ऐसी ही तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा चीन ने हिमालय की तराई में हेलिपैड तक बना ली है। भारत को चीन की इन सभी हरकतों की जानकारी है और वह किसी भी हालत में चीन के बहकावे में आने वाला नहीं है। चीन द्वारा पिछले कई दशकों से सीमावर्ती इलाकों में की जा रही तैयारियों को गंभीरता से लेते हुए भारत ने भी अब अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा हुआ, जब चीनी सेना ने जबरन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन भारत का मित्र होने का कितना ही दम भरे, मगर उसके कार्यकलाप उसकी भारत विरोधी नीति को ही स्पष्ट करते हैं। चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार तथा अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने का मकसद सिर्फ भारत को कमजोर बनाए रखना है। पाकिस्तान को सागर के किनारे परमाणु परियोजना स्थापित करने के लिए चीन ने उसको तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की राह में चीन ने हमेशा भारत के खिलाफ रोड़े ही अटकाए हैं। ऐसे में यह सवाल तो खड़ा होता ही है कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है चीन से या पाकिस्तान से। 1

निरीह लोगों की खून से होली खेलकर फायदा किसको

उग्रवादी या जिहादियों का असली टार्गेट निरीह जनता ही होती है। बम फेंककर अथवा गोलियां चलाकर निहत्थे लोगों की हत्या करना सबसे आसान काम है। उग्रवादी तथा जिहादी संगठन ऐसे निरीह लोगों की हत्या कर सोचते हैं कि कोई बड़ा तीर मार लिया हो। दुनिया का कोई भी हिस्सा क्यों न हो, आतंकवादी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपने इस कुकृत्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने में तनिक भी शर्म महसूस नहीं करते। मगर सवाल उठता है कि अपने ऐसे कुकृत्यों को स्वीकार करने के बाद उग्रवादी अथवा जिहादियों को आम जनता से क्या कोई सहानुभूति अथवा हमदर्दी हासिल होती है। यह सही है कि एक-आध दिन के लिए कुकृत्यकारी संगठन मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है, मगर इससे किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं मिलता। इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने के फलस्वरूप जिस प्रकार मानव संपदा का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती, भले ही उस संगठन की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा क्यों न हो जाए। कोकराझाड़ जिले के बालाजान तीनाली में हाल ही के दिनों हुई नरसंहार की घटनाओं को इन्हीं बातों की रोशनी में देखा जाना चाहिए। आतंकवादियों ने भरे बाजार में गोलियों की बौछार कर 14 लोगों की जान लेने के अलावा कई लोगों को बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। आतंकवादियों की योजना ऐसे नरसंहार को अंजाम देकर बीटीएडी क्षेत्र में दंगा फैलाने की रही होगी, मगर स्थानीय जनता ने आतंकवादियों के इस नापाक मंसूबे को इस बार कामयाब नहीं होने दिया। मालूम हो कि इससे पहले भी आतंकवादी ऐसी नरसंहार की घटना को अंजाम देकर बीटीएडी क्षेत्र में दंगा करन में सफल रहे थे। राज्यवासी बीटीएडी के उन दंगों को भूले नहीं होंगे, जब सैकड़ों लोगों को बेघर होकर शरणार्थी शिविरों

में शरण लेनी पड़ी थी। वैसे परिवार आज भी अपनी उजड़ी जिंदगी को फिर से संवार नहीं पाए हैं। जिसके घर का कोई सदस्य आतंकवाद की ज्वाला की भेंट चढ़ गया, उस घर का सूनापन अब भी वैसे का वैसा ही है। बाद में कुछ दिनों तक ऐसी हत्या-नरसंहार की घटनाएं नहीं होने पर बीटीएडी के लोगों ने चैन की सांस ली ही थी कि बालाजान की घटना ने एक बार फिर उनके जख्मों को हरा कर दिया। बालाजान की कांड की चिंगारी को बीटीएडी इलाके के अन्य भागों में फैलने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों के प्रयासों की जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। लोगों ने आतंकवादियों के ऐसे नापाक मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया और इस लड़ाई में हिंदू-मुसलमान, ईसाई आदि ने शांति सभाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर आतंकवादियों तक यह पैगाम पहुंचाया कि उनकी एकता-भाईचारे को खत्म नहीं किया जा सकता।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस सवाल का जवाब संभवत: किसी के पास नहीं है कि बालाजान की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा। आतंकवादियों के खूनी खेल में जिन्होंने अपने पिता-भाई-बेटे अथवा बहन को हमेशा के लिए खो दिया उनको दिलासा कौन देगा। आतंकवादियों ने ठीक सामने से अंधाधुंध गोलीबारी कर जिस तरह से निरीह लोगों को मौत के घाट उतारा, वह मंजर असमवासियों के लिए कल्पना से भी बाहर है। असम में इससे पहले इस तरह के नरसंहार की घटना कभी भी नहीं घटी। दिनदहाड़े भरे बाजार में आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाने की घटना को राज्यवासियों ने बड़ी ही असहजता से लिया है। क्योंकि इससे पहले कम-से-कम लोगों ने टीवी चैनलों पर तो ऐसी घटना को लाइव नहीं देखा था। यहां इस बात का भी जिक्र किया जाना जरूरी है कि पिछले तीन दशक में राज्य में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी-उग्रवादी संगठनों ने अलग-अलग जगह पर लोगों की हत्याएं की हैं, मगर बालाजान जैसी नरसंहार की घटना किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं की है। बालाजान की घटना में किसी तीसरी ताकत का हाथ नहीं रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर जनता अब समझदार हो गई है। हर कोई असम में शांति चाहता है, क्योंकि पता है शांति से ही राज्य का विकास और युवाओं को रोजगार संभव है। l

भारत को चाहिए पाक अधिकृत कश्मीर

स्वाधीनता के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा जमाने की साजिश रचता रहा है। कई बार कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया है। अपने वजूद में आने के बाद से अब तक पाकिस्तान कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका है, यह अलग बात है कि पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और लड़ाई के मैदान में वह कभी भी भारत के सामने नहीं टिक पाया है। इस बार भी कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ से गुहार लगाई है। इस मसले को लेकर अमरीका के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी पाकिस्तान को कहीं से भी किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला है। यह पाकिस्तान ही है, जो कश्मीर की आजादी पर कश्मीरियों के बीच जनमत कराने का राग अलापता रहा है। लड़ाई के मैदान से लेकर राजनीतिक-कूटनीतिक बिसात पर करारी शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान के स्वभाव में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं।

पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस के मौके पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल वशीर ने पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस को कश्मीर की स्वाधीनता को अर्पित करने की बात कह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी। वशीर ने अपने बयान में यह बात भी जोड़ी थी कि उनका देश हमेशा कश्मीर की जनता को अपना कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन देता रहेगा और कश्मारी अवाम की कुर्बानियों को व्यर्थ जाने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री से लेकर सेनाध्यक्ष-उच्चायुक्त तक समय-समय पर इस प्रकार के भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। यह बात अलग है कि पाकिस्तानी नेताओं के ऐसे बयान अब तक गीदड़ भभकी मात्र साबित हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सरफराज अजीज ने भी यह कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी कि कश्मीर के

मसले पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान जल्द ही भारत को आमंत्रित करेगा। ऐसी हल्की बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर विराम लगा दिया कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का अटूट अंग है।

गृह मंत्री के इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी तीखे तरीके से लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा। श्री मोदी ने पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से समझा दिया कि कश्मीर को लेकर उसने यदि ज्यादा ही सक्रियता दिखाई तो भारत भी पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाक सेना द्वारा वहां के निरीह लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों का मसला संयुक्त राष्ट्र में उठा सकता है। श्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत भी पाक अधिकृत कश्मीर को उसके चंगुल से मुक्त कराने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री ने पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए कहा कि कश्मीर के उस हिस्से को आजाद कराने के लिए उचित कदम उठाने में कोई कमी नहीं रख छोड़ेगा। इससे पहले स्वाधीन भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इतने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी थी। श्री मोदी के इस कदम को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यहां इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर का एक हिस्सा चीन को दे रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान की गलबाहियां किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में यह बात भी साफ है कि चीन भारत के वैसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाता हो। पिछले दिनों एनएसजी में भारत के शामिल होने की राह में चीन द्वारा रोड़े अटकाने की घटना को इसी आलोक में देखा जा सकता है। इसके जवाब में भारत भी दक्षिण चीन सागर के विवाद को हल करने में चीन की मदद नहीं करने वाला। ऐसी विषम परिस्थिति से पार पाने के लिए चीन भारत से सहयोग-समर्थन और मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं श्री मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उछालकर पाकिस्तान के होश गुम कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की अगली चाल क्या होती है। ।

बच्ची के अपहरणकांड से निकले सबक

हाल ही में हुई एक बच्ची के अपहरण की घटना ने पूरे राज्यवासियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। महानगर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मात्र 16 घंटे में बच्ची को अपहर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लिया और इस घटना में शामिल नौकरानी सहित आधे दर्जन अपराधियों को भी धर दबोचा। इसके बावजूद इस घटना को लेकर अभी भी चर्चाओं का दौर थमा नहीं है। एक नौकरानी द्वारा सोची समझी योजना के तहत एक बच्ची का उसी के घर से अपहरण कर लेना, यह सवाल तो खड़ा करता है ही कि क्या हमारे राज्य में भी अपहरण का धंधा सर उठाने लगा है। विगत 22 अगस्त को अल्फा स्वाधीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश से तिनसुकिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष रत्नेश्वर मोरान के पुत्र कुलदीप मोरान का अपहरण किए जाने की घटना को भी इस कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है। इन घटनाओं ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे बच्चे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं? यहां यह सवाल भी विचार करने लायक है कि बच्चों के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन है।

आज के अधिकांश माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए उतना वक्त नहीं है, जितना वक्त बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी है। इस स्थिति को अभिभावकों की मजबूरी के तौर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पति की आय ही काफी नहीं रह गई है। लड़कियां भी पढ़-लिख गई हैं और घर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पति-पत्नी का काम अथवा नौकरी करना समय की मांग है। काम के बोझ तले दबे ऐसे भी अभिभावक हैं, जिनके पास एक साथ बैठकर खाना खाने तक का वक्त नहीं है, वैसे में ये अभिभावक अपने बच्चों का कितना ध्यान रख पाते होंगे यह पूछने अथवा बताने की जरूरत नहीं है। वैसे हर एक बच्चा अपने माता-

पिता के साथ वक्त गुजारना चाहता है।

समाज में पहले जैसे संयुक्त परिवार भी नहीं के बराबर रह गए हैं। पहले माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चा दादा-दादी, चाचा-ताऊ के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहता था, मगर आज के दिन पति-पत्नी की गैर-मौजूदगी में बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी नौकर-आया पर होती है। माता-पिता के साथ बच्चों का खेलना-बतियाना अब दूर की कौड़ी लगती है। राज्य के किसी भी शहर में चले जाएं, बच्चों की देखभाल के लिए किसी के भी पास वक्त नहीं है। इसका समाधान एक नौकर-नौकरानी तक ही सीमित होकर रह गया है। अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन, मनोरंजन के लिए टीवी-वीडियो, खाने के नाम पर जंक फूड, मस्ती के नाम पर मोबाइल-इंटरनेट आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, बस नहीं है तो बच्चों के साथ बिताने के लिए उनके पास समय। बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं-मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा देने भर से अभिभावकों की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बच्चा क्या खाता है, कहां जाता है और अपने स्कूल में उसकी गतिविधियां क्या हैं, ऐसी बातों पर यदि अभिभावक ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा।

इसे आधुनिक दौर की विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के दौर में पैदा होने वाला बच्चा अपने माता-पिता नहीं, नौकरानी-आया की गोद में पलकर बड़ा होता है। ऐसे में बच्चे की सुरक्षा की बात कौन करे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाए। पिछले दिनों महानगर में घटी बच्ची के अपहरण की घटना समाज की आंखें खोल देने वाली घटना साबित हुई है। घर में काम पर रखने वाले नौकर-ड्राइवर आदि की पूरी जानकारी-उनकी फोटो न रखना जहां एक ओर बच्चों एवं स्वयं की सुरक्षा के प्रति हमारी चरम लापरवाही को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह बात भी स्पष्ट करता है कि हम इन नौकर-आया-ड्राइवरों पर किस हद तक निर्भरशील हो गए हैं। इस घटना से सभी औलादवालों को सबक लेनी चाहिए और जिंदगी की भाग-दौड़ से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों को भी देना चाहिए। इससे बच्चों को माता-पिता के प्यार की गर्माहट का अहसास होगा और उनमें सुरक्षा की भावना का भी संचार होगा। l

बलूचिस्तान के समर्थन में भारत, पाक में हलचल

स्वाधीनता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाक अधिकृत बलूचिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी के बाद इस मामले ने पड़ोसी देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के चार प्रदेशों में से एक बलूचिस्तान की जनता पिछले 69 सालों ने पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों को सहन करती आ रही है। बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है और बंदूकों के दम पर जनता की आवाज को उसके हलक से भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उकसावे के कारण इन दिनों कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र कर पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलूचिस्तानी जनता की नारकीय जिंदगी पर टिप्पणी करने के बाद पाक प्रधानमंत्री की रातों की नींद हराम हो गई है। 15 अगस्त के बाद बलूचिस्तान के बहुत से नेता-संगठनों ने श्री मोदी से उनके आंदोलन का समर्थन करने और उनकी मांगों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की अपील की है ताकि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। मोदी की इस कूटनीति ने पाकिस्तान में बौखलाहट की स्थिति पैदा कर दी है। बलूचिस्तान के बलोच वुमन फोरम की अध्यक्ष नायेला कादरी ने टीवी चैनलों पर रक्षा बंधन के दिन नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताते हुए उनसे समर्थन की गुहार लगाई। नायेला ने कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, बस आपका सहयोग-समर्थन चाहिए। इसके अलावा विश्व के कोने-कोने में रहकर आंदोलन चला रहे विभिन्न बलूचिस्तानी नेताओं ने भी भारत के अर्थात नरेंद्र मोदी के उक्त कदम की सराहना करते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई।

इस बार स्वाधीना दिवस समारोह में श्री मोदी ने जो कूटनीतिक दांव खेला, उससे पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। अब तक पाकिस्तान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की स्वाधीनता और वहां हो रहे मानवाधिकार हनन का झूठा रोना रोकर भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करता आया है। मगर देश स्वाधीन होने के बाद यह पहला मौका है, जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया हो। देश-विदेश के किसी कूटनीतिज्ञ ने संभवत: सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान का जिक्र कर पाकिस्तान को उसके ही घर में विलेन बना देंगे। बलोच नेशनल मूवमेंट ने भी बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत की स्थिति का समर्थन किया। नेशनल मूवमेंट के प्रतिनिधि हलाल हाईदर बलोच ने कहा बलूचिस्तान के लोगों की सोच भारत के लोगों की सोच के साथ पूरी तरह से मिलती है। उन्होंने कहा कि बहुत से संगठन भारत से अपील कर चुके हैं कि वह बलूचिस्तान के स्वाधीनता संग्राम को अपना समर्थन दे, क्योंकि बलूच जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, जबकि पाकिस्तान अपने जन्म से ही आतंकवाद-कट्टरवाद का समर्थक रहा है। और तो और, पाकिस्तान की सरकार तथा सेना की छत्रछाया में आतंकवादी संगठनों के कट्टरवादी नेता वहां खुलेआम घूमते हैं, मगर उन्हें पकड़ कर सलाखों के पीछे डालने की किसी में हिम्मत नहीं है। मालूम हो कि बलूचिस्तान प्रदेश पाकिस्तान के स्वाधीन होने के पहले से ही एक स्वाधीन प्रदेश था। देखा जाए तो बलूचिस्तान की हालत भी बिल्कुल जम्मू-कश्मीर की तरह ही है। यह प्रदेश पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम प्रांत में स्थित है और इस प्रांत की राजधानी कुव्वैत है। 3,47,190 वर्गफुट में फैले इस प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1,31,62,222 थी। पाकिस्तान द्वारा 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद से ही वहां की जनता अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ती रही है। वहां की जनता ने 1948 के अलावा वर्ष 1958-59, वर्ष 1973-77, वर्ष 2004, वर्ष 2012 से लेकर अब तक स्वाधीनता हासिल करने की कई बार कोशिशें कीं और उनकी यह लड़ाई आज भी जारी है। 1

माजुली में कैबिनेट की बैठक जनता की उम्मीदें

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने विगत 8 सितंबर को विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को राज्य का 35वां जिला घोषित कर न सिर्फ माजुलीवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है, बल्कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को भी निभाया है। इस घोषणा के साथ ही इतने दिन उपेक्षित पड़े सत्रीया संस्कृति के केंद्र स्थल माजुली को एक अलग पहचान ही नहीं मिली है, बल्कि इस स्थान का महत्व भी चौगुना हो गया है। राज्य सरकार के इस कदम का राज्यवासियों ने खुले दिल से स्वागत किया है और साथ ही साथ यह उम्मीद भी जताई है कि माजुली के जिला सदर होने से इसका चहुंमुखी विकास संभव हो सकेगा। वैसे तो राज्यवासियों के लिए माजुली का एक अलग ही महत्व है, भौगोलिक नजरिए से भी इसका कमतर महत्व नहीं है।

माजुली को जिला घोषित कर देने से ही इस क्षेत्र अथवा यहां के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि ब्रह्मपुत्र की प्रबल प्रवाह से उत्पन्न कटाव की चपेट में आकर माजुली का एक बड़ा भू-भाग ब्रह्मपुत्र में समा चुका है और भूकटाव का यह सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में एक दिन माजुली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब तक के भूकटाव के कारण माजुली के हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर लोग खुले आकाश के नीचे अपना जीवन यापन करते हुए अच्छे दिन आने की बाट जोह रहे हैं। 'गैजेट ऑफ बंगाल एंड नार्थ ईस्ट इंडिया' में दर्ज जानकारी के अनुसार वर्ष 1951 में माजुली का क्षेत्रफल 485 वर्ग मील था, मगर भूकटाव के कारण वर्ष 2012 के आते-आते यह द्वीप-भूखंड 508.13 वर्ग किलोमीटर में सिमटकर रह गया है। हर साल एक बड़ा भूखंड कटाव की चपेट में आकर ब्रह्मपुत्र में लीन हो जाता है। आमतौर पर भूकटाव की जो तीव्रता रहती है, माजुली में कटाव की वह तीव्रता कई गुणा अधिक है। अब तक माजुली के 89 गांव हमेशा के लिए ब्रह्मपुत्र में समा चुके

हैं। इस साल भी कटाव के कारण माजुली के सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। नदी-द्वीप के विकास के लिए सरकार ने पर्याप्त आर्थिक मदद दी है, मगर इस मदद का सही मायने में माजुली के विकास में कितना सदुपयोग हुआ है, यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि पिछली सरकारों ने माजुली के विकास और भूकटाव के नाम पर अपने शासन काल में कितनी धनराशि खर्च की और उसका उपयोग कहां-कहां किया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। इसके अलावा राज्य सरकार को ऐसे कदम भी उठाने होंगे, जिससे माजुलीवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। माजुली को जिला घोषित किए जाने के बाद यहां विभिन्न सरकारी भवन-कार्यालय आदि का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि भवन-कार्यालय के निर्माण के बाद वह ठेकेदार-अधिकारियों से निर्माण कार्य में लागत धनराशि का पूरा हिसाब ले। यह बात याद रखनी चाहिए कि माजुली के विकास के नाम पर अब तक जिन ठेकेदार-अधिकारियों ने करोड़ों की राशि में हेरफेर किया है, वे लोग माजुली के ही नहीं, पूरे राज्य के गुनहगार हैं। राज्य के विकास में छिद्र करने वाले और यहां की प्राकृतिक संपदा लूटने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। माजुलीवासियों को बचाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और माजुली के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन करे।

माजुली को जिला घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री श्री सोनोवाल, वन मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म, परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और जल संसाधन मंत्री ने माजुलीवासियों के लिए जो घोषणाएं की हैं, जो आश्वासन दिए हैं-जनता उनके पूरा होने का इंतजार कर रही है। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि पहले की कांग्रेस और असम गण परिषद की सरकार ने माजुली के विकास और सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की थी, मगर हकीकत में ऐसी योजना का एक प्रतिशत काम भी नहीं हुआ। माजुली के विकास के नाम पर भ्रष्ट ठेकेदार-सरकारी अधिकारियों ने जमकर चांदी काटी। जो भी हो जनता यही चाहती है कि एक नया सूरज उगे और माजुली में एक नई सुबह का आगाज हो, जो माजुलीवासियों के लिए अपने साथ माजुली की समृद्धि और विकास का पैगाम लेकर आए। ।

पाक में हुक्मरानों का नहीं आतंकियों का शासन

भारत पर पाकिस्तान का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आक्रमण करना कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाने की बात कही थी, तब से ही पाकिस्तानी नेता भारतीय और भारत को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। एक तरह से यदि देखा जाए तो पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तानी नेताओं की राजनीति ही भारत विरोध पर टिकी है। भारत के प्रति पाकिस्तान की नापाक नीयत अब तक हुई कई लड़ाइयों में साबित हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा के बाद कारगिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा के बाद पठानकोट हमला बताता है कि पाकिस्तान के दिलो-दिमाग में भारत के प्रति कितना जहर भरा है। लोग कहते हैं पाकिस्तान को चाहे जिनता भी दूध पिला दें, वह अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही वहां के हुक्मरानों ने अपने देश की सुख-समृद्धि के लिए जितना दिमाग खपाया है, उससे अधिक दिमाग इस बात में खपाया है कि भारत को किस तरह से अस्थिर किया जाए, भारत को किस तरह से कमजोर किया जाए। अपने इसी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने कई अलगावादी नेता, कट्टरवादी संगठन और आतंकी संगठनों को जन्म दिया, उनको पाला-बड़ा किया। मगर ये संगठन भारत का बाल तक बांका नहीं कर सके। यह बात अलग है कि दूसरों के घर में आग लगाने के लिए तीली जलाने वाले पाकिस्तान को कई बार अपने हाथ झुलसाने पड़े हैं। उसके पैदा किए आतंकवादी उसी के लिए सिर दर्द साबित हुए हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान द्वारा पैदा किए गए ऐसे आतंकवादी संगठन एक बार नहीं, कई बार पाकिस्तान में खून-खराबा कर चुके हैं। पाकिस्तान जब भी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाज उठाता है अथवा कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो आतंकी उसका जवाब कराची, पेशावर, बलूचिस्तान, लाहौर आदि स्थानों में खून-खराबे के

माध्यम से देते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान खुद की ही लगाई आग में जल रहा है।

विगत 18 सितंबर को पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी औकात दिखाई। उसकी मदद से भारतीय सीमा में प्रवेश कर आतंकवादियों ने कश्मीर के एक सैन्य शिविर में सो रहे सैनिकों पर हमला कर कम-से-कम 20 सैनिकों की हत्या कर दी। इनमें से 17 जवानों के घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन जवानों का बाद में निधन हो गया। कुछ जवान हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए। बाद में तीन घंटे तक चली भीषण मुठभेड़ में चार पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद हुई जांच में यह बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाक सरकार की मदद और उसके सक्रिय सहयोग से अवैध रूप से भारतीय भूखंड में प्रवेश किया था। यह बात भी साबित हुई कि पाक अधिकृत कश्मीर से भारत में घुसे आतंकियों ने पाकिस्तान की परोक्ष शह पर ही भारतीय भूखंड पर हमला बोला था। विगत 15 सालों में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना पर किया गया यह भीषणतम हमला था। मालूम हो कि वर्ष 2002 में श्रीनगर से करीब 300 किलोमीटर दूर कालू चौक स्थित सेना के मुख्य कार्यालय पर तीन आत्मघाती हमलावरों ने हमला कर 30 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना में कई सैनिक तो अपने परिवार के साथ मारे गए थे। वर्ष 2014 में 5 दिसंबर को भी बारामुला में आतंकियों ने हमला कर 10 सैनिकों की हत्या कर दी थी। कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान हमेशा से ही तनाव फैलाता आया है। इसके बाद भी पाकिस्तान भारत से उक्त सभी घटनाओं के सबूत मांगता है और भारत द्वारा दिए सबूतों को कभी तो नाकाफी बताता है और कभी बेबुनियाद। भारत द्वारा अब तक कई सबूत उपलब्ध कराए जाने के बाद भी पाकिस्तान एक भी आतंकी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में खुले घूमते हैं, सभाएं करते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। फिर पाकिस्तान इनके वहां रहने-ठहरने से इनकार करता है। पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को पकड़ कर उन्हें जेल भेजने की जगह उनकी हिफाजत में ही लगा रहता है। ऐसे में यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पाकिस्तान पर वहां के हुक्मरानों का नहीं, आतंकियों का शासन चलता है। l

खिलौने के नाम पर बच्चों को हथियार ही क्यों ?

दुर्गा पूजा हो या अन्य कोई त्योहार, बच्चों के लिए खिलौने अति प्रिय उपहार होते हैं। इन खिलौनों में गुड्डे-गुड़िया, बैलून, हथियार, देवी-देवता, विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्र, रसोई के बर्तन, किसी मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली चिकित्सा उपकरण सहित ढेर सारी चीजें शामिल हैं। त्योहार पर जब तक बच्चों को ऐसे खिलौने नहीं मिल जाते, तब तक उनके बाल-मन को चैन नहीं मिलता। जब खिलौने मिल जाते हैं तो कई दिन तक बच्चे उन खिलौनों को अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। एक मनचाहा खिलौना पाने के लिए बच्चे अपने पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं और मनचाहा खिलौना हासिल करने के लिए वे अपने माता-पिता के अलावा घर के अन्य किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ते। खिलौना हासिल करने की जिद में कभी-कभी तो बच्चे की पिटाई तक हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार जीत बाल हठ की ही होती है। पूजा-पर्व के दौरान बच्चों का अपने माता-पिता से खिलौने की मांग करना अथवा जिद करना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हम सभी ऐसे दौर से गुजरे हैं और शायद ही कोई होगा, जिसने खिलौना खरीदने की जिद में अपने माता-पिता के हाथ से कभी न कभी मार न खाई हो।

समय के साथ खिलौने का रूप-रंग भी बदला है। अब बाजार में मिट्टी के बने खिलौने बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। मिट्टी की जगह प्लास्टिक ऑफ पेरिस ने ली है और प्लास्टिक के गुड्डे-गुड़िया की जगह चीन-जापान में निर्मित अत्याधुनिक हथियार की शक्ल वाले खिलौनों से बाजार भरा पड़ा है। ऐसे विदेशी खिलौने देखने में आकर्षक होते हैं। इसमें से रोशनी (रे) भी निकलती है और ये आवाज भी भरपूर करते हैं। ऐसे हथियार जैसे खिलौने आज के बच्चों की पहली पसंद हैं। अभिभावक भी बच्चों की पसंद और जिद को देखते हुए

हथियारनुमा खिलौने बच्चों को खरीदकर दे देते हैं। मगर इससे बच्चों के कोमल मन-दिमाग पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में किसी ने भी सोचा है क्या? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों के कोमल दिमाग पर किसी भी वस्तु का तुरंत प्रभाव पड़ता है। वैसे भी टीवी-सिनेमा में दिखाई जाने वाली हिंसा-मारकाट ने वैसे ही बच्चों को हिंसक बना दिया है, रही-सही कसर ऐसे हथियारनुमा खिलौने पूरी करने में लगे हैं। अभिभावकों के साथ बाजार गई बच्ची भी अब अपने मम्मी-पापा से गुड़िया अथवा रसोई घर में काम आने वाले बर्तनों की मांग नहीं करती और न ही बच्चे डॉक्टरी उपकरण खरीदना चाहते हैं। सामाजिक नजरिए से देखें तो यह स्थिति एक चिंताजनक भविष्य का संकेत देती है। बच्चा जब अपने घर-समाज, टीवी-सिनेमा में लड़ाई-झगड़ा, हिंसा-मारपीट ही देखता है तो उसका स्वभाव भी वैसा ही होने लगता है। वैसे भी मानव मन नकारात्मक बातों को अधिक आसानी से ग्रहण करता है। लिहाजा जब बच्चों को खिलौने के तौर लगातार हथियार रूपी खिलौने ही दिए जाते हैं तो बच्चे भी आहिस्ता-आहिस्ता हिंसक होने लगते हैं। उनके आचरण में बाल सुलभता नहीं रहती और कई बच्चे तो किशोर उम्र की दहलीज पर ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। बच्चों की ऐसी दुर्दशा के लिए माता-पिता को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। बच्चों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए अभिभावकों को ही जागरूक बनना पड़ेगा। बेहतर तो यही होगा, बच्चों को खिलौनेनुमा हथियार देने से बचा जाए। दुर्गा पूजा के मौके पर आप यदि अपने बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कुछ ऐसा खरीदकर देते हैं, जो उसके बौद्धिक विकास में मददगार हो तो आपका यह कदम न सिर्फ बच्चे के, बल्कि समाज के भविष्य के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। यदि आप अपने बच्चे को सीटी, बैलून अथवा मिट्टी-प्लास्टिक के खिलौने खरीदकर देते हैं तो अच्छा यही होगा कि उनके व्यवहार के बारे में अपने बच्चे को बताएं। मसलन, किसी दूसरे की सीटी को बिना साफ पानी से धोए मुंह में नहीं लेनी चाहिए अथवा खिलौने से खेलने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए आदि। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि बच्चों को खिलौने खरीदकर देने के अलावा उन्हें पैसों की बचत करने की भी शिक्षा दी जाए। l

चीन क्यों चाहता है भारत-पाक के बीच लड़ाई हो

भारत-पाकिस्तान के बीच के मौजूदा हालात में चीन की भूमिका को देखते हुए लगता है कि वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो। चीन की हरकतें भारत-पाक के बीच सुलगते रिश्तों के बीच आग में घी डालने जैसी लग रही है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के साथ-साथ चीन खुद भी भारत को घेरने की कोशिशों में लग गया है। भारत से लगती पाकिस्तान और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध सरीखी स्थित कहीं भारत को चौतरफा घेरने की तो नहीं है? 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद पिछले एक दशक में एशिया का पावर हाउस बना चीन उस पल की ताक में लगा है जब किसी भी बहाने भारत पर हमला किया जा सके। मगर चीन यह भी जानता है कि विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ चाणक्य के देश भारत पर आज के दिन इतनी आसानी से हमला नहीं किया जा सकता। आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं रह गया है। पिछले एक साल में भारत-चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन लाइन का अतिक्रमण कर चीन भारत के धीरज की परीक्षा ले चुका है। हर बार भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को जबरन उनकी सीमा में भेज देते हैं और भारत भी इस मामले को अधिक तूल देकर चीन को कोई मौका नहीं देता। कहना न होगा भारत इस पूरे मामले को लेकर बड़ी ही सावधानी के साथ फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रहा है।

चीन की हरकतों को देखकर लगता है कि वह बजाय भारत के साथ सीधी लड़ाई लड़ने के पाकिस्तान के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध कराने की सजिश में लगा है। यदि किसी भी सूरत में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कई मामलों में चीन भारत को ब्लैकमेलिंग कर सकेगा। चीन पाकिस्तान का खुला समर्थन कर एक तरह से भारत को चुनौती देने की कोशिश में लगा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने की प्रक्रिया में चीन जहां एक ओर सबसे बड़ी रुकावट खड़ी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने की

वकालत भी कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चीन ने भारत के विरोधी की भूमिका निभाई है, जबकि ठीक इससे उलट हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है।

दक्षिण महासागर जल सीमा विवाद में हाल ही में चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से उसका मनचाहा फैसला नहीं मिला है। इस मामले में भारत की भूमिका भी चीन के खिलाफ ही थी। भारत के इस कदम से चीन और भी तिलमिला उठा है। इसलिए चीन भारत से बदला लेने के लिए खुलेआम पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध करने के लिए न सिर्फ उकसा रहा है, बल्कि पाकिस्तान को अपनी ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहा है। चीन द्वारा पीठ थपथपाने के बाद से ही पाकिस्तान भारत को अपनी गीदड़ घुड़की देने में लगा है। वैसे भी चीन इस गलतफहमी में है कि भारत-पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध छिड़ता है तो उस स्थिति में चीन के लिए भारत पर युद्ध थोपना आसान हो जाएगा। 1962 में तो चीन ने भारत पर बड़ी आसानी से हमला कर दिया था, मगर आज का भारत पहले जितना कमजोर नहीं है और चीन यह बात अच्छी तरह से जानता है। आज का शक्तिशाली भारत चीन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

पाकिस्तान और चीन की मित्रता दोनों ही देशों के हितों पर टिकी है। चीन आज के दिन पाकिस्तान को नागरिक वस्तुओं की ही नहीं, सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति करने में लगा है। और तो और, पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने में भी चीन ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। सैन्य परीक्षण में भी चीन परोक्ष रूप से पाकिस्तान का सहयोग करते आया है। इसके एवज में चीन ने पाकिस्तान के बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है। चीन को पाकिस्तान में अपना माल बेचने के लिए एक तैयार बाजार मिल गया है, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। संयुक्त राष्ट्र के पटल पर अमरीका सहित विश्व के तमाम बड़े देशों ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने की मांग की, मगर चीन ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से ही रोक दिया। इससे पहले भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को उक्त प्रस्ताव दिया था, जो चीन की कारस्तानियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया था। 1

आतंवाद के खिलाफ भारत-रूस हुए लामबंद

भारत के साथ रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। पिछले कई सालों में भारत-अमरीका के बीच मधुर संबंध बन जाने की वजह से रूस ने भारत से कुछ दूरी बना ली थी, मगर अब एक बार फिर दोनों देशों के शीर्ष नेता अपने पुराने संबंधों को सजीव करना चाहते हैं। गोवा में हाल ही में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के संबंध में यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि एक पुराना मित्र दो नए मित्रों से बेहतर होता है। श्री मोदी के इस बयान ने जहां एक ओर भारत-रूस को एक-दूसरे के और करीब ला दिया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान-चीन के ललाट की सिलवटों को और भी गहरा कर दिया है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान ने रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर पूरी दुनिया के सामने यह डींग हांकी थी कि रूस अब उसके साथ है। मगर मोदी के बयान ने तो पाकिस्तान की हवा ही निकाल कर रख दी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जारी साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के जिक्र से जहां एक ओर रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, वहीं दूसरी ओर चीन को भी उसी बयान के पक्ष में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। यह बात अलग है कि साझा बयान जारी होने के कुछ ही घंटों बाद चीन ने यह बयान जारी कर सनसनी फैला दी कि आतंकवाद को किसी देश अथवा धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन के आयोजन को रद्द कराकर कूटनीति में पहली जीत हासिल करने वाला भारत ब्रिक्स में अपनी अगली कौन-सी कूटनीति चाल चलता है, देखने लायक होगा।

इस सम्मेलन में न सिर्फ भारत-रूस के संबंधों की नई सिरे से समीक्षा होनी थी, बल्कि रूस के साथ हजारों करोड़ रुपए के रक्षा सौदे भी होने थे। इस स्थिति को सुखद नतीजों में बदला जा सके इसके लिए श्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले से ही एक-दूसरे के संपर्क में थे। नरेंद्र मोदी एक बात को लेकर शुरू से ही निश्चित थे कि रूस भले ही पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करे, मगर रहेगा हमेशा भारत के पक्ष में। रूस ने इस बार भी अपने पुराने मित्र भारत

को निराश नहीं किया। याद दिला दें कि 1962 में जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव लिया था, उस वक्त रूस ने भारत के पक्ष में मतदान किया था। तब भी रूस के इस निर्णय की पूरी विश्व बिरादरी में चर्चा हुई थी। आज भी भारत के लोग रूस के साथ दोस्ती चाहते हैं। भारत ने जब पहली बार अपना उपग्रह 'आर्यभट्ट' छोड़ा था, उस वक्त भी रूस का सहयोग-समर्थन भारत के पक्ष में रहने की वजह से यह काम आसानी से हो पाया था। इसके बाद दोनों मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से कई उपग्रह प्रक्षेपित किए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) और रसियन फेडरल स्पेस एजेंसी एक साथ मिलकर अगले साल 'चंद्रयान-2' प्रक्षेपण करेगी। रूस ने 1962 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद में 'वीटो' का उपयोग कर गोवा को पुर्तगाल के उपनिवेश में जाने से बचाया था। 1961 तक गोवा पुर्तगाल के ही अधीन था। जब पुर्तगालियों ने गोवा से जाने से मना कर दिया था, तब भारत ने अपनी सेना को वहां भेजा था। कई पश्चिमी देशों ने भारत को युद्ध से दूर रहने की धमकी दी थी। भारत के इस कदम के खिलाफ साधारण परिषद में लिए गए प्रस्ताव के पक्ष में अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पश्चिम जर्मनी और आमंत्रित पाकिस्तान ने भी वोट डाला था, मगर रूस ने वीटो लगाकर इस प्रस्ताव को धराशायी करने का काम किया।

भारत को हथियार बेचने के मामले में रूस हमेशा से ही अमरीका से आगे रहा है। भारत की जरूरत की 70 फीसदी युद्ध सामग्री की आपूर्ति रूस ही करता आया है। मिग-29 युद्धक विमान से लेकर अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति रूस ही करता आया है। ब्रिक्स सम्मेलन में इसी व्यापारिक परंपरा को आगे बढ़ाया गया। श्री मोदी और श्री पुतिन की उपस्थिति में युद्ध सामग्री से संबंधित एक बड़ा सौदा होने के साथ ही दोनों के बीच की दोस्ती का प्रगाढ़ रूप एक बार फिर दुनिया के सामने आया। जहां तक रूस का सवाल है तो वह भी चाहता था कि भारत के साथ उसके प्रगाढ़ संबंध बरकार रहें, क्योंकि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत ही ऐसा देश है, जो रूस से सबसे अधिक युद्ध सामग्री की खरीददारी करता है। रूस जहां भारत से आर्थिक फायदे की उम्मीद रखता है, वहीं भारत रूस को संकट काल में काम आने वाले मित्र के तौर पर मानता है। ऐसे में भारत-रूस की दोस्ती के बीच कोई आड़े नहीं आ सकता। न पाकिस्तान और न ही चीन। ।

असम की धरोहर है सुधाकंठ

डॉ. भूपेन हजारिका को यदि असम की जातीय धरोहर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साहित्य-संगीत-कला के क्षेत्र में इस महान कलाकार के अतुलनीय योगदान ने पूरे विश्व में असमिया जाति को एक पहचान प्रदान की है। जब वृहत्तर असमिया जाति संकट के दौर से गुजर रही थी, उस घड़ी भूपेन दा ने अपने गीतों के माध्यम से, अपनी रचनाओं से राज्य में निवास करने वाली सभी जाति, जनजाति-जनगोष्ठी के लोगों के बीच समन्वय सेतु बनाने का काम किया था। पहाड़ी-मैदानी राज्यवासियों के बीच आपसी भाईचारे की डोर को मजबूत करने में भूपेन दा कुछ हद तक सफल भी रहे थे। उनमें हर एक व्यक्ति के मन को टटोल पाने की अद्‌भुत क्षमता थी। आम लोगों के लिए जीने-मरने की ललक रखने वाले सुधाकंठ राज्य के सभी जाति-जनजाति और जनगोष्ठियों की नाराजगी और मन में छिपे क्षोभ को बेहतर ढंग से समझते थे। उनका एक ही मकसद था, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना। इसलिए उनके गीतों में बार-बार पहाड़ी लोगों की सहज-सरलता और भोलेपन का जिक्र आता है। मनुष्य और मिट्टी के साथ गहरे लगाव की वजह से ही उनके गीतों में कच्ची मिट्टी की खुश्बू आती है। यही वजह है जाति और माटी से जुड़े रहने वाले भूपेन दा देश-विदेश में जहां कहीं भी गए, लोगों ने उन्हें अपने सर-माथे पर लिया।

सुधाकंठ भूपेन हजारिका को लेकर हम असमवासियों की संवेदनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। वैसे भी किसी भी मसले को लेकर जब भी कोई विवाद होता है, हम सभी संवेदनशीलता की लहरों में डूबने-उतरने लगते हैं। हम अत्यधिक संवेदनशील हैं और वैसा जब भी कोई मौका आता है, हम खुद को संभाल नहीं पाते। सुधाकंठ की चिर विदाई के समय भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। उनके चले जाने के गम में पूरा राज्य आंसुओं की बाढ़ में डूबा हुआ था। तब का आलम यह था कि राज्यवासी-राज्य के विभिन्न संगठनों ने भूपेन दा

के नाम पर तरह-तरह की योजनाएं हाथों में लेने की या तो सरकार से मांग की थी अथवा स्वयं करने की घोषणा की थी। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि राज्य में शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जो सुधाकंठ को असम की जातीय धरोहर न मानता हो। मगर इसके बाद क्या हुआ। समय के साथ-साथ लोगों की संवेदनाएं और मांगें मंद पड़ने लगीं और भूपेन दा के नाम पर विभिन्न संगठनों ने जितनी भी योजनाओं की घोषणा की थी, उनमें से अधिकतर योजनाएं आधे रास्ते में ही धराशाई हो गईं। तब कुछ संगठनों ने यह भी मांग की थी कि सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भूपेन दा के कालजयी गीत हमेशा बजते रहें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, मगर इस मांग पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। भूपेन दा के जाने के बाद उनके गीतों को जिस तरह से विकृत किया जा रहा है, वह एक चिंता का विषय होना चाहिए था। यह सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहा तो आने वाली पीढ़ी को हम असम की जातीय धरोहर हमारे भूपेन दा के बारे में कैसे बता पाएंगे। हम में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिनको नहीं पता कि डॉ. भूपेन हजारिका के गाए गीतों को भूपेंद्र संगीत कहा जाता है। जबकि यदि कोई कलाकार बिना तैयारी के रवींद्र संगीत गाने के लिए मंच पर खड़ा भर हो जाए तो हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा हो जाता है। लिहाजा असम की जातीय धरोहर समझे जाने वाले भूपेंद्र संगीत को लेकर हमें संजीदा रहना चाहिए।

डॉ. भूपेन हजारिका के लोकप्रिय गीतों को यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर नियमित रूप से बजाया जाए तो इसमें किसी को नुकसान नहीं होने वाला। वैसे भी भूपेन दा के इतने गीत हैं कि आज जिस गीत को बजाया-सुनाया जाएगा, उसकी अगली पारी आने में महीनों लग जाएंगे। भूपेन दा के गीत-गाने पसंद करने वाले श्रोताओं को भी एक ही गीत लगातार नहीं सुनने पड़ेंगे। सुधाकंठ के निधन के बाद इस प्रकार का प्रस्ताव कई संगठनों की ओर से लाया गया था, मगर उस पर आगे बात नहीं बन सकी। राज्य सरकार अथवा उसका संबंधित विभाग इस प्रस्ताव पर चिंतन करे तो यह भूपेन हजारिका को याद करने की एक शानदार पहल हो सकती है। ।

रंगीन रोशनियों के बीच मिट्टी के दीये की तलाश

दीपावली का मतलब ही है रंग-बिरंगी रोशनी और पटाखों की आवाज। दीपावली की रात हर एक घर के दरवाजे पर कतार में प्रज्ज्वलित दीयों को देखकर सभी का मन आनंद से भर उठता है। लोग पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी छोड़कर अपनी इस खुशी का इजहार करते हैं। दीपावली की रात भर पूरा देश पटाखों की आवाज से गूंजता रहता है। पटाखों की आवाज इतनी तेज होती है कि पास बैठे दो लोग भी अपनी बातें नहीं सुन सकते। ऐसी आतिशी रोशनी और पटाखों के धूम-धड़ाकों के बीच हम देशवासी दीपावली का पर्व मनाते हैं। दीपावली के मौके पर देश भर में ही नहीं, विश्व के अन्य कई देशों में भी रोशनी का पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे धार्मिक विश्वास और सदियों से चली आ रही परंपाएं दोनों ही जुड़े हैं।

मगर आज दीपावली का अर्थ बदल गया है। दीपावली के मौके पर अधिक से अधिक कानफोडू आवाज करने वाले पटाखे फोड़ने की एक-दूसरे में होड़ मच जाती है। इन दिनों प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है और किसी-किसी जगह पर तो यह खतरे के निशान तक को पार कर जाती है। आज के दिन वैसे ही पूरी दुनिया प्रदूषित हो चुकी है। वायु-पानी, भूमि-आकाश हम मनुष्यों के गैर-जिम्मेदाराना कार्यों की वजह से प्रदूषित हो चुके हैं। प्रदूषित वातावरण सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में दीपावली के मौके पर की गई आतिशबाजी और फोड़े गए पटाखों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषित वातावरण और भी अधिक जहरीला हो जाता है। आज से दो दशक पहले दीपावली के मौके पर छोड़े जाने वाले पटाखे-आतिशबाजी से उत्पन्न धमाकों की वजह से वातावरण जितना प्रदूषित होता था, आज उसका प्रभाव उससे कई गुणा अधिक पड़ने लगा है। प्रदूषण को लेकर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से इंसानों को सबसे अधिक

मूल्य चुकाना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, दमा, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक होने लगी हैं। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों में ग्रीन दीपावली मनाने की एक नई सोच पनपने लगी है। ग्रीन दीपावली का अर्थ है बिना पटाखे-आतिशबाजी छोड़े, बिना शब्द-प्रदूषण फैलाए सिर्फ मिट्टी के दीये जलाकर श्रद्धापूर्वक दीपावली मनाना।

आज यदि बाजार पर नजर डालें तो पूरा बाजार चीन निर्मित सामग्री से पटा पड़ा है। रंग-बिरंगे बल्बों की लड़ियों से लेकर बिजली के अन्य सजावटी उपकरण, रंग-बिरंगे दीये, पटाखे-आतिशबाजी और तो और गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां तक चीन से आने लगी हैं। बाजार की स्थिति ऐसी हो गई है कि लाख खोजने पर भी भारतीय गांवों के कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीये अथवा पटाखे-आतिशबाजी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वैसे पूरे देश में शिव-काशी के पटाखे जितने लोकप्रिय हैं, हमारे राज्य में नगांव-बरपेटा में बने पटाखे भी उससे कम लोकप्रिय नहीं हैं। मगर चीन से आयातित रंगीन रोशनियों के बीच हमारे मिट्टी के दीयों को खोज निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। चीन निर्मित रंग-बिरंगे बल्बों की झालरें तथा रोशनी से अठखेलियां करने वाले बिजली के उपकरणों ने हम सभी को अपने मोहपाश में इस कदर जकड़ लिया है कि हम मिट्टी के दीये प्रज्ज्वलित करना भूल-से गए हैं। हकीकत यह है कि आज कल हम चीन निर्मित बिजली की झालरों से दीपावली मनाते हैं और शगुन के तौर पर अपने घर के सामने दो-चार दीये जला देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन निर्मित बिजली की झालरें अथवा अन्य रोशनी की सामग्री आकर्षक व सस्ती होती है, मगर यह भी सच है कि ऐसी सामग्री के अत्यधिक उपयोग ने दीपावली के आनंद-उमंग को काफी हद तक प्रभावित किया है। पहले घर के सामने कतार में जलते दीयों में तेल डालने अथवा बार-बार जलाने के लिए गृहस्थ को पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ती थी, मगर अब बिजली के एक स्वीच ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। चीन के पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोधी हरकतों की वजह से देश में चीन के खिलाफ गुस्सा उबाल पर है। लोग चीनी सामग्री के बहिष्कार की एक-दूसरे से अपील कर रहे हैं । इन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो रोशनी से डूबी रंगीनियों में एक अदद मिट्टी के दीये की तलाश कर रहे हैं, जो अपने दम पर अमावस्या की काली रात को चुनौती दे सके। l

गुजर गया पूजा-पर्व का मौसम अब साफ-सफाई की बारी

राज्यवासियों ने पिछले दिनों बड़ी ही श्रद्धापूर्ण सूर्य उपासना का पर्व छठ का महात्योहार मनाया। इसी के साथ यदि देखा जाए तो पिछले दो महीने से चला आ रहे हिंदुओं के त्योहार-पर्व का एक सिलसिला पूरा हुआ। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के साथ हिंदुओं के पर्व-त्योहार की शृंखला शुरू हुई थी। पिछले दो महीने से जारी त्योहार-पर्व का सिलसिला तो खत्म हो गया, मगर त्योहार के नाम पर महानगर में जहां-तहां जमे गंदगी के ढेर आज भी पूरी तरह से हटाए नहीं गए हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे विश्वकर्मा-काली-लक्ष्मी की टूटी-फूटी मूर्तियां हमारी धार्मिक संवेदनहीनता को ही नहीं दर्शातीं, बल्कि यह भी बताती है कि हम साफ-सफाई के प्रति कितने लापरवाह हैं।

दुर्गा पूजा-दीपावली के मौके पर लोगों ने अपने घरों की सफाई तो कर ली, लेकिन घर का सारा कचरा मोहल्ले की गलियों के अलावा जहां-तहां फेंक दिया। उसमें से कुछ कचरा तो संबंधित विभाग द्वारा उठा लिया गया तो कई जगह अभी भी कचरा बिखरा पड़ा है। दीपावली के मौके पर फोड़े गए पटाखों से उत्पन्न कागज की चिंदियों को आज भी जहां-तहां बिखरे हुए देखा जा सकता है। दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाली पूजा समितियों को ऐसी गंदगी को साफ करने के विशेष प्रयास

करने चाहिए थे। इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा भी समुचित व्यवस्था ली जानी चाहिए थी। दुर्गा पूजा-छठ पूजा से पूर्व पूजा समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन ने साफ-सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने का विशेष रूप से आग्रह किया गया था, मगर लगता है प्रशासन के उक्त आग्रह को गंभीरता से नहीं लिया गया। दरअसल साफ-सफाई का मसला प्रशासन की अपील अथवा कड़ाई से जुड़ा मुद्दा है ही नहीं। गली-मोहल्ले की साफ-सफाई की भावना स्वत: आनी चाहिए। वैसी हालत में जब पूजा-पर्व के नाम पर कहीं कचरे का ढेर लगता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी नैतिक रूप से पूजा समितियों पर ही आती है। छठ पर्व से पहले घाट की सफाई और दुर्गा पूजा से पहले मंडप तक पहुंचने वाले रास्तों की सफाई के कार्यक्रम तो आयोजित किए जाते हैं, मगर धार्मिक कार्यक्रम के खत्म होते ही बाद की सफाई की बात को पूरी तरह से भुला दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि महानगर की कोई भी पूजा समिति साफ-सफाई को गंभीरता से नहीं लेती। कुछ समितियां हैं, जो साफ-सफाई पर भी संपूर्ण ध्यान देती हैं, मगर इस कार्यक्रम को एक अभियान का रूप दिए जाने की जरूरत है। पूजा-पर्व के गुजर जाने के बाद आने वाले पहले रविवार को सफाई दिवस के रूप में चुना जा सकता है। इस दिन यदि मोहल्ले के सभी पुरुष-महिला, युवा-बच्चे सफाई अभियान में हिस्सा लें तो मोहल्ले को साफ-सुथरा रखा जा सकता है। सिर्फ पूजा-पर्व के दौरान ही क्यों, महीने में किसी एक रविवार को ऐसा सफाई कार्यक्रम कर मोहल्ले को हमेशा साफ-सुथरा रखा जा सकता है। इस विचार को आगे बढ़ाने अथवा और भी अधिक परिष्कृत करने में जिला प्रशासन और गुवाहाटी नगर निगम भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने मोहल्ले को साफ रखने वालों को पुरस्कृत अथवा उनका अभिनंदन कर अन्य मोहल्ले वालों को भी अनुप्रेरित किया जा सकता है। यह बात समझ लेना बेहतर होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई के लिए बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। हमारे आस-पास की सफाई हमें स्वयं आगे बढ़कर करना होगा। चाहे वह सफाई पूजा-पर्व के बाद की हो अथवा नियमित रूप से की जाने वाली। ।

परिवर्तन की लहर : मोदी से ट्रम्प तक

नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब पूरे विश्व की नजर उन पर टिकी थी। देश-विदेश में चर्चा का बाजार गर्म था कि श्री मोदी समाज के सभी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई पड़ोसी देशों की मनमानी, आतंकवादियों के खिलाफ लगातार लड़ी जाने वाली लड़ाई और देश के समक्ष मुंह बाए खड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। पिछले ढाई साल में श्री मोदी ने कदम दर कदम यह साबित कर दिया कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। देश के विकास के लिए वे किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार हैं। देशहित में अधिक से अधिक काम कर सकें, इसके लिए श्री मोदी न सिर्फ कम भोजन करते हैं, बल्कि कम नींद भी लेते हैं। यह भी खबर आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो समय बचाने के लिए यात्रा के दौरान अपने विशेष विमान में ही नींद पूरी कर लेते हैं। श्री मोदी संभवत: लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि राष्ट्र की बागडोर जिसके हाथों में है, वही यदि खाने-सोने में वक्त पूरा करने लगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। भारत को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने और विश्व भर में देश का सम्मान-ताकत बढ़ाने के लिए श्री मोदी ने अब तक जितने भी कदम उठाए हैं, विश्ववासियों ने उसकी जमकर तारीफ की है।

भारत-पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे देश में घुसपैठ कर हमारे सैनिकों पर हमला कर उनकी हत्या करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के शिविरों को तबाह कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि कोई उसकी ओर बुरी नजर डालने की जुर्रत न करे। सिर्फ यही नहीं, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर फैलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे पर श्री मोदी ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह से घेरा कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व भर में अलग-थलग पड़ गया है। नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ उनके ही देश में आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी

पार्टी के नेता तथा पूर्व क्रिकेटर इमरान खान अपने ही प्रधानमंत्र की नेक नीयती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ श्री मोदी द्वारा चली गई इस कूटनीतिक चाल की पूरे विश्व भर में सराहना की गई। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक सरकार द्वारा बलूच लोगों पर किए जा रहे अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को सार्वजनिक कर भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान के लोगों का समर्थन कर उन्हें नैतिक बल भी प्रदान किया। पिछले सप्ताह से प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की नई मुद्रा नीति के तहत देश में 500 और 1000 रुपए को बदलने के नाम पर काला बाजारियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उसका देश की 95 प्रतिशत जनता समर्थन कर रही है। परिवर्तन की लहरों पर सवार होकर देश को समृद्ध करने की श्री मोदी ने जो नीति अपनाई है, उस पर यूरोपियन देश भी नजर रखे हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, नई मुद्रा नीति और जापान के मामले में श्री मोदी ने जो साहसिक कदम उठाए हैं, उससे यूरोपीय देशों में भारत की साख और सम्मान दोनों ही बढ़ा है।

श्री मोदी का अनुकरण करते हुए विश्व का सुपर पावर कहे जाने वाले अमरीका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का जिक्र कर, यह बता दिया कि आज की घड़ी में विश्व मंच पर भारत पहली पांत में खड़ा है। श्री मोदी ने परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की, उसकी चर्चा अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी सुनी गई। अपनी एक चुनावी कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हिंदी में यह नारा लगाते हुए देखा गया 'अबकी बार ट्रम्प की सरकार'। अब अमरीका की बगाडोर ट्रम्प के हाथों में है। उन्होंने भी कभी छुट्टी न लेने और एक डॉलर वेतन पर काम करने की घोषणा की है। अब मोदी-ट्रम्प का गठजोड़ आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ किस नीति पर काम करेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जबकि भारत की नजर इस पर है कि ट्रम्प के शासन काल में अमरीका-पाक संबंध किस तरह से करवट बदलते हैं। l

नोटबंदी : जनता से संसद तक खलबली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात जब सभी टीवी चैनलों पर मंगलवार मध्य रात्रि के बाद से 1000-500 रुपए के नोटों को अमान्य करार दिए जाने की घोषणा तो जनता से लेकर जननेता तक में खलबली मच गई। 9-10 नवंबर को बैंक-एटीएम बंद घोषित किए गए और उसके बाद से अब तक पूरा देश बैंक-एटीएम के बाहर कतार में खड़ा है। किसी के पास बेटी की शादी करने के पैसे नहीं हैं तो किसी ने इसलिए अस्पताल में दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पताल वाले 500-1000 रुपए के नोट लेने को तैयार नहीं थे और मरीज के परिवार वालों के पास देने के लिए छोटे नोट नहीं थे। अपने ही पैसे बदलने अथवा लेन-देन के लिए देश की जनता रात-रात भर कतार में खड़ी रही। नोटबंदी की घोषणा का एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी जनता को राहत नहीं मिली है। सभी परेशान हैं। इसके बावजूद पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा कर एक साहसी और सही कदम उठाया है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने भी स्वागत किया है। इसके बावजूद नोटबंदी को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। जनता से लेकर जननेता तक अमीर से लेकर गरीब-मजदूर तक की यह शिकायत भी सही लगती है कि इतना बड़ा फैसला करने से पूर्व सरकार को जितने बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी थी, सरकार वैसी तैयारियां करने में असफल रही। इसी को लेकर जनता से संसद तक में बवाल मचा हुआ है। संभवत: सरकार को अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद देश में इस तरह की अफरा-तफरी का माहौल बन सकता है। घोषणा के बाद के पहले तीन दिन तक पूरे देश में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। विपक्ष को भी समझ में

नहीं आ रहा था कि इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मगर बाद में सरकार की तैयारियों से जुड़ी खामियां भी सभी के सामने आने लगीं। देश भर की करीब दो लाख एटीएम से नए 2000 और 500 के नोट न मिलने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दलील दी गई कि एटीएम के अंदर लगे चेस्ट को बदलने की जरूरत थी और यह बात पहले ही लीक हो जाती तो संभवत: नोटबंदी की बात भी पहले ही लीक हो जाती। मगर सरकार के पास इस बात की कोई दलील नहीं कि नोटबंदी के कई दिन बाद माइक्रो एटीएम, मोबाइल एटीएम, स्वीप कार्ड, पेट्रोल पंप-बिग बाजार पर डेविड कार्ड के माध्यम से नकदी भुगतान जैसे कदम उठाने की घोषणा की गई, वैसी घोषणा नोटबंदी के साथ ही क्यों नहीं की गई। नोटबंदी के दौरान सरकार, बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समन्वय की कमी भी उभरकर सामने आई। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा शादी वाले घर-परिवार को संबंधित बैंक से ढाई लाख रुपए की नकदी निकाल पाने की घोषणा किए जाने के दो दिन बाद तक उनकी घोषणा पर सिर्फ इसलिए अमल नहीं हो पाया, क्योंकि रिजर्व बैंक की अधिसूचना बैंकों तक पहुंची ही नहीं थी। इस वजह से भी लोगों में सरकार और बैंकों के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिली। नोटबंदी की घोषणा का एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी देश भर में स्थिति सुधरी नहीं है। महानगर और बड़े शहरों की स्थिति में आए मामूली बदलाव को देश भर में आए बदलाव के रूप में देखना गलत होगा। दिन गुजरने के साथ ही लोगों की समस्याएं-दुश्वारियां भी लंबी होती जा रही हैं। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए जल्द से जल्द तोड़ निकालना होगा। यह स्थिति यदि अधिक लंबी चली तो जनता का गुस्सा भड़क भी सकता है। कहना न होगा विपक्षी पार्टियां भी जनता की इन्हीं परेशानी-गुस्से को हथियार बनाकर सरकार से दो-दो हाथ करना चाहती हैं। विपक्ष यह नहीं कह रहा कि सरकार का नोटबंदी का फैसला गलत है, विपक्ष का सरकार पर आरोप यह है कि बिना पूरी तैयारी के नोटबंदी की घोषणा करने से आम जनता परेशान है और सरकार इसकी जिम्मेदारी-जवाबदेही से नहीं बच सकती। 1

भगवान भरोसे है वन्य जीवों की सुरक्षा

जोरहाट जिले के कारेंग चापरी के बाघमारा में विगत 24 नवंबर को लोगों द्वारा एक तेंदुए की पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने और इससे ठीक एक दिन पहले शोणितपुर जिले के बालीपार में पतंजलि फूड पार्क में बने गड्ढे में गिरकर एक हथिनी की मौत हो जाने की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सचमुच में ही असम के वन्य जीवों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे ही रह गई है। पशु तस्करों के हाथों गैंडे-हाथियों का मारा जाना आम घटना थी, मगर गांव के आम लोगों द्वारा तेंदुए को पीट-पीट कर मार डालने की घटना चिंताजनक है। लोगों में बढ़ता हिंसा का यह भाव आगे चलकर समाज की शांति-सद्भावना में खलल डाल सकता है।

24 नवंबर को जब पूरे राज्यवासी वीर लाचित को स्मरण कर लाचित दिवस मना रहे थे, उसी दिन जोरहाट जिले के एक अंदरुनी गांव में वन विभाग के अधिकारी-जवानों की उपस्थिति में गांव के कुछ लोग एक तेंदुए को बुरी तरह से पीटने में लगे थे। लोगों ने तेंदुए को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारी सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं कर सके। घटनास्थल पर उपस्थित वन विभाग के अधिकारी-जवान इसके लिए प्रशिक्षित ही नहीं थे कि ऐसे मौके पर लोगों की उत्तेजित भीड़ को किस तरह से संभाला जाए। लिहाजा देखते-ही-देखते गांव वालों ने एक दुर्लभ वन्य जीव को मार डाला। बताया जाता है कि तेंदुए द्वारा गांव के तीन लोगों को घायल किए जाने के बाद गांव के लोगों ने वन विभाग तथा पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी, मगर वन विभाग और पुलिस अधिकारी काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचे। गांव के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से तेंदुए को वापस जंगल में खदेड़ देने की मांग भी की थी, मगर वन विभाग के अधिकारियों ने हवा में कई गोलियां दागकर ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लिया। गांव वालों ने यह भी गुहार लगाई कि तेंदुए की पहरेदारी

की ही व्यवस्था कर दे, मगर वन विभाग ने अपने हाथ उठा दिए। इसके बाद गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया और सभी हिंसक तरीके से तेंदुए पर टूट पड़े। गांव वालों का गुस्सा जब चरम पर था, वन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। उनकी निष्क्रियता इस बात का सबूत था कि ऐसे हालात पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसकी उन्हें संपूर्ण जानकारी-प्रशिक्षण नहीं था। ऐसे वन अधिकारियों को देखकर यह ख्याल आता है कि ये लोग वन्य जीवों को बचाने-उनके संरक्षण के लिए नहीं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नौकरी करते हैं। हमारे देश में वैसे ही तेंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, इसकेबावजूद हम अगर तेंदुए की रक्षा नहीं कर पाए तो एक दिन यह वन्य प्राणी भी दुनिया से विलुप्त हो जाएगा।

इस घटना से एक दिन पहले शोणितपुर जिले के बालीपार में बनने जा रहे पतंजलि फूड पार्क में बने गड्ढे में एक हथिनी अपने शावक के साथ गिर पड़ी और वन विभाग के अधिकारी दिन भर कोशिशें करने के बाद भी उस हथिनी को नहीं बचा सके। वन विभाग की इससे बड़ी निष्क्रियता और असफलता और क्या होगी। हथिनी का शावक दिन भर अपनी मां से लिपट-लिपटकर चिंघाड़ता रहा, मगर वन विभाग की सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। इस घटना ने भी यह साबित कर दिया कि हमारे निकम्मे वन विभाग के पास गड्ढे में गिरे हाथी तक को निकालने की क्षमता नहीं है। हमारे यहां हाथी-मनुष्य का टकराव कोई नई बात नहीं है। वनों के सिकुड़ने और वनांचलों में लोगों के जा बसने की वजह से हाथियों के लिए विचरण भूमि कम पड़ने लगी है। इसके अलावा जंगली हाथी खाने की तलाश में अक्सर जंगल से निकलकर जनबस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। हाथियों के झुंड के इस बिन बुलावे आगमन की वजह से गांव वालों को नुकसान उठाना पड़ता है। मगर 23 नवंबर की घटना का इन सभी कारणों के साथ कोई संबंध नहीं था। विभिन्न वनांचलों में हाथियों की आवाजाही (एलिपेंट कॉरिडोर) के रास्ते पर जब भी किसी प्रकार की रुकावट डाली जाती है अथवा गड्ढा खोदा जाता है तो मासूम हाथियों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। हरे-भरे जंगल, ऊंचे-ऊंचे पर्वत और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की विचरण भूमि के रूप में विश्व भर में विख्यात असम में वन्य जीवों की सुरक्षा को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ।

कैशलेस चुनाव से भी लगेगी काले धन पर लगाम

हमारे देश में चुनाव के नाम पर पांच साल के अंतराल पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह पहली शर्त है कि एक निश्चित समयावधि में आम जनता को मतदान के माध्यम से सरकार चुनने का मौका उपलब्ध कराया जाए। इस चुनावी प्रक्रिया को संपूर्ण करने में जो धनराशि खर्च होती है, वह भी आम जनता की होती है। इसके बावजूद चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अथवा उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत तय करने और आम मतदाताओं की नजर में आने के लिए अनाप-सनाप पानी की तरह पैसे खर्च करते हैं। यहां तक की अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए कई उम्मीदवार तो मतदाताओं को गुपचुप तरीके से भी पैसे देते हैं। इस तरीके से मतदाताओं को दिए जाने वाले पैसों का आमतौर पर संबंधित पार्टी अथवा उम्मीदवारों के पास कोई हिसाब नहीं होता। कभी-कभी मतदाताओं को गुपचुप ढंग से चुकाई जाने वाली राशि एक करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। ऐसे पैसों का चूंकि कोई हिसाब-किताब नहीं होता, लिहाजा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव खर्च के लिए तय की गई राशि में यह पैसे नहीं जोड़े जाते हैं। हकीकत में यदि देखा जाए तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टी

अथवा उम्मीदवार को जो तय रकम सीमा दी जाती है, चुनाव में उससे कई गुणा अधिक धनराशि खर्च की जाती है। हमारे देश का कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार इस आरोप से मुक्त नहीं है। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, राज्यसभा से लेकर पंचायत स्तर के चुनावों में भी इसी तर्ज पर पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं। चुनाव के नाम पर इस तरह से किए जाने वाले खर्च पर लगाम लगाने का वक्त अब आ गया है। सरकार अथवा चुनाव आयोग इस मामले में एकजुट होकर सही कदम उठाए, चुनाव में पैसे खर्च करने का एक नियम तय करे तो इस तरह से काले धन के लेन-देन पर अंकुश लगाया जा सकता है।

भविष्य में यदि कैशलेस चुनाव की अवधारणा को अमली जामा पहनाया जा सका तो चुनाव के नाम पर हुए पूरे खर्च की पाई-पाई का हिसाब निकाला जा सकता है। चाहे वह खर्च सरकार अर्थात चुनाव आयोग ने किया हो अथवा राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार ने। बैंक स्टेटमेंट में कैशलेस लेन-देने संबंधी सारी बातें साफ हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में मतदाताओं को पटाने-रिझाने के लिए गुपचुप तरीके से उन्हें पैसे देने की न तो जरूरत रहेगी और न ही उम्मीदवारों के पास इस तरह का कोई मौका ही होगा। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ चुनाव का पूरा खर्च ही निकाला जा सकेगा, बल्कि बहुत-सी फिजूलखर्ची को कम भी किया जा सकेगा। हमारे देश में यदि कैशलेस चुनाव होते हैं तो पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कैशलेस चुनाव भी कराए जा सकते हैं। वैसे तो भारत जैसे विशाल देश में चुनावी खर्च पर अंकुश लगा पाना एक चुनौती है, मगर फिर भी सरकार ने विमुद्रीकरण का जो कदम उठाया है, वैसा ही कठोर कदम उठाकर चुनाव के नाम पर किए जाने वाले अनाप-सनाप खर्च पर काबू पाया जा सकता है। इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा लाख कठोरता बरते जाने के बावजूद पिछले चुनावों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों सहित उम्मीदवारों ने पानी की तरह पैसा बहाया था। चुनाव में यदि कैशलेस नियम लागू कर दिया जाता है तो नि:संदेह ऐसे खर्च पर काबू पाया जा सकेगा। ।

कब तक चलेगा पाकिस्तान का झूठ

आतंकवादियों की पनाहगाह कहे जाने वाले पाकिस्तान का झूठ हाल ही में दुनिया के सामने आ चुका है। वैसे भी झूठ बोलना पाकिस्तान की पुरानी आदतों में शामिल है। चीन की शह पर भारत को आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहे पाकिस्तान ने अतीत से आज तक भारत को नीचा दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक झूठ बोला है। खुद को परमाणु संपन्न देश बताने से लेकर आतंकवाद को फैलाने तक पाकिस्तान ने झूठ बोलने का एक भी मौका नहीं गंवाया है। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि झूठ पर झूठ बोलकर किसी भी प्रकार से भारत को कमजोर किया जाए, दुनिया के सामने उसे कमजोर अथवा नीचा दिखाया जाए, मगर हर बार पाकिस्तान की ही करतूत विश्व के सामने उजागर हो जाती है।

हाल ही में समाचारों में आया था कि अमरीका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 'एक शानदार व्यक्तित्व का अधिकारी' बताया है। समाचार में यहां तक कहा गया कि ट्रम्प ने शरीफ को फोन कर उनसे शीघ्र मिलने की भी इच्छा जताई है। समाचार की इस कड़ी में यह भी विस्तारपूर्वक छापा गया कि ट्रम्प ने पाकिस्तान के नागरिकों को सबसे बुद्धिमान बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कहने वाले ट्रम्प के चुनाव जीतने के बाद उनके नाम से पाकिस्तान के पक्ष में समाचार में आए इस बयान के बाद पूरे विश्व पटल पर हलचल बढ़ गई। भारत-अमरीका के बीच परवान चढ़ते रिश्तों पर पैनी नजर रखने वाले देश तो एकदम से चौंक गए कि ट्रम्प अमरीकी विदेश नीति को कौन-सी दिशा देना चाहते हैं। आतंकवाद को खत्म करने की कोशिशों

में लगे देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए ट्रम्प के इस बयान पर आश्चर्य प्रकट किया। विश्व राजनीतिक पटल पर यह सवाल भी बड़ी गंभीरता से उठाया गया कि अमरीका ने अपने भारतीय संबंधों को कैसे और क्यों दरकिनार कर दिया। मगर एक दिन बाद ही यह साफ हो गया कि यह यह पूरा प्रकरण पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया सफेद झूठ का पुलिंदा मात्र था। पाकिस्तान द्वारा किए गए इस झूठे प्रचार पर स्वयं ट्रम्प ने भी गहरी नाराजगी प्रकट की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्वयं आगे आकर पाकिस्तान के उक्त बयान को झूठा बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की प्रशंसा करना और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करने संबंधी समाचार पत्रों-चैनलों में प्रसारित-प्रचारित समाचार सच नहीं है। ट्रम्प ने यह भी स्पष्ट किया कि शरीफ ने जीत की बधाई देने के लिए स्वयं उनको फोन किया था। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह साफ किया कि जैसा की समाचार में कहा जा रहा है, शरीफ के साथ उनकी उस तरह की बातें नहीं हुईं।

पाकिस्तानी नेता और सत्ता पर काबिज अधिकारियों द्वारा झूठ पर झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष तथा राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने हाल ही में यह बयान देकर मीडिया में सनसनी फैला दी थी कि आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए पाकिस्तान घी डालने का काम कर रहा है। यह वही मुशर्रफ हैं, जिन्होंने आतंकियों को भड़काकर भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध छेड़ने का दु:साहस किया था। मुशर्रफ जितने दिन पाक की सत्ता पर काबिज रहे, तरह-तरह की भारत विरोधी हरकतें करते रहे और अब भी अपनी नापाक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। कारगिल के युद्ध के समय पाकिस्तान का वह झूठ पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना, जब पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए अपने ही सैनिकों के शव को सम्मान सहित लेने से तो दूर पहचानने तक से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद यह कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान के पुलिंदे में अभी भी कितने झूठ बाकी हैं। 1

राजमार्ग के किनारे शराब बिक्री पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से यह बात भी स्पष्ट होती है कि जो काम केंद्र तथा राज्य सरकारों को करना चाहिए, वह काम अब उच्चतम न्यायालय को करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के फलस्वरूप न सिर्फ सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि राजमार्ग और इसके आसपास होने वाली आपराधिक घटनाएं भी कम होंगी। देश के कुछ गिने-चुने शराबबंदी वाले राज्यों को छोड़ अन्य सभी ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जहां-तहां शराब की दुकानें-बार खोलने का लाइसेंस दे रखा है। इससे सरकार के राजस्व में तो बढ़ोतरी हुई है, मगर युवा पीढ़ी का बंटाधार हुआ जा रहा है। शहरी इलाकों की बात तो छोड़ ही दें, आजकल शाम ढलते ही गांवों में भी शराबियों की जमात सड़कों पर पसरने लगती है। आज जबकि किशोर उम्र के लड़के शराब गटकने लगे हैं तो वह युवा पीढ़ी कितनी तेजी से पतन के गर्त में गिर रही है, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकार यदि लाइसेंस जारी करती है तो इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजस्व संग्रह राज्य के विकास और प्रशासनिक कामकाज को संचालित करने के लिए जरूरत की धनराशि जुटाने का एक प्रमुख जरिया है। राजस्व की सही तरीके से उगाही नहीं होगी तो इसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ेगा, मगर ऐसे लाइसेंस जारी करते समय यह कड़े निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए कि स्कूल-कॉलेज अथवा अन्य किसी शिक्षण संस्थान के आसपास शराब की दुकनें हरगिज न खोली जाएं। सिर्फ ऐसे निर्देश जारी कर देने भर से नहीं होगा, उसका कड़ाई से पालन भी

करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही इससे पहले न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए शिक्षण संस्थानों के आस-पास शराब की दुकानें खोलने पर निषेधाज्ञा जारी की थी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री व प्रयोग पर भी पाबंदी लगी हुई है।

सरकार का एक अपना विभाग है, आबकारी विभाग। यह विभाग राजस्व संग्रह करता है, मगर इस विभाग को राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी करने के साथ ही अपने सामाजिक सरोकारों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। लचर शराब नीति और राज्य सरकार व उसके विभाग की उदासीनता के कारण ही बार-बार ऐसे मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शराब बिक्री पर रोक लगाने संबंधी फैसले से एक बात बार फिर साबित हो गई कि शराब की दुकान खोलने के लिए स्थान चयन के मामले में राज्य सरकारें गंभीर नहीं हैं, जबकि समाज में शांतिमय और सुरक्षित माहौल स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। भारतीय समाज में सामाजिक अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए शराबखोरी अथवा अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को एक प्रमुख कारण बताया जाता है। शराब के नशे में धुत व्यक्ति बड़ी आसानी से गंभीर से गंभीर अपराध कर बैठता है और जब उसका नशा उतरता है तब जाकर उसे अपनी गलती का अहसास होता है। राजमार्ग पर बेहद तेज गति से दौड़ती गाड़ियों को भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा सकता है। शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने के फलस्वरूप सड़क हादसों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। रात को अथवा तड़के सड़क हादसों की संख्या तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बावजूद किसी भी राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। वैसे भी साल में सिर्फ एक बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मना लेने भर से जनता को इस बारे में जागरूक नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारें जब राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अथवा उसके आस-पास शराब दुकानों को खुलने से नहीं रोक पाईं, तब जाकर उच्चतम न्यायालय को इसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ा। अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है। राज्य सरकारों को यदि अपना राजस्व बढ़ना है तो वे अन्य उपाय खोजें, शराब दुकान खोलने के लाइसेंस को राजस्व उगाही का जरिया हरगिज न बनाएं। l

पुराने को अलविदा कह नए साल का करें स्वागत

दो दिन बाद भोर के कोहरे को चीरते हुए सूर्य की पहली किरण जब धरती को स्पर्श करेगी तो उसके साथ नए साल का उल्लास और उम्मीदों का सागर भी होगा। पुरातन को विदा करना और नवीन का स्वागत करना प्रकृति का नियम है। पूरी दुनिया के लोग नए साल अर्थात वर्ष 2017 के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। इस दौड़ में असम के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले एक सप्ताह से पार्टी-वनभोज का दौर जारी है। क्रिसमस डे की रात चढ़ा मस्ती का खुमार अब तक उतरा नहीं है और अगले दो-चार दिनों तक खुमार उतरने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। हर रोज वनभोज के लिए जाने वालों की टोलियां दिखाई पड़ ही जाती हैं। कामरूप महानगर जिले में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चला रहे जिला प्रशासन ने वनभोज पर जाने वालों से आग्रह किया है कि वह लोग वनभोज के दौरान आनंद मनाने के साथ-साथ वहां की साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। यह एक तरह से नागरिकों को उनकी ही जिम्मेदारी का स्मरण कराना है। पर्व-त्योहार के मौके पर आनंद-उल्लास मनाना अच्छी बात है, मगर उसके साथ-साथ यदि लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत हो जाएं तो यह और भी अच्छी बात है।

दो दिन बाद ही नया साल आने वाला है। हम सभी पुराने को भूल नए साल का जश्न मनाने में लग जाएंगे। मगर यह वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखने, अपने अंदर झांकने का भी है। पिछले एक साल में हमने क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं कर पाए। हमारे कौन-से संकल्प पूरे हुए, कौन-से अधूरे रह गए। हमने क्या खोया और साल भर में क्या पाया। इन सबका आंकलन आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कुछ हासिल न कर पाना जितना दुख देता है, उसे हासिल नहीं कर पाने का अहसास हमें उससे अधिक दुख देता है। यही वह

वक्त है, जब हमें एक बार तनिक ठहरकर सोचना चाहिए कि हमारी दौड़ का अंत कहां है। हमारा लक्ष्य क्या है। पिछले साल का लेखा-जोखा जहां हमें अपनी सफलता पर संतोष देगा, वहीं हमारी असफलताओं की भी समीक्षा करेगा कि सफलता हासिल करने में कमी कहां रह गई। यही लेखा-जोखा हमें अपनी अगले साल की योजना बनाने को प्रेरित करेगा।

क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम नए साल की योजनाओं को अब अंतिम रूप देने में लग जाएं। याद रखिए, हमारे पास अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए सिर्फ 365 दिन का ही वक्त होता है। लिहाजा जरूरी है कि हम कोई अनूठा काम करने के बजाय हर काम को अनूठे तरीके से करने की कोशिश करें। साल भर में पूरी की जाने वाली योजनाओं की फेहरिस्त हमें अहसास कराती है कि हमारे पास वक्त कितना कम अथवा अधिक है। इसके लिए जरूरी है कि हर काम का एक रोडमैप हो और किसी भी हालत में वक्त जाया न किया जाए। कारण वक्त उस रेत भरी मुट्ठी की तरह होता है, जो हथेली से फिसल जाने के बाद वापस लौटकर नहीं आता। हमें वक्त की कीमत और वक्त के मिजाज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी कवि ने कहा भी है, 'आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज।' जिसने वक्त का सम्मान किया है, वक्त ने उसे हमेशा ही मालामाल किया है। इसलिए यह एक समझदारी भरा फैसला होगा कि हम नए साल में एक समय आधारित योजनाक्रम बनाएं और पूरी ईमानदारी व लगन के साथ उस पर काम करने में लग जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला नया साल हम सभी के लिए उम्मीदों से लबालब और सफलताओं से भरा होगा, मगर ऐसा तभी होगा जब हम स्वयं इसके लिए तैयार होंगे। नव वर्ष के आगमन से दो दिन पहले हमें खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेना है। अपना अंतिम आंकलन कर लेना है कि सफलता को अपने बाहुपाश में भरने के लिए हम कितना तैयार हैं, हमारी तैयारियां कितनी मुक्कमल हैं। यदि हमारी तैयारियों में कोई कमी रह भी गई हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कम-से-कम 50 घंटे का वक्त अभी भी बचा है और पचास घंटे कम नहीं होते। आइए हम वर्ष 2016 को भावभीनी विदाई दें और नए साल का स्वागत करें, इस कामना के साथ कि नया साल पूरे विश्व के लिए मंगलमय होगा। l

पाक में नोटबंदी, पांच हजार के नोट पर पाबंदी

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी की घोषणा किए जाने के बाद से न सिर्फ हमारे देश में, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल आदि में भी हाहाकार मचा हुआ है। मालूम हो कि भारत-नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे नेपाली शहरों में बड़े पैमाने पर भारतीय मुद्रा का लेन-देन होता है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद नेपाली व्यपारियों के पास बड़ी मात्रा में जमा 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में भी भारतीय नोटबंदी को लेकर भारी कोहराम मचा हुआ है। मीडिया में आए समाचारों को यदि सच मान लिया जाए तो पाकिस्तान में छापे गए अरबों-खरबों के मूल्य के फर्जी 500-1000 नोट उक्त घोषणा के बाद रद्दी के टुकड़ों में बदल चुके हैं। इसके अलावा विदेशी मुद्राओं की अदला-बदली का कारोबार करने वाले पाकिस्तानी व्यापारियों के पास भी बड़ी मात्रा में 500 और 1000 के नोट जमा रह जाने की बात कही जा रही है।

इन सब से अलग भारतीय नोटबंदी का पाकिस्तान की संसद में भी असर देखा गया। जहां एक ओर कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी सहित अन्य सारी विपक्षी पार्टियां नोटबंदी का विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी संसद ने वहां प्रचलित 5000 रुपए के नोट को निषिद्ध करने के सरकारी फैसले को पारित कर दिया है। इस फैसले के अमल में आने के बाद पाकिस्तान में कम-से-कम वहां की कुल मुद्रा की 30 प्रतिशत मुद्रा, जो कि 5000 के नोट की शक्ल में हैं, चलन से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सांसद उस्मान सईफुल्लाह खान ने जब वहां की संसद में 5000 रुपए के नोटबंदी का प्रस्ताव रखा तो अधिकांश सांसदों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी अवाम को बैंक सेवा से जोड़ने के लिए चरणबद्ध तरीके से अगले तीन से पांच साल के अंदर इन 5000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर

दिया जाएगा। इसी कड़ी में वेनेजुएला में 11 नवंबर को अधिक मूल्य वाले नोट को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की गई थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक आदेश जारी कर वहां की 100 बोलिवर बिल (नोट) पर पाबंदी लगा दी थी। उनकी इस घोषणा के बाद वेनेजुएला में नकदी का संकट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से नोटबंदी के इस फैसले को वापस लेना पड़ा। वेनेजुएला सरकार की ओर से कहा गया है कि नोटबंदी के फैसले को जनवरी तक टाल दिया गया है और बाद में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

इधर देशवासियों ने खुले दिल से नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया है। 8 नवंबर के बाद से ही बैंक और एटीएम के बाहर लगी कतारों में पूरा देश खड़ा है। लोगों को तरह-तरह की मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। लाइन में लगी हालत में कई लोगों के मारे जाने की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं। इसके बावजूद देश की जनता मोदी के फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। पिछले दिनों देश भर में बरामद हजारों करोड़ रुपए के काले धन और भ्रष्ट व्यापारी-अधिकारी, बैंक कर्मियों की गिरफ्तारी की खबरों ने गरीबों को राहत पहुंचाने का काम किया है। देश की गरीब जनता यह सोचकर खुश है कि बेईमानी करने वाले सलाखों के पीछे और बेईमानी से जमा किया गया काला धन सरकारी खजानों में जा रहा है। आम नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे फोन कर काला धन और भ्रष्टाचारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की घटनाएं यह साबित करती हैं कि जनता के मन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना रोष भरा पड़ा है। देश को इस स्थिति से उबारने के लिए जनता सरकार को अपना हर संभव मदद देने में लगी है। लाख तकलीफें उठाने के बाद भी देश के किसी भी कोने में नोटबंदी के खिलाफ जनांदोलन की एक छोटी-सी लहर तक देखने को नहीं मिली।

वहीं देश की सभी विपक्षी पार्टियां गला फाड़-फाड़कर कह रही हैं कि नोटबंदी से गरीब बर्बाद हो गए। किसानों की फसल तबाह हो गई। हजारों बेटियां बिना शादी रह गईं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा साहसिक फैसला लेकर पूरे विपक्ष को हासिए पर धकेल दिया है। ऐसे में विपक्ष के पास सिवाय अपना विपक्ष धर्म निभाने अर्थात सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा दूरा कोई चारा बचा नहीं रह गया है। ।

देश-विदेश तक पहुंचें असमिया परंपरागत पकवान

नए साल के आगमन पर राज्यवासी भी अपने-अपने अंदाज में खुशियां मनाने में जुटे हुए हैं। साल के पहले दिन से जारी वनभोज का सिलसिला जोरों पर है। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर वनभोज प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। माघ बिहू अर्थात भोगाली बिहू ने राज्यवासियों की इस खुशी को और भी बढ़ा दिया है। आज से लोगों में परंपरागत पकवान खाने-खिलाने का दौर शुरू हो जाएगा। बर्गर-पिज्जा, मैगी-चाउमिन खाने वाले युवाओं में भी अगले कई दिनों तक परंपरागत पकवानों के प्रति बड़ा आकर्षण देखने को मिलेगा। सड़कों के किनारे लगी परंपरागत पकवानों की दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़ और पिछले एक पखवाड़े से जगह-जगह आयोजित हो रहे भोगाली मेलों की सफलता को देखकर कहा जा सकता है कि असम का युवा आज भी अपनी जड़ों से कटा नहीं है। असम की कला-संस्कृति, परंपराएं आदि अब भी उसके दिल के किसी कोने में जिंदा हैं। बस जरूरत है, इस भावना को जागृत रखने का। इसके लिए अभिभावक वर्ग को आगे आना होगा।

युवा वर्ग में हमारे परंपरागत पकवानों के प्रति कितना आकर्षण है, इसका अंदाजा परंपरागत पकवान बनाने वाले प्रतिष्ठान 'भोगाली जलपान' की सफलता से लगाया जा सकता है। पिछले कई सालों में इस प्रतिष्ठान ने सफलता के कई पायदानों को पार किया है। सिर्फ भोगाली जलपान ही क्यों, अन्य कई मिष्ठान्न आदि की दुकानों पर भी बड़ी मात्रा में असमिया पकवान बिकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या इन पकवानों के बाजार को लेकर है। इसके लिए हम न तो गंभीर हैं और न ही प्रयासरत। आज जब गुजरात का परंपरागत पकवान ढोकला असम के बाजार में बिक रहा है तो हमारे असम के पीठा-लारू गुजरात-दिल्ली सहित अन्य राज्यों में क्यों नहीं बिक सकते, जबकि देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में असम सहित पूर्वोत्तर के लोग रहते हैं। दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के बाजार में यदि असम के परंपरागत पकवान उपलब्ध हों

तो बड़ी संख्या में इसके खरीददार भी मिल जाएंगे। इसके लिए हमें बस गंभीरता के साथ प्रयास करने होंगे। विज्ञापन अर्थात मार्केटिंग आज की पहली जरूरत है। बाजार में सिक्का जमाना है तो मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। मार्केटिंग के दम पर यदि 12 रुपए की मैगी बिक सकती है तो हमारे पीठा-लारू क्यों नहीं। मार्केटिंग के साथ-साथ हमें इनकी पैकिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपने देखा होगा असमिया पकवानों को आकर्षक दिखाने के लिए पैकिंग के नाम पर एक पाई भी खर्च नहीं की जाती। बाजार में बिकने वाले पीठा-लारू एक साधारण पारदर्शी पेपर में पैक कर ग्राहकों को सौंप दिया जाता है। हमारे देश में मार्केटिंग और पैकिंग के दम पर तो गुटखा जैसा जानलेवा जहर भी आसानी से बिक जाता है तो फिर हम असमिया परंपरागत पकवानों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में पीछे क्यों रहें। स्वाद को कभी भी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। असम के लोगों को पंजाब की परंपरागत रसोई मक्के की रोटी-सरसों का साग से लेकर दक्षिण भारत के इडली-डोसा, राजस्थान के गट्टे-सांगरी की सब्जी तक का स्वाद चखने का मौका मिलता है तो देश के अन्य राज्यों के लोगों को असमिया पकवानों के जायके से वंचित क्यों होना पड़े। इसके लिए हमें ही आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी। असमिया पकवानों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का बीड़ा हम सभी को मिलकर उठाना होगा। यह काम करने के लिए बाहरी राज्य से कोई आएगा, हमें इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए। वैसे भी आज के संचार माध्यम के युग में किसी भी वस्तु को लोगों तक पहुंचाना अथवा लोकप्रिय बनाना पहले जैसा कठिन काम नहीं रह गया है। इसके लिए जरूरी है बस एक ईमानदार कोशिश की। यह काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। फिर क्यों न अब की बार नए साल, भोगाली बिहू पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने असमिया पकवानों को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। यदि हम इस अभियान को सफल बना पाएं तो यह असमिया एवं प्रवासी असमिया दोनों के लिए एक शानदार उपलब्धि होगी। इससे असम में कुटीर उद्योग की संभावनाएं बढ़ेंगी और बेरोजगारी कम होगी, इन बातों को तो बिना इसका जिक्र किए ही समझा जा सकता है। तो फिर क्यों न भोगाली बिहू के मौके पर विश्ववासियों को असमिया भोग का स्वाद चखाने के अभियान को आज से ही शुरू किया जाए। ।

अच्छे पड़ोसी चाहता है भारत

अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती भरा रिश्ता रखने में यकीन रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को दूसरे रायसीना संवाद के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में एक बार फिर कहा कि उनका सपना एक अच्छे और एकीकृत पड़ोस का है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अकेले शांति बहाल नहीं कर सकते और अगर पाकिस्तान को भारत के साथ शांति के मुद्दे पर बातचीत करनी है तो पहले उसे आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है, मगर अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालकर नहीं। वर्ष 2014 की मई में सत्ता संभालते ही श्री मोदी ने अपने इरादे सभी के सामने जता दिए थे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों के प्रमुखों को निमंत्रित कर उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते चाहता है। साथ ही साथ उसने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक से और चीन की गीदड़ भभकियों का माकूल जवाब देकर यह भी साफ कर दिया कि वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत के इस रवैए का असर विश्व राजनीतिक पटल पर भी देखा गया। भारत को परेशान करने की नीयत से चीन ने पाकिस्तान की पीठ थपथापानी शुरू कर दी। चाहे वह एनएसजी में भारत के शामिल होने के मुद्दे का खुलेआम विरोध करना हो अथवा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में रोड़े अटकाना हो। चीन ने ऐसा कोई मौका नहीं गंवाया, जिससे भारत को नुकसान और पाकिस्तान को फायदा होता हो।

वियतनाम के साथ भारत के मजबूत होते सैन्य संबंधों से बौखलाए चीन की सरकारी मीडिया ने इसी महीने भारत को धमकाते हुए कहा है कि बीजिंग

का मुकाबला करने के लिए यदि वियतनाम के साथ भारत अपने सैन्य संबंध मजबूत करने का कोई कदम उठाता है तो इससे क्षेत्र में 'गड़बड़ी' पैदा होगी तथा चीन 'हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा।' नई दिल्ली हनोई को सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलें बेचने की योजना बना रहा है, खबर आने के बाद चीन की सरकारी मीडिया ने धमकी दी है। वियतनाम को सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की खबरों पर चीन की चिंताओं को रेखांकित करते हुए ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है, यदि भारत सरकार रणनीतिक समझौते या बीजिंग के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से वियतनाम के साथ असल में अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करती है तो इससे क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा होगी और चीन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। इसमें कहा गया कि मिसाइलों की आपूर्ति सामान्य हथियार बिक्री के रूप में होनी है। ग्लोबल टाइम्स ने यह बात इन खबरों का हवाला देते हुए कही कि नई दिल्ली का यह कदम चीन द्वारा भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने से रोकने तथा जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयासों में चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के जवाब में है। कुल मिलाकर ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख से यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि चीन के प्रति भारत का वह पहले जैसा नरमी वाला रुख नहीं रह गया है। चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने में भारत खुद को सक्षम पाता है।

चीनी सैनिकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की जाने वाली घुसपैठ और चीन सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर अपना दावा ठोंकने की घटनाओं पर भी भारत ने कड़ा रुख अपनाकर चीन के समक्ष अपनी मंशा साफ कर दी है। पिछले साल 9 सितंबर को भी चीनी सैनिक न सिर्फ भारत की सीमा में घुस आए थे, बल्कि उन्होंने सीमा के 45 किलोमीटर अंदर प्लम इलाके में अपने कैंप भी बना लिए थे। उक्त घटना के चार दिन बाद 13 सितंबर को भारतीय सेना और आईटीबीपी ने इलाके की संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ा। मालूम हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चांगलांग जिले से 94 किलोमीटर दूर है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने सीमा पर स्थित हदीग्रह पास इलाके से घुसपैठ की और वहां से 45 किलोमीटर अंदर आकर प्लम इलाके में अस्थाई कैंप भी बना लिया। l

बिहार की तर्ज पर असम में भी हो शराबबंदी

बिहार के तीन करोड़ लोगों ने शराबखोरी के खिलाफ विगत 21 जनवरी को 11 हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया, लगभग उन्हीं दिनों असम के अखबारों में एक खबर सुर्खियां बनी कि जोरहाट में नशे का सेवन करने के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मौत हो गई। जहां बिहार में बनाई गई मानव श्रृंखला में 78 हजार शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने भाग लेकर नशे के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया, वहीं असम का विद्यार्थी वर्ग गुटखा जैसे नशे के चंगुल में है। कानूनन जूर्म होने के बावजूद राज्य के अधिकांश शिक्षण संस्थानों के आसपास गुटखा जैसा जानलेवा नशीला पदार्थ बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। कितनी विरोधाभासी तस्वीर है। बिहार सरकार की शराबबंदी की घोषणा के समर्थन में तीन करोड़ लोगों का सड़कों पर निकल आना कम बड़ी बात नहीं है। 11 हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला यह संदेश देती है कि नशाखोरी समाज का सबसे भयंकर नासूर बना हुआ है। विश्व के किसी भी हिस्से में शराबखोरी के खिलाफ तीन करोड़ लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बनाने का उदहारण नहीं है।

किसी जमाने में बिहार शराबखोरी के लिए कुख्यात था। बिहार में विषैली कच्ची शराब का सेवन कर लोगों के मारे जाने की घटना आम हुआ करती थी। शराबखोरी ने बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया था। शराब की वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए और राज्य में अपराध का ग्राफ भी काफी बढ़ गया था। घरेलू हिंसा की मुख्य वजह शराब को बताया गया। समाज का हर एक तबका शराब के चंगुल में फंसा था। गैर-कानूनी ढंग से कच्ची शराब बनाने वाले नशेड़ियों को शराब के नाम पर जहर बेचने लगे। पूरी व्यवस्था ही चरमरा कर रह गई थी। बिहार को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए समाजशास्त्रियों की राय थी कि बिहार में शराबबंदी कर बिगड़ी सामाजिक और कानून व्यवस्था को संभाला जा सकता है।

ऐसी स्थिति में बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी जैसा एक दु:साहसी फैसला लिया। लोगों ने सोचा नीतिश का यह फैसला टिक नहीं पाएगा। थक-हार कर कुछ दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। बिहार की तीन करोड़ जनता ने मानव श्रृंखला में भाग लेकर यह साबित कर दिया कि वह लोग नीतिश के फैसले के साथ है। मुझे याद है जब बिहार सरकार राज्य में शराबबंदी लागू करने की कवायद में जुटी थी, ठीक उसी दौरान राज्य सरकार कैबिनेट में देशी शराब बनाने संबंधी निर्णय ले रही थी। सिर्फ शुल्क अथवा राजस्व बढ़ाने के लिए समाज को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे फैसलों को समझदारी भरा तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। जहां तक असम की बात है तो यहां भी शराबबंदी अथवा नशाबंदी जैसे कानून की सख्त जरूरत है। युवा वर्ग नशे के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका है। शाम के बाद सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों में रास्तों के किनारे-कलवर्ट की रेलिंग पर शराब पीते युवाओं की टोलियों को आसानी से देखा जा सकता है। दुर्गा पूजा हो अथवा बिहू त्योहार के दिनों शराब की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती है। साथ में बढ़ जाती है सड़क दुर्घटनाएं भी। ऐसी दुर्घटनाओं में मारे जाने अथवा घायल होने वाले भी अधिकांश युवा ही होते हैं। पुलिस और चिकित्सक शराबखोरी को सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण बताते

हैं। ऐसे में हम शराबखोरी को शह देकर कब तक अपने जवान बच्चों को मरता-तड़पता हुआ देखते रहेंगे। अच्छे काम का अनुकरण होना ही चाहिए। बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू कर एक अच्छा और प्रशंसनीय कदम उठाया है। असम सरकार को चाहिए कि अपने पड़ोसी राज्य बिहार का अनुकरण कर वह भी असम में शराबबंदी लागू करने की घोषणा करे। राज्य सरकार का एक साहसी फैसला युवा असम को नशे के गर्त में गिरने से बचा सकता है। असम सरकार यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि युवाओं में परिवर्तन लाए बिना असम में परिर्वतन नहीं लाया जा सकता। आज का युवा ही कल का असम है। युवा यदि नशे में लड़खड़ाता रहेगा तो असम तनकर खड़ा कैसे रह सकता है। खुद को नरेंद्र मोदी का सिपहसालार कहने वाले सर्वानंद सोनोवाल केसामने असम में शराबबंदी लागू करना एक बड़ी चुनौती है। सरकार यदि ऐसा फैसला लेती है तो इसका विरोध भी होगा, समर्थन भी मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वानंद सोनोवाल इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं। l

भ्राम्यमान थिएटर के अद्वितीय व्यक्तित्व थे रतन लहकर

शून्य से शुरू होने वाला असम का भ्राम्यमान थिएटर अब एक उद्योग का स्वरूप ले चुका है। राज्य के हजारों युवाओं को भ्राम्यमान थिएटर रोजगार देता है। थिएटर जगत को शून्य से शिखर तक लाने में कई लोगों के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हमेशा से ही पर्दे के पीछे रहकर काम करते ऐसे व्यक्तियों में स्वर्गीय रतन लहकर का नाम पूरी श्रद्धा व सम्मान के साथ लिया जाएगा। भ्राम्यमान थिएटर का हॉलीवुड कहे जाने वाले पाठशाला से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले निर्देशक, अभिनेता, संगठक, समाजसेवी रतन दा ने अपनी पूरी उम्र थिएटर के विकास कार्य में ही खपा दी। वे हमेशा ही थिएटर के मंच को लेकर प्रयोग किया करते थे। उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर थिएटर के मंच पर रोशनी और छांव के ऐसे-ऐसे मंजर प्रस्तुत किए, जो आमतौर पर विश्व के किसी भी थिएटर के मंच पर देखने को नहीं मिलते। उनके शब्दकोश में 'असंभव' शब्द था ही नहीं। थिएटर मंच पर किए गए उनके तकनीकी प्रयोग ने उन्हें पूरे विश्व में ख्याति दिलाई। थिएटर का मंच ही उनका पहला और आखिरी प्रेम था, लिहाजा उन्होंने ने मंच को सुसज्जित करने के लिए नई-नई तकनीक इजाद की और दर्शकों से जी भरकर तालियां और प्यार बटोरा।

रतन लहकर को सफलता मानो वरदान में मिली थी। दर्शकों को रोमांचित करने में उनको बड़ा ही सुख मिलता था। उनकी तकनीक में भी रोमांच के दर्शन होते हैं। पूरी दुनिया में जब ऑस्कर विजेता फिल्म 'टाइटैनिक' की धूम थी, रतन दा उस वक्त अपने कोहिनूर थिएटर के मंच पर ही टाइटैनिक को उतारने की कल्पना में डूबे हुए थे। उनकी जब यह कल्पना साकार हुई तो असम के थिएटर जगत में मानो तहलका-सा मच गया। मंच पर उड़कर जहाज की डेक पर आता हेलिकाप्टर, बर्फ के पहाड़ से टकराता और दो टुकड़ों में बिखरते

टाइटैनिक को देखना थिएटर के दर्शकों के लिए कम रोमांचक नहीं था। बाद में उनका थिएटर राज्य के जिस शहर-गांव में गया, दर्शकों ने बार-बार सिर्फ टाइटैनिक को ही देखा। हम कह सकते हैं कि उनकी इस सोच की वजह से ही असम का भ्राम्यमान थिएटर आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है। टाइटैनिक की लोकप्रियता को देख नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विशेष आमंत्रण पर उन्होंने जब दिल्ली में टाइटैनिक का मंचन किया तो दर्शकों ने दांतों तले अंगुली दबा ली थी।

उनकी सोच का ही नतीजा है कि आज राज्य के गांव-नगरों में थिएटर देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रतन दा भले ही पर्दे के पीछे रहते थे, मगर मंच के सामने बैठे दर्शक-श्रोताओं की भावनाओं को खूब समझते थे। आज रतन दा की वजह से ही हम सभी एक साथ बैठकर थिएटर का आनंद उठा पाते हैं। थिएटर ने कभी भी दर्शकों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया था। थिएटर के प्रेक्षागृह में घंटों बैठा रहने वाला उनका दर्शक बोर न हो जाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा ही खास ध्यान रखा।

रतन दा दिखने में भले ही सीधे-साधे थे, मगर उनकी नजर बड़ी तेज थी। छोटी-बड़ी घटनाओं को किस तरह से दर्शकों के सामने रखा जाए, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी। बहुत कम लोगों को पता है कि रंगमंच दिखने में जितना आकर्षक लगता है, उसके पीछे उतनी ही समस्याएं रहती हैं और ये कभी-कभी तो गंभीर रूप भी धारण कर लेती हैं। भ्राम्यमान थिएटर के नाटकों के रिहर्सल से लेकर उसके मंचन होने तक न जाने कितनी ही समस्याएं पैदा होती हैं और अंततः उनका हल भी निकाल लिया जाता है। उनके पास तो मानो ऐसी हर एक समस्या का समाधान था। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के दौरान वे बहुत लोगों के लिए अप्रिय पात्र भी बने, लेकिन उन्होंने सिवाय अपने काम के अन्य किसी भी वस्तु को कभी भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया। भ्राम्यमान थिएटर जगत में उनके जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं। कोई भी काम करने की ठान लेने के बाद वे उस काम को करके ही दम लेते थे। ऐसे एक व्यक्ति का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने से भ्राम्यमान थिएटर को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। ।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान से बढ़ता है भाईचारा

संस्कृति की कोई परिधि, कोई दायरा नहीं होता है। इसलिए दो अलग-अलग संस्कृति-परंपराओं के लोगों के बीच जितना अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है, भाईचारा भी उतना ही अधिक बढ़ता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य समाज की संस्कृति-संस्कार के बारे में जानने-समझने की कोशिश करता है तो उसके सामने नए-नए रास्ते खुलने लगते हैं। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्र-प्रांत और देश के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आजकल बहुत महत्व दिया जाने लगा है। विश्व के हर एक क्षेत्र की अपनी विशेषता, अपनी सभ्यता-संस्कृति है। लोगों में भले ही सांस्कृतिक भिन्नता रहे, फिर भी एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान करने में कोई भी हिचक महसूस नहीं करता।

राज्य के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच सांस्कृतिक सोच का आदान-प्रदान करने की दिशा में सांस्कृतिक महासभा, असम एक विशेष भूमिका का निर्वहन करने में लगी है। यह संस्था अपने स्थापना काल से ही लोगों को विविधता से परिपूर्ण असमिया संस्कृति के बारे में जानकारी देती रही है। यह बात कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि असम विभिन्न कला-संस्कृतियों से भरा एक बगीचा सरीखा है। इस बगीचे का जितना विस्तार होगा, इसकी खुशबू चारों ओर उतनी ही फैलेगी। हमारे असम में विभिन्न जाति, जनजाति, जनगोष्ठी के लोग निवास करते हैं। हर जाति-जनजाति की अपनी ही कला-संस्कृति और परंपराएं हैं। ये विभिन्न परंपराएं आपस में मिलकर ही एक समृद्ध संस्कृति वाले असम का सृजन करती है। हम यदि इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हमारे राज्य की बोड़ो, मिसिंग, देउरी, सोनोवाल, कछारी, कार्बी, मटक, ताई आदि संस्कृति का कोई सानी नहीं है। इन समृद्ध संस्कृतियों पर जितना भी गर्व किया जाए कम है। हमारे राज्य

में निवास करने वाली विभिन्न जाति, जनजाति, जनगोष्ठी के बीच खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, गृह निर्माण, सामाजिक रीति-रिवाज आदि में भारी भिन्नता होने के बावजूद सभी अपने आपको असमिया-असमवासी बताते हैं। विभिन्न जाति-जनजाति में विविधता होने के बावजूद वे अपनी एकता और आपसी भाईचारे को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। सांस्कृतिक महासभा, असम इन्हीं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के काम में लगी है।

पिछले दिनों नलबाड़ी जिले के कमारकुची में महासभा के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। उक्त अधिवेशन के खुले सत्र में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। श्री पुरोहित ने भी अपने संबोधन में असम की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का जिक्र करते हुए इनके जरिए आपसी भाईचारे को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत को रेखांकित किया था। राज्यपाल ने कहा था कि संस्कृति और परंपराएं हमें एक-दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैसे भी नलबाड़ी जिले का कमारकुची क्षेत्र विभिन्न धर्म-जनजातियों की मिलन भूमि के रूप में जाना जाता है। यहां विभिन्न धर्म-संप्रदाय के लोग आपस में मिल-जुलकर निवास करते हैं। इन लोगों के आपसी भाईचारे को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां के लोग न सिर्फ शांति प्रिय है, बल्कि आपस में हिलमिल कर रहने वाले भी है। कमारकुची के सामाजिक सद्भावना और आपसी भाईचारे की कल्पना दूर किसी नगर-महानगर में बैठकर हरगिज नहीं की जा सकती।

यह बहुत जरूरी है कि युवा पीढ़ी को न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाए, बल्कि उन्हें हमारे प्राचीन व भाईचारे से परिपूर्ण संबंधों के बारे में भी बताया जाए। युवा पीढ़ी को यह बात समझाने की जरूरत है कि राज्य की बोड़ो, मिसिंग, देउरी, सोनोवाल, कछारी, कार्बी, मटक, ताई जनजाति की भले ही अलग-अलग भाषा-संस्कृति, संस्कार-परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम सभी असमिया हैं। इस भावना में न सिर्फ हमें असमिया संस्कृति की विशालता-उदारता के दर्शन होते हैं, बल्कि श्रीमंत शंकरदेव और अजान फकीर के आदर्शों की भी सुगंध मिलती है। l

दीपोर बिल के संरक्षण के लिए सरकार उठाए कदम

राज्य के पक्षी अभयारण्य का जब भी जिक्र होता है, हमारे सामने जेहन में महानगर के निकटवर्ती दीपोर बिल की तस्वीर उभर आती है। सर्दी के मौसम में दीपोर बिल में न सिर्फ हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षी, बल्कि प्रवासी पक्षी भी विचरण करने के लिए आते हैं। वैसे तो राज्य केअन्य कई पक्षी अभयारण्य में भी कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिलता है, मगर दीपोर बिल की चर्चा इसकेऔर आस-पास के इलाके में फैले कचरे-प्रदूषण की वजह से अधिक होती है। पक्षी अभयारण्य जैसे महत्वपूर्ण स्थान के पास डंपिंग ग्राउंड बनाना हमारी संवेदनहीनता को दर्शाता है। इसके अलावा दीपोर बिल के आस-पास हो रहा अतिक्रमण भी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा करने में लगा है। अतिक्रमण की वजह से जहां एक ओर दीपोर बिल का दायरा कम होने लगा है, वहीं दूसरी ओर इसके आस-पास कचारा फेंके जाने की वजह से इसके पानी के प्रदूषित होने का खतरा भी बढ़ गया है। पर्यटन की भारी संभावनाएं रहने के बावजूद दीपोर बिल का सिकुड़ना, सरकार की कथनी और करनी के फर्क को दिखाता है। इस प्रदूषण की वजह से ही पिछले महीने दुर्लभ प्रजाति के कई पक्षियों की मौतें हो चुकी हैं। हलांकि वन मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्म इस संभावना से इनकार करती हैं कि दीपोर बिल का पानी की पीकर दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की मौत हुई होगी। श्रीमती ब्रह्म ने इस सिलसिले में विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि पछले दिनों दीपोर बिल के पानी का सेवन करने की वजह से दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि दीपोर बिल का पानी जहरीला होता तो इसका सेवन करने वाले अन्य पक्षी अथवा मछलियां भी मरतीं, मगर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। उन्होंने संभावना जताई कि दीपोर बिल के पास ही बने डंपिंग ग्राउंड के आस-पास गिद्ध अथवा अन्य प्रजाति के पक्षी मंडराते रहते हैं, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डंपिंग ग्राउंड

की किसी जहरीली वस्तु के खाने से उनकी मौतें हुई हों।

हम भी यही मानकर चलते हैं कि दीपोर बिल के पानी का सेवन कर इन पक्षियों की मौत नहीं हुई, मगर इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि दीपोर बिल के आस-पास प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, जिस वजह से कभी भी पक्षियों अथवा अन्य वन्य जीवों के मारे जाने की घटना घट सकती है। सरकार को भी इस बात की गंभीरता को समझना होगा। अब समय आ गया है कि सरकार दीपोर बिल के संरक्षण और विकास के बारे में गंभीरता से सोचे। दीपोर बिल का संरक्षण कर न सिर्फ इसके अस्तित्व को बचाया जा सकेगा, बल्कि इसे बहुउद्देश्यीय मकसद के लिए विकासित भी किया जा सकता है। पर्यटन, मछली पालन, नौका विहार और रोमांचक खेल जैसी कई संभावनाएं दीपोर बिल में छिपी हुई हैं। प्रकृति प्रेमियों का मानना है कि सबसे पहले दीपोर बिल और इसके आसपास की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की जरूरत है, क्योंकि दीपोर बिल का दायरा जितना संकुचित होगा, यहां प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही बढ़ेगी। अब दीपोर बिल का किस तरह से विकास करना है, इसके लिए तो सरकार को विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ेगी।

पर्यटन केंद्र के रूप में भले भी दीपोर बिल का नाम भी शामिल हो, मगर पर्यटन विभाग भी इसको विकसित करने के मामले में खास कुछ नहीं कर पाया है। पर्यटन विभाग यदि दीपोर बिल के प्रति पर्यटकों को आकर्षित कर पाता है तो इसके विकास की संभावना भी चौगुना बढ़ जाएगी। हर साल दिसंबर-जनवरी महीने में बड़ी संख्या में लोग दीपोर बिल के किनारे वनभोज को आते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह वनभोजकारियों के लिए एक जगह तय कर दे। दीपोर बिल में कोई कचरा, प्लास्टिक, पानी की बोतल आदि न फेंक पाए, इसके लिए जरूरी है दीपोर बिल के चारों ओर तार की बाड़ लगा दी जाए, इससे दीपोर बिल सुरक्षित भी रहेगा और इसकी सुंदरता पर भी आंच नहीं आएगी। यहां वनभोज के लिए आने वालों से साफ-सफाई के नाम पर एक न्यूनतम शुल्क राशि भी वसूली जा सकती है, इस पैसों से इसके आसपास के इलाके की सफाई भी हो सकेगी और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। दीपोर बिल की सुरक्षा-संरक्षण के लिए आंदोलन-धरना-प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसके लिए चाहिए सरकार और जनता का संयुक्त प्रयास, सहयोग और सद्इच्छा। l

अब सुरंग के रास्ते आतंकवादी भेजना चाहता है पाकिस्तान

भारत के हाथों बार-बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान में सुधार के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, मगर वह बजाय अपने घर में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने के भारत में आतंक की आग भड़काना चाहता है। भारत के खिलाफ नई-नई साजिशें रचना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। जब भी मौका मिलता है, पाकिस्तान अपनी औकात दिखा ही जाता है। यह अलग बात है कि भारत के सामने पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होती है। अब पाकिस्तान भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग खोदकर उसके जरिए भारत में अपने आतंकी भेजने की कोशिश में लगा है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू-काश्मीर के सांभा जिले के रामगढ़ सेक्टर को जोड़ने वाली एक 20 फुट लंबी सुरंग का पता लगाया। यह पहला मौका नहीं है, जब पाकिस्तान ने सुरंग के द्वारा भारत में अपने आतंकी भेजने की कोशिश की हो। इससे पहले 2012 में भी पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खोदी गई चार सौ मीटर और वर्ष 2009 में कश्मीर के अखनूर सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर पाक द्वारा खोदी गई एक सुरंग मिली थी।

पाकिस्तान जल मार्ग और स्थल मार्ग से अपने आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की लगातार कोशिशें करता रहा है। मगर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए उरी हमले के बाद भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का जीना हराम कर रखा है। उरी हमले के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हाथों भारत में घुसपैठ

करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के बड़ी संख्या में मारे जाने के बाद पाकिस्तान के होश गुम हो रखे हैं। 6 जनवरी को लश्कर-ए-तैयबा के कट्टर आतंकी मुजफ्फर नाइको के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद पाकिस्तान के हाथ-पांव वैसे ही फूले हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत को अशांत करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऊपर से जम्मू-कश्मीर के हालात ने पाकिस्तान को और परेशान कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी और कश्मीर के अलगाववादियों के खिलाफ बरती गई सख्ती के बाद पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में दंगा भड़काने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। नोटबंदी के कारण पुराने 500 और 1000 के नोट चलन के बाहर होने के बाद से पाकिस्तान मानो कंगाल बन गया हो। इतने दिन पाकिस्तान 500-1000 के नकली नोटों की मदद से कश्मीर के युवाओं को बहका कर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करवाया करता था। मगर मोदी सरकार ने नोटबंदी कर पाकिस्तान का यह रास्ता भी बंद कर दिया है। नोटबंदी के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में छापे गए अरबों-खरबों के 500-1000 के भारतीय नकली नोट रद्दी में बदल गए, बल्कि पाकिस्तान के पास अपने आतंकियों को पालने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं बची। पाकिस्तान आज अपनी ही लगाई आग में जल रहा है, मगर वह उन नासमझ देशों में है, जो खुद के घर में लगी आग की चिंता करने की जगह अपने पड़ोसी के घर को फूंकने की कोशिश अधिक करते हैं। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत के सामने खड़ा होने और टिके रहने की अब उसकी औकात नहीं रही। भारत की रक्षा तैयारियों के आगे पाकिस्तान नहीं टिकता। सिर्फ परमाणु संपन्न राष्ट्र होने का दंभ भरते हुए वह दुनिया को तबाह करने की धमकी देता रहता है। मगर भारत पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर यह साबित कर चुका है कि वह गीदड़ भभकी देने में नहीं कुछ कर गुजरने में अधिक विश्वास करता है। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए कि वह भारत जैसे शक्ति संपन्न पड़ोसी राष्ट्र के साथ मिल-जुलकर रहे। इसी में पाकिस्तान की भलाई है। पाकिस्तान यदि सचमुच फलना-फूलना चाहता है तो यह भारत के साथ दोस्ती के दम पर ही संभव है। 1

नमामी ब्रह्मपुत्र उत्सव, एक अर्थपूर्ण प्रयास

दुनिया भर की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही परवान चढ़ी हैं। जहां नदी का बहाव होता है, उसके आसपास जन-जीवन जरूर होता है। असम की ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के किनारे पनपने-परवान चढ़ाने वाली सभ्यता-परंपराएं भी सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। ब्रह्मपुत्र को असम की जीवन रेखा कहा जाता है, बिना ब्रह्मपुत्र के असमवासी अपने जिंदा रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। ठीक असम के बीच होकर बहने वाले ब्रह्मपुत्र के किनारे न जाने कितनी जाति-जनजातियों का इतिहास आज भी जिंदा है। कवियों की कल्पना में, लेखकों की लेखनी में, नाट्यकारों के नाटक और चित्रकारों की चित्रकला में ब्रह्मपुत्र के न जाने कितने ही रूप हैं। शांत ब्रह्मपुत्र जहां समृद्धि और विकास का संवाहक है, वहीं जब ब्रह्मपुत्र क्रोधित होता है तो अपने तेज बहाव में गांव के गांव को प्लावित कर देता है, अपने कटाव से बड़े-बड़े भूखंडों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। असमवासियों का पिता है ब्रह्मपुत्र। तभी तो यहां के लोगों को इसके गुस्से से भी लगाव है। असम के लोकगीत में ब्रह्मपुत्र का बखान, भूपेन दा के गीतों में इसका गुणगान आज भी लोगों केहृदय को स्पंदित करता है। धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया गया है। अशोकाष्टमी के दिन ब्रह्मपुत्र को पूजने का रिवाज रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि साल में बस 'अशोकाष्टमी' के दिन ही ब्रह्मपुत्र का जल गंगाजल से भी अधिक पवित्र रहता है। इतना पवित्र की मातृ-हत्या जैसे गंभीर पाप तक धुल जाते हैं।

राज्य सरकार के तत्वावधान में आयोजित पहले नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव का मकसद इन्हीं सब बातों को रेखांकित करने के साथ ही ब्रह्मपुत्र को पूरी दुनिया में महिमा-मंडित करना भी है। सच में यदि कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र के बारे में देश-दुनिया के लोगों को पूरी जानकारी तक नहीं है। हम असम सहित पूर्वोत्तर के लोग भी ब्रह्मपुत्र में छिपी संभावना और विकास के रास्तों के बारे में ठीक से नहीं जानते। इस आयोजन के माध्यम से देश-दुनिया के लोगों को

देश के सबसे बड़े नदी उत्सव में आमंत्रित किया गया है ताकि उन्हें ब्रह्मपुत्र और इसके दोनों किनारों पर बसे शहर-नगर में छिपी संभावनाओं के बारे में बताया-समझाया जा सके। सदिया से धुबड़ी तक ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित 21 जिलों में चार दिन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल इस उत्सव को एक अभिनव कदम के तौर पर देखने देखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने ब्रह्मपुत्र को महिमा मंडित कर उसके जरिए राज्य का विकास करने की बात सोची ही नहीं। इस आयोजन के माध्यम से हम देश-दुनिया को बताना चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र में आर्थिक विकास की कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। हम असमवासियों को समझाना चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र का विकास कर हम न सिर्फ बेशुमार नौकरियां पैदा कर सकते हैं, बल्कि अन्य प्रकार के रोजगार भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा-ब्रह्मपुत्र हमारी संस्कृति, सभ्यता, अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा सब कुछ है। ब्रह्मपुत्र से निकली उप नदियां हमारे राज्य को और अधिक समृद्ध करती हैं। ब्रह्मपुत्र न जाने कितने परिवारों का पेट पालता है। मछली पालन, नौका सेवा लोगों केलिए पुश्तैनी धंधा बना हुआ है।

परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी कहते हैं ब्रह्मपुत्र में अपार संभावाएं छिपी हुई हैं, बस उन संभावनाओं को तलाशने के लिए दृष्टि चाहिए। यही बात हमें देश-विदेश के निवेशकों को भी समझानी है। केंद्र सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की मदद से ब्रह्मपुत्र का विकास किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र को गहरा करने केलिए उसकी खुदाई कर उससे निकली मिट्टी से सदिया-धुबड़ी तक एक्सप्रेस हाईवे बनाने की सोच को इस विराट दर्शन से जोड़कर देखा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित कर अथवा ब्रह्मपुत्र पर बहुउद्देश्यीय बांध बनाकर राज्य-देश का भला क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

असम और पूर्वोत्तर दक्षिण एशिया का व्यावसायिक हब होने जा रहे हैं। दुनिया के निवेशकों को यहां निवेश करने का बेहतर विकल्प होगा। ऐसे में असम को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में महाबाहु ब्रह्मपुत्र एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। l

नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव, एक संभावना

नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव के उत्साह में प्रकृति ने खलल डालने की तमाम कोशिशें कीं। उत्सव के आयोजन के पहले दिन से समापन समारोह तक राज्य भर में तूफान-आंधी, बरसात-ओलावृष्टि का तांडव जारी रहा। इसके बावजूद गुवाहाटी सहित ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे राज्य के 21 जिलों में नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव सफल रहा। तूफान-बरसात की परवाह न करते हुए बड़ी भारी संख्या में लोग न सिर्फ उत्सव में पहुंचे, बल्कि अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाई। नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव की समाप्ति के बाद अब इसके उद्देश्य और सफलता की ईमानदारी के साथ समीक्षा की जानी चाहिए। इस आयोजन का प्रयोजन क्या था और इससे हमें हासिल क्या होने वाला है। इस पर पूरे राज्यवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार ने जनता को यह समझाने की कोशिश की कि बाढ़ और भू-कटाव का प्रमुख कारण समझा जाने वाला ब्रह्मपुत्र असम की समृद्धि के दरवाजे भी खोल सकता है। लोगों को समझाया गया कि ब्रह्मपुत्र का सद्पयोग कर राज्य में उद्योग-धंधे लगाए जा सकते हैं, बाहर से निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, रोजगार के अवसरों का सृजन कर बेरोजगारी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। दलील तो यह भी दी गई कि ब्रह्मपुत्र का समुचित प्रबंधन कर विकास के नए-नए रास्ते खोले जा सकते हैं। 40 हजार करोड़ रुपए की लागत में 841 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की खुदाई और इसके दोनों किनारों पर 1300 किलोमीटर के एक्सप्रेस हाईवे निर्माण के लिए असम सरकार, राष्ट्रीय जल परिवहन प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच हुए समझौते को नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव के तत्कालिक फायदे के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की खुदाई कर इसकी गहराई को बढ़ाने की परिकल्पना ही असम की समृद्धि का संकेत है। ब्रह्मपुत्र की गहराई बढ़ेगी तो इसकी जल भंडारण क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे बाढ़ का प्रकोप भी कम होगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर बनने वाले रास्ते न सिर्फ यातायात के नए युग का शुभारंभ करेंगे, बल्कि ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे

23 जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए बांध का भी काम करेंगे। इस कड़ी में हम धुबड़ी जिले के गौरीपुर का उदाहरण ले सकते हैं। गौरीपुर के किनारे से होकर गुजरने वाले 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को ऊंचा कर दिए जाने के बाद इस शहर पर गदाधर नदी की बाढ़ का कहर पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमारे राज्य में 1300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस हाईवे अपने आप में पहला एक्सप्रेस हाईवे होगा। यह हाईवे जिस शहर से होकर गुजरेगा, न सिर्फ उस शहर का विकास होगा, बल्कि वहां रोजगार-धंधे के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे।

ब्रह्मपुत्र पर छोटे-छोटे बहुमुखी बांध बनाकर बिजली उत्पादन करने के साथ ही सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के अलावा बाढ़-कटाव को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र यहां के भूमिपुत्रों के लिए मछली पालन का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की योजना के पूरा होने पर असम के विकास में भारी तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है। सर्वानंद सोनोवाल की सरकार यह बात स्थापित करने में लगी है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे सिर्फ असम की सभ्यता-संस्कार, परंपराएं ही परवान नहीं चढ़तीं, बल्कि ब्रह्मपुत्र को आधार बनाकर असम को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ किया जा सकता है। नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव के सफल आयोजन से न सिर्फ देश भर में, बल्कि दुनिया भर में एक सकारात्मक संदेश गया है। नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव में देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को जहां गंभीरता प्रदान की है, वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख तथा 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का काम किया है। इसकेअलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमिता राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, योग गुरु बाबा रामदेव जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव में शामिल होकर इसके राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करने का काम किया है। नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समक्ष ब्रह्मपुत्र से जुड़े उन सारे सपनों को पूरा करने की चुनौती होगी, जो सरकार ने राज्य की जनता को दिखाए हैं। l

लोक विश्वास-परंपराओं के बीच में बोहाग बिहू

विश्व भर में किसी-न-किसी नाम से लोक विश्वास अथवा पुरातन परंपरा केअनुसार कोई-न-कोई पर्व-उत्सव मनाने की परिपाटी सदियों से चलती आ रही है। ऐसे उत्सव के साथ कोई-न-कोई कहानी अथवा लोक विश्वास जरूर जुड़ा होता है। इसी के आधार पर उत्सव का रूपरंग, खानपान, पोशाक-परिधान, नृत्य-गीत आदि तय किए जाते हैं। विज्ञान की विकास यात्रा में शामिल रहने के बावजूद कोई भी लोक विश्वास को नकार नहीं सकता। भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण संस्कारों पर टिकी है, लिहाजा ऐसे उत्सव के साथ लोक विश्वास का जुड़ा रहना स्वाभाविक है। असमिया संस्कृति को प्रकाशमय करके रखने वाले बोहाग बिहू को लेकर भी कई लोक कथाएं-लोक विश्वास प्रचलित हैं। असम में कृषि आधारित उत्सव का शुभारंभ बोहाग बिहू अर्थात रंगाली बिहू से होता है और इसका समापन माघ बिहू अर्थात भोगाली बिहू से होता है। रंगाली-भोगाली बिहू उत्सव कृषि पर आधारित होने के कारण ही इनके साथ भूमि, अग्नि और गौ-पूजा जैसे पहलू जुड़े हैं। इन उत्सवों का स्वरूप असमिया जाति को एक सहज-सरल हृदयवाली जाति के रूप में स्थापित करता है।

हमारे देश में बिना गाय के कृषि कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से यदि देखा जाय तो देश की पूरी ग्रामीण आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था की धुरी ही गाय रही है। खेत में हल जोतने से लेकर फसल को ढोकर खेत से खलिहान तक ले जाने, घर की सफाई-पुताई करने, यहां तक की बच्चों के लिए दूध का प्रबंध करने तक में गाय ही सबसे आगे रहती है। इसलिए बोहाग बिहू का पहला दिन गोरू बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय-मवेशियों को नदी-पुखरी, खाल-बिल में नहलाने के बाद उनको दो विशेष

प्रकार के पेड़ के पत्तों से हल्के-हल्के ढंग से मारा जाता है। लोक विश्वास है कि ऐसे पत्तों से मवेशियों के शरीर पर मारने से मच्छर तथा अन्य पतंगे उनको नहीं काटते। बोहाग बिहू के मौके पर गांव के लोग तरह-तरह के पत्तेदार साग विशेष तौर पर खाते हैं। कहीं-कहीं तो सौ प्रकार के साग खाने का भी उल्लेख मिलता है। वैसे यह नहीं बताया गया है कि बोहाग बिहू पर किस प्रकार का साग खाना चाहिए। मगर आमतौर पर घर-गांव में जो साग उपलब्ध होता है, वहीं खाया जाता है।

इन सब लोक विश्वासों के बीच बोहाग बिहू एक नए स्वरूप में न सिर्फ असमवासियों के, बल्कि विश्ववासियों के सामने है। आज विश्व का कोई भी ऐसा देश बचा नहीं होगा, जहां एक भी असमिया प्रवासी न रहता हो और बोहाग बिहू न मनाया जाता हो। बदलते वक्त के साथ कृषि आधारित बोहाग बिहू ने भी अपना रूप-रंग बदला है। खेत-खलिहानों से निकलकर बिहू मंच तक पहुंच गया है। इस प्रक्रिया में कई दशक लगे हैं। अब बोहाग बिहू सिर्फ कृषि कार्य करने वालों तक ही सिमटकर नहीं रह गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही नहाने-खिलाने के लिए गाय न मिले, अमरीका में भले ही भारतीय गांवों में पाए जाने वाले साग के दर्शन न हों, इन सब के बावजूद वहां बोहाग बिहू जरूर मनाया जाता है। बोहाग बिहू में असम का बिहू नृत्य भी होता है, बिहू गीत और ढोल-पेपा भी। वक्त भले अपने सफर को तय करते-करते इस मुकाम तक पहुंच गया हो, मगर इस दौर में भी बोहाग बिहू ने अपना आकर्षण-गरिमा को नहीं खोया है। असमिया युवती-महिला चाहे वह किसी भी उम्र, परिवेश की क्यों न हो, अपने मेखला चादर को वर्षों तक इसलिए सहेजकर रखती है ताकि साल दर साल बोहाग बिहू में वह मेखला पहनकर ढोल-पेपा की धुन पर थिरक सके। बैशाख का महीना आते ही हमारे युवाओं में भी बोहागी का नशा सर चढ़कर बोलने लगा है। विभिन्न बिहू तोलियों में रात-रात भर चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपने चहेते गायक-गायिकाओं के गीतों पर थिरकती युवाओं की टोली को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है, बोहागी बिहू का आकर्षण कल भी था, आज भी है और आने वाले कल को भी रहेगा। l

उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के मायने

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों को 403 सीटों में से 325 सीटों पर हासिल जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अब भी बरकरार है। इन सीटों में से अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीती हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा की ऐसी ही आंधी देखने को मिली। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा केखाते में कुल 57 सीटें आईं। पंजाब को छोड़ गोवा और मणिपुर में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा और अन्य दलों के समर्थन पर वह इन दोनों राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। इस तरह मार्च 2017 में भाजपा शासित राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नाम भी जुड़ गए। मणिपुर में भाजपा को मिली कामयाबी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ ही पूर्वोत्तर केआठ में से तीन राज्यों में भाजपा

सत्ता में आ गई है। इन पांचों राज्यों के चुनावों में एक बात हर जगह समान रूप से उभरकर सामने आई कि मोदी मैजिक कहीं भी कम नहीं हुआ है। मतदाताओं ने मोदी के नाम पर दिल खोलकर वोट डाले, बिना इस बात पर विचार किए कि उनके वोट पर जीतने वाली भाजपा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा ने पांचों राज्यों में किसी को भी बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था और ये चुनाव एकमात्र मोदी के नाम पर लड़े गए। इन चुनावों में यदि भाजपा हारती तो चुनावी पंडितों द्वारा उसे मोदी की हार करार दिया जाता।

इन चुनावों में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हर एक राज्य में जाकर अपनी चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी के मुद्दे को जरूर उठाया। चुनावी पंडितों द्वारा यहां तक कहा गया कि ये चुनाव विमुद्रीकरण पर आधारित होंगे। लेकिन जनता ने भाजपा को विजयी बनाकर देश को यह भी स्पष्ट संकेत दे दिया कि वह भी मोदी की नोटबंदी के पक्ष में है। इस नोटबंदी से आम जनता को तकलीफ तो हुई, मगर उसे वहीं इस बात का संतोष भी था कि आखिरकर अमीरों से यह सवाल पूछने वाला कोई तो सामने आया कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए। वैसे तो यह चुनाव देश के पांच राज्यों में हुए, मगर देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव ही सुर्खियों में छाया रहा। चुनाव प्रचार के दौरान यहां कब्रिस्तान-श्मशान, दीपावली-ईद से लेकर गुजरात के गदहों तक पर सभी राजनीतिक दलों ने जमकर बयानबाजी की। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी सरकार की विकास से जुड़ी योजनाएं पसंद आईं। उन्होंने इन सभी मुद्दों को दरकिनार कर जन-धन बैंक खाते, तीन तलाक और उज्ज्वला योजना जैसी बातों को महत्व दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान, दलित, पिछड़े मतदाताओं ने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान कर अन्य राजनीतिक दलों को यह बात दो टूक शब्दों में समझा दी कि अब वे किसी भी पार्टी का वोटबैंक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। मुसलमान मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने करीब सौ मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत पक्की करने के लिए

कांग्रेस से दोस्ती करने के नाम पर सौ से अधिक सीटें उसकी झोली में डाल दी, मगर ये सारे गणित कोई कारनामा नहीं दिखा सके।

इन चुनावों ने एक तरह से यदि देखा जाए तो आने वाले दिनों की राजनीतिक तस्वीर सभी के सामने स्पष्ट कर दी है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी पार्टियां। इन चुनावों में भाजपा को मिली शानदार जीत से आने वाले दिनों में राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ेगी और कोई भी विधेयक वह अपनी वोट संख्या के दम पर पारित कराने की स्थिति में होगी। आज के दिन लोकसभा में भाजपा और उसके मित्र दलों का बहुमत तो है, लेकिन राज्यसभा में अब भी उनके सदस्यों की संख्या बहुमत से कम है। इन चुनावों से एक बात और साफ हो गई है कि अगली बार मायावती जैसी प्रखर नेता का राज्यसभा तक पहुंचने का मार्ग भी लगभग बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी पार्टी को न्यूनतम जितनी सीटों की जरूरत पड़ती है, बासपा के खाते में उतनी सीटें भी नहीं आई हैं। अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए रायबरेली, अमेठी जैसी अपनी परंपरागत सीटों को बचा पाना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। अब जबकि अगले लोकसभा चुनावों को करीब ढाई साल ही बचे रह गए हैं, विपक्षी पार्टियों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अभी से जनता के दरबार में जाकर हाजिरी लगानी शुरू कर देनी चाहिए। विपक्षी दलों को चाहिए कि वह अपनी गलतियों से सीख लें। लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बिना मजबूत सरकार और मजबूत विपक्ष के हम स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। ।

विद्यार्थियों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन

मैट्रिक अथवा हायर सेकेंडरी की परीक्षा के दिनों विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं ने समाज शास्त्रियों को चिंतित कर रखा है। समाज में इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले इन विद्यार्थियों के असमय दुनिया छोड़कर चले जाने की घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। ऐसे विद्यार्थियों के आत्महत्या से पूर्व लिखे गए पत्रों से कई बार यह बात सामने आई है कि पढ़ाई को बोझ अथवा परीक्षा में फेल हो जाने के डर की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विधानसभा में ऐसी आत्महत्याओं के लिए अयोग्य शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया था। डॉ. शर्मा ने विधानसभा में इस बात पर अफसोस व्यक्त किया था कि अयोग्य शिक्षकों की नौकरी नियमित (प्रादेशीकरण) किए जाने के हक में दलील देने वाले विधायक-मंत्री कभी उन बच्चों के हक में बोलते नजर नहीं आते, जो अयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने के कारण परीक्षा में फेल होने के डर से फंदे पर लटक जाते हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की योग्यता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भविष्य के आदर्श नागरिक और कौशलयुक्त मानव संपदा का सृजन करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का होना पहली शर्त होनी चाहिए।

बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति के लिए कई समाज शास्त्री अभिभावकों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इनकी दलील है कि अभिभावक बेहतर परीक्षाफल हासिल करने और कक्षा में अव्वल आने के नाम पर बच्चों पर इस कदर मानसिक दबाव डालते हैं कि उनका नतीजा आखिरकार बच्चे का फांसी के फंदे पर लटकना होता है। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि उम्मीद के अनुसार परीक्षाफल नहीं आने की शंका से ग्रसित होकर बच्चा आत्महत्या कर लेता है और बाद में उसका परीक्षाफल उम्मीद से भी बेहतर निकलता है। अभिभावकों को यह बात समझनी ही होगी कि उसका बच्चा बजाए पढ़ाई के किसी अन्य क्षेत्र में भी खास हो सकता है। अपने बच्चे को सबसे आगे की

पंक्ति में खड़ा करने के लिए अभिभावकों में होड़ लगी नजर आती है। स्कूल बसों में घर लौटते निढाल विद्यार्थियों को कभी-न-कभी हम सभी ने देखा होगा। बच्चे से उसका बचपन, उसकी मासूमियत छिनकर हम उसे अच्छा नागरिक, संवेदनशील इंसान कैसे बना सकते हैं। इम्तिहान का मतलब ही यदि दबाव रह गया है तो हमें ऐसी परीक्षा पद्धति को बदलने की मांग करनी चाहिए। बेहतर शिक्षा के नाम पर अपने ही जिगर के टुकड़े की जिंदगी से खिलवाड़ करने का यह सिलसिला बंद होना चाहिए।

परीक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा हो, किसी प्रकार का दबाव नहीं। यह बात शिक्षक-अभिभावकों को मिलकर अपने बच्चों को समझानी होगी। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं है कि प्रतियोगिता के इस दौड़ में बेहतर रिजल्ट और शानदार अंक हासिल करना जरूरी है, मगर यह जरूरत बच्चे की जान की कीमत से तो अधिक नहीं होनी चाहिए। हम यदि घर में बच्चे को उसके मनमाफिक माहौल दें तो सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि परीक्षा पूर्व आत्महत्या करने वाले अधिकतर युवा 16 अथवा उससे अधिक उम्र के होते हैं। अर्थात वह उम्र, जब उन्हें सबसे अधिक देखभाल, सुझाव-परामर्श की जरूरत होती है। इस उम्र के विद्यार्थी तो पढ़ाई के अलावा अन्य प्रकार की गतिविधियों में भी शामिल होना चाहते हैं, मगर जब उन्हें पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई वाले माहौल में धकेल दिया जाता है तो उनके मन में सिवाय छटपटाहट के कुछ नहीं रह जाता।

अब सफलता के मायने बदल रहे हैं और दुनिया भी बड़ी तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है। बच्चे को किसी सांचे में ढालने से पहले एक बार परख लें कि वह किस मिट्टी का बना है और आप उसे जिस सांचे में ढालना चाहते हैं, बच्चा उसमें फीट बैठता भी है या नहीं। अपने बच्चे के शौक, आदत, स्वभाव को भी अहमियत दें और हां, उसे सफलता हासिल करने या परीक्षा में सबसे अव्वल आने की अंधी दौड़ में तो हरगिज शामिल न होने दें। याद रखिए आपका प्यारा बेटा अथवा बेटी इस देश, राज्य और समाज की संपत्ति है, जिनसे पूरा देश समृद्ध होता है। l

समन्वय की प्रतीक है बटद्रवा-बरपेटा की होली

वैसे तो देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पूरे राज्य भर में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जिक्र जब बटद्रवा और बरपेटा की होली का आता है तो सभी केआंखों केसामने रंग भरे गुब्बारे और हवा में उड़ता गुलाबी अबीर तैरने लगता है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान बटद्रवा और धर्म प्रचार केप्रमुख केंद्र कहे जाने वाले बरपेटा में कई सदियों से होली मनाई जा रही है। हम यदि कहें कि होली के इस उत्सव में बटद्रवा और बरपेटा के लोगों के प्राण बसते हैं तो यह अतिरंजित नहीं होगा। बसंत ऋतु में मनाए जाने वाले रंगोत्सव की तैयारियां स्थानीय लोग महीने भर पहले से ही करने लगते हैं। बटद्रवा केनिवासी तो फाल्गुन का महीना आते ही इसकेरंग में रंग जाते हैं। रंगोत्सव का स्वागत करने के लिए श्रीमंत शंकरदेव द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मालूम हो कि श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान बटद्रवा राज्य में द्वितीय बैकुंठ के नाम से भी विख्यात है। बटद्रवा सत्र में भक्तगण होली केदो महीने पहले से पलाश के फूलों को सुखाना प्रारंभ कर देते हैं और पांच दिनों तक चलने वाले दौल उत्सव के आनंद की लहरों में सभी डूबने-उतरने लगते हैं। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों के लोग भी बटद्रवा पहुंचते हैं।

विभिन्न पुस्तकों में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा दौलोत्सव मनाने की जानकारी मिलती है। रामचरण ठाकुर की 'कथा गुरु चरित' में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 21 वर्ष की आयु में बसंतकालीन दौल उत्सव की शुरुआत करने का जिक्र मिलता है। 'कथा गुरु चरित' में उल्लेख किए गए अनुसार श्रीमंत शंकरदेव ने ऊंचे-ऊंचे दौल का निर्माण कराया था। माना जाता है कि शंकरदेव ने 19 वर्ष की उम्र में 'चिन्हयात्रा' की रचना कर उसमें अभिनय करने के बाद इस बसंतोत्सव की तैयारियां की थीं। क्योंकि इसके बाद ही बटद्रवा में दौल गृह का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों में यह बात प्रचलित है कि दौल गृह

के निर्माण के बाद श्रीमंत शंकरदेव के प्रिय शिष्य बलराम आता द्वारा मरुवापुर से फागु गुड़ी अथवा अबीर लाकर दौल को सजाया गया था। महापुरुष ने बटद्रवा में सबसे पहले दौल उत्सव का प्रारंभ किया था। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने शिष्यों के साथ दौल गृह के चारों ओर केले के पेड़ लगाकर होली गीत भी गाए थे। सन् 1570 में बटद्रवा सत्र में दौल उत्सव का शुभारंभ करने के बाद ही असम के विभिन्न स्थानों में इसका प्रचार-प्रसार किया गया। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्म प्रचार के दौरान भी दौल उत्सव को प्रचारित करने में मदद मिली। श्रीमंत शंकरदेव भागवत, पुराण, हरिवंश में वर्णित फाल्गुन उत्सव के बारे में पढ़ने के बाद ही इस बसंतकालीन उत्सव के बारे में जान पाए थे। बटद्रवा में दौल उत्सव के पहले दिन गंधोत्सव का पालन कर इस त्योहार का प्रारंभ किया जाता है। कीर्तन घर के दक्षिण में स्थित दौल मंदिर से गोविंद गोसाईं को संध्या के समय गायन-बायन के साथ थान के उत्तर दिशा में स्थित आकाशीगंगा के किनारे से एक अस्थायी घर में ले जाने की परंपरा आज भी कायम है। यहीं गोसाईं को रखकर मंत्र उच्चारण कर घर को जला डालने के बाद गोसाईं को लाकर बटद्रवा में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए तेल से नहला-धुलाकर उन्हें नव-वस्त्र पहनाए जाते हैं। दूसरा दिन 'गोसाईं के सिर पर अबीर चढ़ाने' के रूप में मनाया जाता है। तीसरे दिन गोसाईं की गायन-बायन के साथ दौल ले जाकर पूजा-अर्चना की जाती है।

दौल उत्सव के दौरान सत्र नगरी बरपेटा भी जीवांत हो उठती है। पूरा बरपेटा होली गीत से गूंज उठता है। सुबह से रात तक होली गीतों की तान सभी को भाव-विह्वल कर देती है और सत्रीय परंपरा दिल में खुशी की लहर पैदा कर देती है। श्रीकृष्ण के प्रेम में बावले सभी के मुंह से होली के गीत अपने आप फूटने लगते हैं। बरपेटा सत्र में मथुरादास बुढ़ा आता ने दौल उत्सव का शुभारंभ किया था। बरपेटा जिले में मनाई जाने वाली होली को स्थानीय भाषा में दौल उत्सव ही कहा जाता है। वैसे तो यह उत्सव पूरे राज्य भर में मनाया जाता है, मगर बरपेटा के दौल उत्सव की बात ही कुछ अलग है। यह दौल उत्सव अपने साथ समन्वय का पैगाम भी लेकर आता है, इसलिए इसे यदि समन्वय पर्व भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। l